RNI No. : MPHIN/2010/38129 MP/IDC/1375/2020-22 www.hariyalikeraste.com

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 12 » अक्टूबर 2020 » मूल्य : 40 रु. Email : hariyalikeraste2010@gmail.com

आत्मनिर्भर कृषि की राह पर देश

सबको साख-सबका विकास

सबको साख-सबका विकास

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने मुरैना में केसीसी वितरित किये।

जिला सहकारी बैंक गुना में विधायक गोपीलाल जाटव ने केसीसी बाँटे।

बैतूल में कलेक्टर श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में हितग्राहियों को केसीसी वितरित किये।

झाबुआ में कलेक्टर रोहित सिंह ने हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।

ग्वालियर में किसानों को केसीसी और ऋण वितरण किया गया।

खरगोन बैंक में पूर्व कृषि राज्यमंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार ने प्रमाण-पत्र सौंपे।

छिंदवाड़ा में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने राशि वितरित की।

छतरपुर में नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री प्रद्युम्नसिंह लोधी ने प्रमाण-पत्र बाँटे।

ANNIVERSARY 10 YEARS ANNIVERSARY

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 12 » अक्टूबर 2020 » मूल्य : 40 रु.

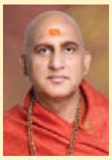

» विशेष संरक्षक : जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनन्त श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज
» संरक्षक : विष्णु नारायण त्रिपाठी
» प्रधान संपादक : बृजेश त्रिपाठी
» प्रबंध संपादक : अर्चना त्रिपाठी
» सलाहकार मंडल :
व्ही.जी. धर्माधिकारी (सेवानिवृत्त सचिव एवं आयुक्त सहकारिता)
एल.डी. पंडित (सहकारी विशेषज्ञ)
सुशील मिश्र (पूर्व अपर आयुक्त सहकारिता)
मणिशंकर उपाध्याय (कृषि विशेषज्ञ)
एम.एस. भटनागर (कृषि रत्न, बीज विशेषज्ञ, सलाहकार बीज संघ)
सुरेशचंद्र ताम्रकर (वरिष्ठ पत्रकार)
डॉ. आर.ए. शर्मा (पूर्व डीन, कृषि महाविद्यालय, इंदौर)
डॉ. वी.एन. श्रॉफ (कृषि वैज्ञानिक)
यशोवर्धन पाठक (व्याख्याता जबलपुर)
पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक' (अध्यक्ष, म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद)
डॉ. राजीव शर्मा (प्रोफेसर एवं कवि, इंदौर)
डॉ. भरत शर्मा (समाजसेवी)
हरप्रसाद मोदी (वरिष्ठ पत्रकार, झाँसी-ललितपुर)
अरुण के. बंसल (फ्यूचर पॉइंट प्रा.लि., नई दिल्ली)
पं. रतन वशिष्ठ (ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक)
लेफ्टिनेंट कर्नल अजय (वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य)
कैप्टन (डॉ.) लेखराज शर्मा (ज्योतिषाचार्य)
» विशेष संवाददाता
इंदौर-उज्जैन संभाग : परीक्षित शर्मा (मो. 7999692727)
भोपाल संभाग : आलोक मालवीय (मो. 9806750146)
होशंगाबाद संभाग : धनराज मालवीय (मो. 9827744248)
छत्तीसगढ़ (रायपुर) : पी.एल. चुरहे (मो. 7389652211)
» प्रकाशक : बृजेश त्रिपाठी
306/ए-ब्लॉक, शहनाई-।। रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 8989991569, 9752558186
» लेआउट-डिजाइन : नितिन पंजाबी (मो. 9893126800)
ई-मेल : nitinpunjabi5@gmail.com
» मुद्रक : वी.एम. ग्राफिक्स
के-29, एल.आय.जी. कॉलोनी, इंदौर

3 हम सब बापू की आवाज सुनें

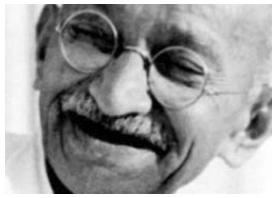

5 एक बड़े फैसले के अनेक पहलू

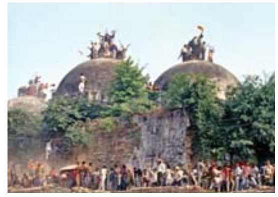

7 असली चिंता छोटे किसानों की

9 दशकों पीछे ले जाने वाला साल

14 राष्ट्रीय सहकारिता का विस्तार

16 गेहूँ उत्पादन की नई तकनीक

22 सबको साख सबका विकास कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रारंभ

60 आ गया 'मिर्जापुर-2' का जबर्दस्त ट्रेलर

किसानों को अब मिली सच्ची आजादी

देश को आजाद हुए भले ही 74 साल हो गए लेकिन अन्नदाता किसानों को अभी तक मंडी कानून की बेड़ियों ने जकड़ रखा था। वह अपनी उपज अपनी मर्जी से कहीं भी बेच नहीं सकता था। मंडियों में दलाल और बिचौलियों के चंगुल में किसान अब तक ठगा जाता था। चुनाव के समय लगभग सभी विपक्षी दल किसानों को उपज बिक्री की आजादी दिलाने के वादे बढ़-चढ़कर अपने घोषणा पत्रों में करते रहे लेकिन किसी ने भी इसे पूरा करने का साहस नहीं दिखाया। अब केंद्र की मोदी सरकार ने जब संसद में कृषि सुधार से संबंधित तीन विधेयक बहुमत से पारित कर दिए तो विपक्ष के पैरों तले से मानों जमीन ही खिसक गई। कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को आंदोलन के लिए भड़काया जा रहा है। पंजाब की देखादेखी हरियाणा के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। रेल पटरियों पर धरना दिया जा रहा है। ट्रेक्टरों को आग के हवाले किया जा रहा है। विरोधी दलों के बहकावे में आकर किसान स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर दी कि हम अपने राज्य में इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे। अन्य राज्यों से भी ऐसा करने की अपील की जा रही है। हमारे मुल्क में ऐसी ओछी राजनीति की वजह से देश की बहुत हानि होती है। पता नहीं हमारे नेताओं को कब सद्बुद्धि आएगी। किसानों को मुक्त व्यापार की आजादी मिलने से वे देश ही नहीं दुनिया के किसी भी बाजार में जहां उचित दाम मिले अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली और मंडी व्यवस्था भी यथावत जारी रहेगी। नए कानून में किसानों को केवल अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी दी गई है ताकि वे अधिकतम मूल्य पा सके। अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत अब किसान निर्यातकों और कारपोरेट व्यवसायियों के साथ समझौता कर सकेंगे। उन्हें उत्तम बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुगम होगी। अभी तक छोटे किसानों को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इससे किसानों का जोखिम कम होगा और खरीददार ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तीसरे कानून के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू प्याज जैसी वस्तुओं को स्टाक सीमा से मुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी परिस्थितियों को छोड़ ये वस्तुएं स्टाक सीमा से मुक्त रहेंगी। इससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को सही मूल्य मिलेगा। कुल मिलाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने की दिशा में ये नए कानून मील का पत्थर साबित होंगे। विपक्ष के विरोध और अदालत में चुनौती देने के इरादों के बावजूद केंद्र सरकार इन कानूनों पर अमल के लिए दृढ़ है। जब कोई भी बड़े बदलाव होते हैं तो उन्हें सहज रुप से स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन बदलाव भी जरूरी हैं। अगर अमल के बाद कोई कमी या खामी नजर आती है तो संसद में संशोधन लाकर उसमें सुधार भी तो किया जा सकता है। विरोध की खातिर विरोध करना कहां तक उचित है।

बृजेश त्रिपाठी

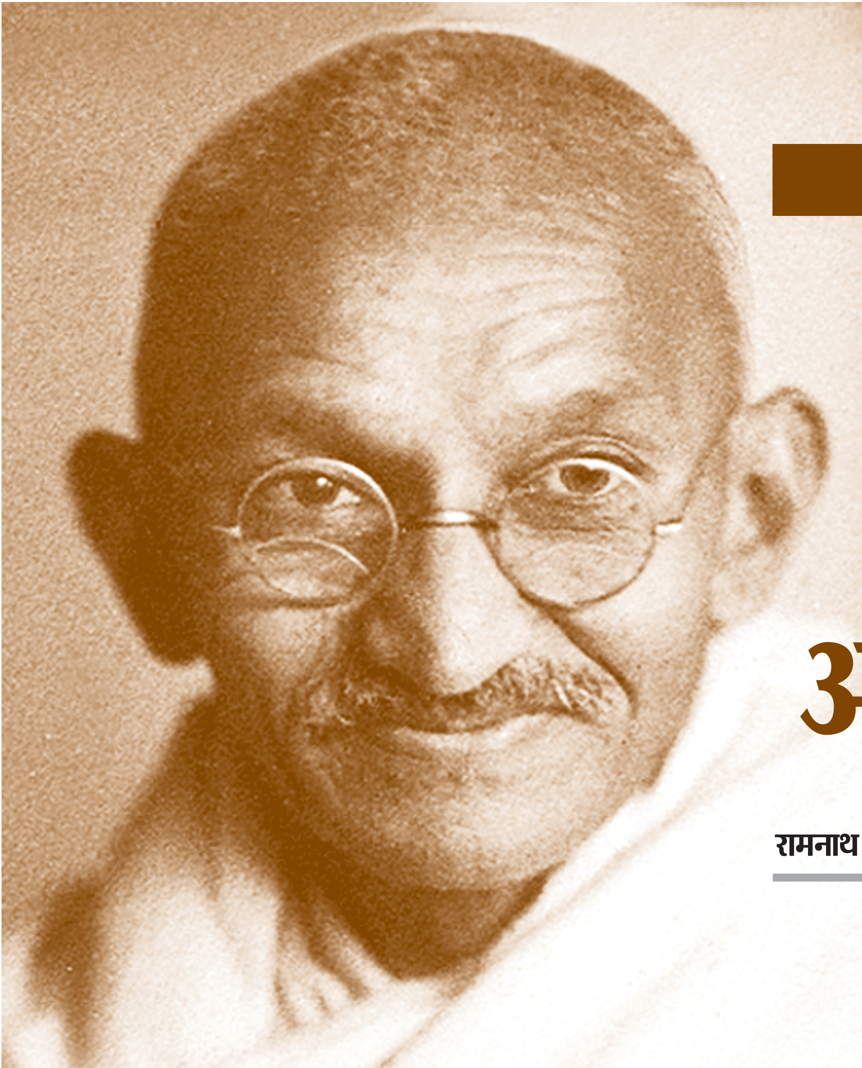

2 अक्टूबर : गाँधी जयंती

हम सब बापू की आवाज सुनें

रामनाथ कोविंद » *राष्ट्रपति, भारत*

असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के प्रति जन-चेतना जगाने के लिए प्रकाशित लेखों के कारण गांधीजी को 1922 में जेल में डाल दिया गया। उनके सहयोगी शंकरलाल बैंकर को भी साथ ही कारावास मिला था। बैंकर ने देखा कि महात्मा गांधी सवेरे चार बजे अपनी दिनचर्या शुरू करने से लेकर देर रात तक एक मिनट भी बरबाद नहीं करते हैं। रोज छह घंटे सूत कातने से लेकर नियमित तौर पर शास्त्रों के स्वाध्याय तक वह किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं। बैंकर भी उत्साहपूर्वक उनके साथ सक्रिय रहते। गांधीजी ने उनके लिए भी एक टाइम-टेबल बना दिया था। गांधीजी से पहले रिहा होते समय बैंकर ने उनसे कहा कि अब उन्हें जीने की नई राह मिल गई है। इस पर गांधीजी ने उनसे कहा, आप अपनी सीख दूसरों के साथ भी साझा करें।

फिर उन्होंने बैंकर से पूछा, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि ऐसी दिनचर्या के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? बैंकर को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। गांधीजी बोले, 'मैं आपको बता सकता हूं कि लोग क्या कहेंगे। वे कहेंगे, वह तो महात्मा हैं, वह ऐसी जीवन-शैली अपना सकते हैं। ऐसा कर पाना हमारे लिए संभव नहीं।' गांधीजी ने बैंकर से लोगों को यह बताने के लिए कहा कि वह कोई जन्मजात महात्मा नहीं हैं। उनके शब्द थे, 'मुझमें भी बहुत से दोष थे और मैंने उन्हें दूर करने के लिए सजगता के साथ अथक प्रयास किए हैं। अब लोग मुझे महात्मा कहने लगे हैं, हालांकि मैं उस अवस्था से बहुत दूर हूं। लेकिन यह मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति इस राह पर चल सकता है, यदि वह इस पर मनन करे और आत्मविश्वास तथा प्रतिबद्धता के साथ सही दिशा में प्रगति करे।'

गांधीजी की 151वीं जयंती के अवसर पर मैं उनकी सीख के बारे में चिंतन करता हूं, तो यह पाता हूं कि उनकी यह शिक्षा हमें सशक्त भी बनाती है और विनम्र भी। बापू ने अपनी ओर से कभी अपने महात्मा होने का दावा नहीं किया। सच तो यह है कि वह अपनी दुर्बलताओं को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर भी, उन्हें मानवीय क्षमता के उच्चतम शिखर तक पहुंचने का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। हम सबको उनकी उपलब्धियां अलौकिक सी लगती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बापू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए जो कहा था, वह सर्वथा सत्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सचमुच यह विश्वास करना कठिन होगा कि उन्मुक्त मुस्कान वाले एक कृशकाय वृद्ध ने बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के आजादी की लड़ाई में विजय का मार्ग प्रशस्त किया।

बापू ने स्वयं बताया है कि वह एक सामान्य बालक थे, जिसकी अपनी कमजोरियां थीं। अंतर बस इतना था कि उन्होंने

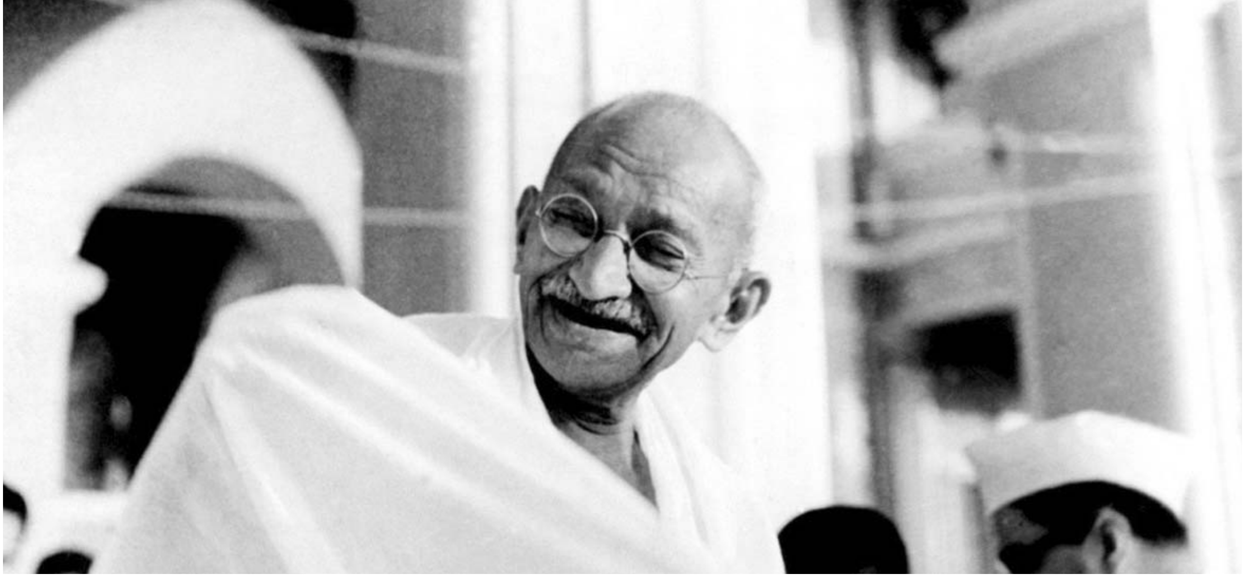

अपनी नैतिकता की नींव को मजबूत बनाने पर पूरी लगन से काम किया। युवावस्था में वह स्वभाव से शर्मीले थे और उनमें आत्म-विश्वास की कमी थी। लेकिन वह अपनी नैतिकतापूर्ण सोच को निरंतर सुदृढ़ बनाते रहे। एक बेहतर इंसान बनने और अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के अहर्निश प्रयास ने उन्हें महात्मा बना दिया। मार्ग कठिन था, कई विफलताओं से भी उन्हें गुजरना पड़ा। लेकिन बिना हिम्मत हारे, वह अपने कदम आगे बढ़ाते गए।

अपनी आत्मकथा में बापू ने लिखा है, 'मुझे जो करना है, तीस वर्षों से मैं जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हुए हूं, वह आत्म-दर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है।' उनका प्रयास इस अर्थ में अनूठा था कि उन्होंने संसार का त्याग नहीं किया, बल्कि निर्बलों के उत्थान और सभी देशवासियों के सशक्तीकरण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधीजी अधिकारों की तुलना में अपने कर्तव्यों के बारे में अधिक सचेत थे और दूसरों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। इनमें हरिजन, किसान, मजदूर, महिलाएं और अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने करुणा पर आधारित एक अलग तरह की राजनीति विकसित की, जिसमें समकालीन विश्व के सभी अहम सवालों के जवाब निहित हैं। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए व्यक्ति, संगठन और राष्ट्र को क्या करने की जरूरत है, यह गांधीजी बड़े विस्तार से बताते हैं।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए व्यक्ति , संगठन और राष्ट्र को क्या करने की जरूरत है, यह गांधीजी बड़े विस्तार से बताते हैं।

बड़े-बड़े कार्य करते हुए भी गांधीजी सदैव विनम्र बने रहते। उनके सहयोगी और अनुयायी उनमें एक पिता का नहीं, बल्कि एक मां का रूप देखते थे। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि किसी स्थान से गांधीजी के जाने के बाद भी वहां के वातावरण में एक सात्विक सुगंध बनी रहती है। अंग्रेजी के उस लेखक के आशय का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे तीन साल पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान हुआ। आश्रम की पवित्रता अब भी अक्षुण्ण बनी हुई है और आज भी वहां उसी गहरी शांति का अनुभव होता है, जो गांधीजी के सान्निध्य में उस परिसर में व्याप्त रहती थी। दिल्ली में राजघाट पर जब-जब मैं उनकी समाधि पर गया हूं, मैंने वहां शांति का वैसा ही स्पंदन अनुभव किया है।

गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष-पर्यंत मनाए गए समारोह आज संपन्न हो रहे हैं। इन समारोहों ने लोगों को गांधीजी की स्मृति को नमन करने और सार्वजनिक जीवन की नैतिक आधारशिला को मजबूत बनाने के अवसर प्रदान किए हैं। बीते वर्ष में भारत और अन्य देशों के अनेक युवाओं को गांधीजी के अमर संदेश से परिचित होने का अवसर अवश्य मिला होगा। यदि हम उनके जीवन से सबक लेना चाहें, तो गांधीजी के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, खासकर आज की स्थिति में, जब हम एक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने सेवा और स्वच्छता के काम में खुद को झोंक दिया था और निःस्वार्थ सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया था।

जनवरी 1934 में आलप्पुझा में एक भाषण में उन्होंने कहा था, 'मुझे अपने जीवन-लक्ष्य में इतनी गहरी आस्था है कि यदि उसकी प्राप्ति में सफलता मिलती है, और मिलना अवश्यंभावी है, तो इतिहास में यह बात दर्ज होगी कि यह आंदोलन विश्व के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए था, जो एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक समष्टि के अंग होंगे।' मुझे विश्वास है कि उसी आस्था और सोच को जागृत रखते हुए हम एक बेहतर विश्व की परिकल्पना और निर्माण करने में सक्षम होंगे। गांधीजी की 151वीं जयंती, उनके जीवन और चिंतन के आलोक में अपनी प्राथमिकताएं तय करने और अपने हृदय की गहराई से उनकी आवाज को फिर से सुनने का एक पुनीत अवसर है। ■

एक बड़े फैसले के अनेक पहलू

प्रांशु अग्रवाल » *वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ*

फैसला नया है, लेकिन कई जरूरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं।16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर के दौर में बनी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर, 1992 को ढहाने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। तब इस घटना के संबंध में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थीं। पहली रिपोर्ट में कारसेवकों को आरोपी बनाया गया था। दूसरी रिपोर्ट में रामकथा पार्क मंच से भाषण दे रहे भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया नामजद किए गए थे।

6 दिसंबर, 1992 की घटना से पहले अक्तूबर 1990 में हजारों रामभक्तों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नीतियों के विरोध में अयोध्या में घुसकर विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया था। इस पर तत्कालीन राज्य सरकार ने कारसेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। इस कार्रवाई के विरुद्ध काफी विरोध प्रदर्शन होने पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

दो साल बाद 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। एक अस्थाई श्रीराम मंदिर का निर्माण किया गया। 16 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए एमएस लिब्रहान आयोग का गठन हुआ। रामलला की दैनिक सेवा पूजा की अनुमति दिए जाने के संबंध में अधिवक्ता हरिशंकर जैन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई, जिसमें 1 जनवरी, 1993 को रामलला की दैनिक सेवा पूजा की अनुमति प्राप्त हुई। तब से वहां दर्शन-पूजन का क्रम निर्बाध रूप से जारी रहा है। तत्कालीन नरसिंह राव सरकार रामलला की सुरक्षा के लिए लगभग 67 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने के संबंध में एक अध्यादेश लेकर आई, जिसे संसद ने 7 जनवरी,1993 को कानून के रूप में मान्यता दे दी।

इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आया, वर्ष 1993 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न किया कि क्या जिस स्थान पर ढांचा खड़ा था, वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई मंदिर या धार्मिक इमारत थी? इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ में दो न्यायाधीशों ने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर तो तभी दिया जा सकता है, जब पुरातत्व विभाग एवं इतिहासकारों के विशिष्ट साक्ष्य

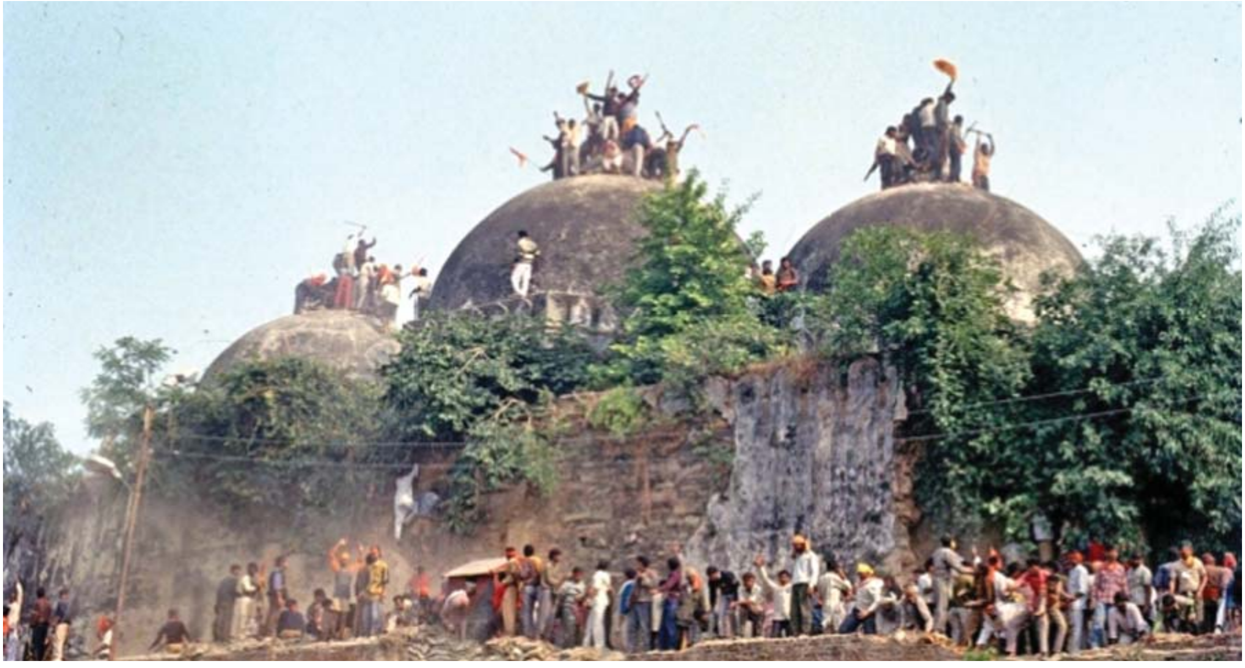

सभी को बाबरी विध्वंस मामले पर फैसले का इंतजार था और सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 32 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

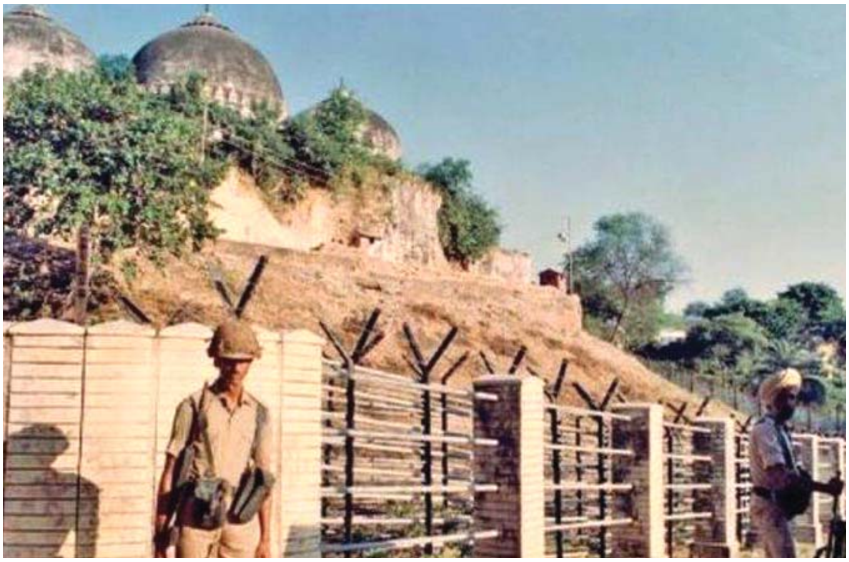

उपलब्ध हों। इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। जवाब में तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल ने 14 सितंबर,1994 को अदालत में अयोध्या मसले पर सरकार का नजरिया रखा था कि सरकार धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मावलंबियों के साथ समान व्यवहार की नीति पर कायम है। अयोध्या में जमीन अधिग्रहण कानून 1993 और राष्टपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया प्रश्न भारतीय नागरिकों में भाईचारा बनाए रखने के लिए है।

24 अक्तूबर, 1994 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ विवादित स्थल के स्वामित्व का निर्णय करेगी और राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देगी। तीन न्यायमूर्तियों की लखनऊ खंडपीठ की पूर्ण पीठ ने वर्ष 1995 में मामले की सुनवाई शरू की। लखनऊ खंडपीठ ने सही तथ्यों का पता लगाने के लिए विवादित स्थल की खुदाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी कहा कि खुदाई में पूरी पारदर्शिता और दोनों समुदायों की मौजूदगी व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

जनवरी 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग गठित किया गया, जिसका काम राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों संप्रदायों से बातचीत करना था। वर्ष 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद नवंबर 2019 में अदालत ने विवादित स्थल के स्वामित्व का फैसला सुना दिया था और अब अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर एवं मस्जिद का निर्माण जारी है।

इसके बाद सभी को बाबरी विध्वंस मामले पर फैसले का इंतजार था और सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 32 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। 28 साल बाद हिन्दुस्तान के एक सबसे बड़े मुकदमे का न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय हुआ है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि जितने भी वीडियो कैसेट और फुटेज सीबीआई ने विवेचना के दौरान दिए, वे सीलबंद अवस्था में नहीं थे। किसी भी वीडियो कैसेट और फुटेज को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर यह जांच नहीं कराई गई कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अस्तित्व में आने के बाद 17 अक्तूबर, 2000 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-3 में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भी अब साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है, लेकिन विध्वंस से जुड़े फोटो के नेगेटिव साक्ष्य में दाखिल नहीं किए गए थे। इसके कारण ये फोटो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत साक्ष्य के रूप में नहीं माने गए। इसके अलावा, विशेष अदालत ने यह भी कहा कि समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में छपी खबरें मात्र अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आती हैं, जिनके आधार पर दोष सिद्ध करना विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता।

यह गौर करने वाली बात है कि बाबरी मस्जिद को ढहाने की किसी पूर्व नियोजित योजना को अभियोजन पक्ष न्यायालय में साबित नहीं कर सका। सर्वोच्च न्यायालय पहले कह चुका है कि संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। साथ ही, आपराधिक षड्यंत्र का भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। जाहिर है, न्यायालय के निर्णय से सभी पक्षकार संतुष्ट हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के विरोधाभासी हित होते हैं। अब इस मामले में सीबीआई अगर महसूस करती है कि पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों द्वारा अपराध किया जाना साबित हो रहा था, तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। ■

नए कृषि विधेयक

असली चिंता छोटे किसानों की

वाई.के. अलघ » *पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कुलपति गुजरात वि.वि.*

संसद ने खेती-किसानी से जुड़े तीन अहम विधेयक पारित किए हैं। इनमें पहला विधेयक है, 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन व सरलीकरण) विधेयक', जो किसानों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी फसल मर्जी की जगह पर बेच सकते हैं। उन्हें फसलों की बिक्री पर कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। दूसरा है, 'कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक।' इसमें वायदा खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और तीसरा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन विधेयक, जिसके तहत खाद्य तेल, दाल, आलू, प्याज जैसे कृषि उत्पादों की भंडारण-सीमा से जुड़ी शर्तें समाप्त कर दी गई हैं। अब अति-आवश्यक होने पर ही इन उत्पादों का स्टॉक किया जा सकेगा। इन तीनों विधेयकों को सरकार ने ऐतिहासिक और किसानों के हित में बताया है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों के किसान इनका विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध का कारण समझने के लिए हमें सबसे पहले देश की कृषि-व्यवस्था पर गौर करना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था जब-जब मुश्किलों में फंसी है, कृषि क्षेत्र ने ही उसे मूलतः खाद-पानी दिया है। आज जब हमें कोरोना के साथ जीने के बारे में सिखाया जा रहा है, 'न्यू नॉर्मल' की बातें की जा रही हैं, तब खेती-किसानी को भी इसी रूप में ढालने की जरूरत है।

जब मानसून अच्छा रहता है, तो अपने यहां खरीफ की बुआई खूब होती है। सरकारी नीतियां भी इनमें सहायक होती हैं, लेकिन चुनौती यह है कि कृषि उपज को किस तरह बढ़ाया जाए और इसे कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि अर्थव्यवस्था में होने वाली गिरावट की भरपाई इससे अधिकाधिक हो सके। सरकारों का ज्यादा ध्यान मूल्य समर्थन नीति पर रहता है, लिहाजा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। यह व्यवस्था उत्तर-पश्चिम के किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन शेष भारत के किसानों को इससे शायद ही फायदा मिलता है। सरकारी खरीद संबंधी मूल्य उनके लिए अब तक अप्रासंगिक रहे हैं। भारत में कृषि

बाजार का दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, लेकिन यह तंत्र तब महत्वहीन हो जाता है, जब इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। यही वजह है कि अपने यहां कृषि उत्पादों का अधिकतर कारोबार मंडी के बाहर होता है, क्योंकि मंडी में सुविधाओं का अकाल है। इसलिए हमें सर्वप्रथम कृषि प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे (आपूर्ति शृंखला) और बाजार की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था जब-जब मुश्किलों में फंसी है, कृषि क्षेत्र ने ही उसे मूलतः खाद-पानी दिया है। आज जब हमें कोरोना के साथ जीने के बारे में सिखाया जा रहा है, 'न्यू नॉर्मल' की बातें की जा रही हैं, तब खेती-किसानी को भी इसी रूप में ढालने की जरूरत है। व्यापार और परिवहन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, तो आवागमन ठप हो गया, और किसानों को जहां-तहां अपनी फसलों का भंडारण करना पड़ा है। रेलवे अब तक सुचारू रूप से अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर सका है, जबकि कई कृषि व्यापार में परिवहन के तौर पर

सरकार किसानों को ऑनलाइन व्यापार करने की सलाह दे रही है, लेकिन इसके लिए पहचान पत्र की जरूरत होती है, जो ज्यादातर छोटे किसानों के पास शायद ही हो। लिहाजा, इन सभी चुनौतियों पर गंभीर बहस की जरूरत है।

रेलवे का ही इस्तेमाल किया जाता है। नासिक-मुंबई या अहमदाबाद-सूरत-वलसाड की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले दैनिक यात्री न जाने कितने दूधवाले और सब्जी-फलवालों से परिचित हो चुके होंगे। सोचिए, ऐसे किसानों की हालत इन महीनों में क्या हुई होगी? जाहिर है, हमें अब बदली हुई स्थितियों के अनुरूप कृषि नीतियां बनानी होंगी।

बहरहाल, नए विधेयकों का विरोध कर रहे लोगों का एक तर्क यह है कि इससे छोटी जोत के किसानों को नुकसान होगा और पूरा फायदा बड़े किसान और कारोबारियों के हिस्से में चला जाएगा। निश्चय ही किसान अपनी फसल को बेचने के लिए लंबा रास्ता तय करते हैं। छोटे गांवों के किसान बड़े गांव में जाते हैं और फिर वहां से उनकी उपज शहरों में पहुंचती है। कई राज्यों में दस लाख से भी अधिक किसान शहरों का रुख करते हैं। मगर बाजार का जो ढांचा अपने देश में है, उसमें उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि खेती-किसानी में आमदनी की किसानों की क्षमता कम होती जाती है। बेशक सरकारें कई तरह की सहायता और कर्ज-योजनाएं लाती हैं, लेकिन जब तक उन बुनियादी मुश्किलों को दूर नहीं कर लिया जाता, जो किसान पहले से झेलते आ रहे हैं, तब तक इन योजनाओं का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता।

साफ है, छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की बुनियादी समस्याओं का समाधान पहले होना चाहिए, उसके बाद नीतियां बननी चाहिए। एक उदाहरण, गुजरात में सरदार सरोवर का पानी अब किसानों के लिए मुश्किल का कारण बन चला है। यहां के पानी को 2002 में मुख्य नहर में मोड़ दिया गया था। नतीजतन, पिछले सप्ताह हर छह में से एक किसान को पानी नहीं मिला।

लिहाजा, हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि छोटे, मध्यम और बड़े गांव शहरों से सीधे जुड़ सकें। यह जुड़ाव सिर्फ आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बाजार, बिजली आदि) से नहीं हो, बल्कि यह सामाजिक स्तर पर भी दिखना चाहिए। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि शहरों में रहने वाले लोगों की आय बढ़े। किसानों की आमदनी किस तरह से बढ़े, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।

इन सभी चुनौतियों को देखकर यह लगता है कि संसद से पारित इन विधेयकों का दीर्घकालिक लक्ष्य तो अच्छा है और ये अच्छे इरादे से प्रेरित हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अपने देश में मंडी से इतर कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के कई बाजार हैं। मगर किसानों के पास खाद्य प्रसंस्करण, प्रथम चरण के बुनियादी ढांचे और इससे संबंधित सुविधाएं नहीं हैं। सरकार किसानों को ऑनलाइन व्यापार करने की सलाह दे रही है, लेकिन इसके लिए पहचान पत्र की जरूरत होती है, जो ज्यादातर छोटे किसानों के पास शायद ही हो। लिहाजा, इन सभी चुनौतियों पर गंभीर बहस की जरूरत है। तभी शायद ज्यादा सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। ■

कोरोना कहर

दशकों पीछे ले जाने वाला साल

निकोलस क्रिस्टॉफ » *स्तंभकार, न्यूयॉर्क टाइम्स*

भले ही हम सोचते हैं कि कोविड-19 मुख्य रूप से दुनिया में बुजुर्गों को ही निशाना बना रहा है, परंतु गरीब देशों में इसका असर उससे भी अधिक प्रलयंकारी है। इसके कारण बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। बच्चों खासतौर से बालिकाओं की पढ़ाई छूट रही है और वे बाल विवाह का दंश झेलने को मजबूर हैं। यह मातृ मृत्यु दर बढ़ने की वजह बन रहा है। इसने पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ मुहिम को कमजोर कर दिया है। इससे विटामिन ए वितरण की राह में भी अवरोध पैदा हो गए हैं, जिसके कारण और ज्यादा बच्चे दृष्टिबाधा का शिकार होंगे और मौत के आगोश में चले जाएंगे। यूएन पॉपुलेशन फंड की चेतावनी है कि कोविड-19 के कारण दुनिया भर में 1.3 करोड़ और अधिक बाल विवाह होंगे, जबकि लगभग 4.7 करोड़ महिलाओं को गर्भनिरोध के आधुनिक साधन नहीं मिल पाएंगे। कुल मिलाकर कोरोना महामारी के बाद बीमारियों, निरक्षरता और भयावह गरीबी की आपदा दस्तक देने वाली है और बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार होंगे। कोविड-19 का दुष्प्रभाव केवल उन पर ही नहीं होगा जो इसके संक्रमण की चपेट में आए, बल्कि उन विकासशील देशों के लोगों पर भी होगा, जिनकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा इस आपदा ने हिलाकर रख दिया है। यह इससे देखा जा सकता है कि तमाम क्लिनिक बंद हैं। एड्स सहित तमाम बीमारियों में काम आने वाली दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। मलेरिया और जननांगों को विकृत करने के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम थम गई है। बांग्लादेशी एनजीओ बीआरएसी के कार्यकारी निदेशक डॉ. मुहम्मद मूसा ने मुझे बताया कि कोविड-19 का प्रत्यक्ष प्रभाव तो संक्रमितों और उनके परिवारों पर ही असर दिखाएगा, लेकिन परोक्ष प्रभाव के चलते नौकरियां जाएंगी, भुखमरी और घरेलू हिंसा बढ़ेगी और तमाम बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी।

कोविड-19 का प्रत्यक्ष प्रभाव तो सं मितों और उनके परिवारों पर ही असर दिखाएगा, लेकिन परोक्ष प्रभाव के चलते नौकरियां जाएंगी, भुखमरी और घरेलू हिंसा बढ़ेगी और तमाम बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी।

आशंका है कि कोरोना से उत्पन्न गतिरोध के कारण करीब आठ करोड़ बच्चे खसरा रोधी वैक्सीन से वंचित रह जाएंगे। यदि वे खसरा से बच भी गए तो कुपोषण से उनकी जान पर आफत आ जाएगी। सबसे अधिक तपिश लड़कियों को झेलनी पड़ेगी। उनमें से तमाम का बाल विवाह करा दिया जाएगा, ताकि नए घर में उनके खान-पान और रहन-सहन की व्यवस्था हो सके या फिर वे मामूली सी तनख्वाह और महज खाने-पीने के एवज में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के लिए शहरों का रुख करेंगी। इससे न केवल उनकी

संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाले मार्क लॉक्कुक का कहना है, 'अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं और आपसे कह दिया जाए कि कल से काम पर नहीं आना तो अगले दिन आपको खाने-पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। मेरा मानना है कि दुनिया में गरीबी, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी इजाफा होने जा रहा है।'

पढ़ाई-लिखाई थम जाएगी, बल्कि उनके शोषण की आशंका भी बढ़ेगी। विकासशील देशों में बालिका शिक्षा को समर्थन देने की दिशा में लगी संस्था कैमफेड इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक एंजेलिना मुरिमीरवा का कहना है, विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या भुखमरी की है। मलावी में कैमफेड के 60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने भोजन की कमी की बात कही है। कोरोना संकट से पहले ही जिंबाब्वे में चार प्रतिशत लड़कियों की शादी 14 साल से पहले हो रही थी। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़कर बदतर तस्वीर पेश कर सकता है। कुछ साल पहले मैंने एक प्रतिभाशाली केन्याई लड़की की दर्दनाक दास्तान सुनी थी। उसका सवाल था कि क्या आर्थिक तंगी के अभाव में उसे अपने सपनों को ताक पर रखकर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या उस व्यक्ति से यौन संबंधों का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, जो उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार है? उसे डर था कि वह व्यक्ति एचआइवी से ग्रस्त हो सकता है। अब तमाम लड़कियों को ऐसी अनहोनी वाले विकल्पों से जूझना होगा।

लॉकडाउन और आर्थिक गिरावट से जुड़ी इस आपदा ने विदेशों से आने वाले धन यानी रेमिटेंस को भी प्रभावित किया है। बीएआरसी के अनुसार लाइबेरिया, नेपाल, फिलीपींस और सिएरा लियोन में काम करने वाले उसके दो तिहाई लोगों का कहना है कि आमदनी में भारी कमी आई है या वह बिल्कुल ही खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाले मार्क लॉक्कुक का कहना है, 'अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं और आपसे कह दिया जाए कि कल से काम पर नहीं आना तो अगले दिन आपको खाने-पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। मेरा मानना है कि दुनिया में गरीबी, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी इजाफा होने जा रहा है।'

बिल गेट्स और तमाम अन्य हस्तियां अमेरिकी कांग्रेस से अपील कर रही हैं कि वह अगले प्रोत्साहन पैकेज में चार अरब डॉलर की राशि इसी मद में जोड़ें, ताकि दुनिया भर में सभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिल सके। उनके अनुसार, इसे चैरिटी न समझा जाए क्योंकि यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक निवेश ही होगा। साथ ही हमें शिक्षा, पोलियो और पोषण जैसी मुहिम के लिए भी आकस्मिक निवेश की दरकार होगी। हालांकि अभी तक अमीर देश अपने तक ही उलझे रहे हैं। उन्होंने संकीर्ण सोच ही दर्शाई है। वे इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं कि दूर-दराज में फैला संक्रमण एक बार फिर उनकी देहरी पर दस्तक दे सकता है। कोविड-19 से लड़ने में 10 अरब डॉलर जुटाने की संयुक्त राष्ट्र की अपील पर केवल एक चौथाई राशि ही इकट्ठा हो पाई है।

आधुनिक दौर में मानवता की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि 1990 के दशक के बाद से भयावह गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर दो-तिहाई निर्धन आबादी को निर्धनता की जद से बाहर निकाला गया। अफसोस की बात है कि अब यह चक्र पलट रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन के आकलन के अनुसार कोविड-19 आपदा की दस्तक के साथ ही दुनिया भर में अत्यधिक गरीबों की तादाद में 3.7 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है। अगले साल तक इसमें और 2.5 करोड़ का इजाफा हो सकता है। हर साल के अंत में मैं एक स्तंभ इसी पर लिखता हूं कि बच्चों के भविष्य और साक्षरता जैसे तमाम पैमानों पर गुजरा साल मानवता के इतिहास में सबसे बेहतरीन रहा, परंतु इस साल या आने वाले कई वर्षों तक संभवतः ऐसा आलेख लिखना संभव न हो। मैंने लॉक्कुक से पूछा कि क्या कोविड-19 प्रगति के उस दौर के लिए एक झटका है या फिर उस पर विराम? उन्होंने यही जवाब दिया कि यह एक बहुत बड़ा झटका है, परंतु यदि हम सतर्क नहीं रहे तो यह एक झटके से भी भयानक साबित होगा। यह बीते कुछ दशकों के दौरान हासिल हुई तरक्की को कई दशक पीछे ले जाएगा। ■

अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर कृषि की राह पर देश

राजनाथ सिंह » *रक्षामंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय कृषिमंत्री*

कृषि से जुड़े दो ऐतिहासिक विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के साथ ही हमने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। हमने किसानों को उद्यमी बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक जरूरी कदम बढ़ाया है। इससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर कृषि की राह भी खुलेगी। यह बीते छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में सरकार के दृढ़ संकल्प एवं समर्पण का परिणाम है। इन दोनों विधेयकों का पारित होना भारतीय कृषि के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारतीय कृषि की वास्तविक संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी के विजन की सराहना करता हूं। साथ ही संसद में इन दोनों विधेयकों के पहलुओं को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी बधाई देता हूं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने किसान और कृषि हित में तमाम साहसिक फैसले किए हैं। इनके तहत 6,685 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 एफपीओ यानी किसान उत्पाद संगठन का गठन किया जाएगा। ये एफपीओ किसानों को स्वयं-सक्षम समूहों में तब्दील करेंगे। इससे किसानों की बाजार, वित्त और उत्पादन तकनीकों तक पहुंच बेहतर होगी। इसी तरह एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाला कृषि अवसंरचना कोष सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और कटाई के बाद प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य है कि 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक कर दिया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिये किसानों को 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। किसानों को आजीविका की सुरक्षा देने में इसने अहम भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार अधिनियम, 2020 को आगे बढ़ाया गया है। इससे न केवल किसानों को मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ता, थोक विक्रेता से लेकर उद्यमियों को भी लाभ पहुंचेगा।

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नए कृषि सुधारों से किसानों की जमीन कंपनियों की भेंट चढ़ जाएगी। मैं ऐसे सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है।

बाजार सुधार कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। नए बाजार सुधारों के साथ हम मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखेंगे। यह सहयोगी क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करेगा।

हमने इन अधिनियमों में कुछ ऐसे कड़े प्रावधान किए हैं, जिससे किसानों के हित सुरक्षित रहें। एफपीओ किसानों की ही एक संस्था है। यह किसानों को मोलभाव की ताकत देगी। सह्याद्रि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भारत में कृषक उत्पादन संगठन की सबसे उम्दा मिसाल है। इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन आज यह अंगूर और कई अन्य फसलों के निर्यात के मामले में अग्रणी है। करीब 8,000 सीमांत किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हर सीजन में 16,000 टन से अधिक अंगूर निर्यात करते हैं। इससे किसानों को एफएमसीजी कंपनियों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है। लोग पूछते हैं कि देश भर में सह्याद्रि जैसी सैकड़ों संस्थाएं क्यों नहीं हैं? इसका जवाब वह प्रतिबंधात्मक ढांचा है, जिसने कृषि में निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया। सुधारों के दम पर हमारे पास सफलता की ऐसी हजारों कहानियां होंगी। अध्यादेश जारी होने के बाद बीते तीन-चार महीनों के रुझान तो शुरुआत भर हैं। बाजार के साथ बेहतर जुड़ाव यह भी दिखाएगा कि हमारे किसान उत्पादन में क्या परिवर्तन करते हैं?

लंबे समय से भारत गेहूं और धान सहित कई फसलों में आत्मनिर्भर हो गया है। इनमें हमारी स्थिति अधिशेष की हो गई है। बाजार की मांग और रुझानों की समझ में वृद्धि से किसान फसल में विविधता लाएंगे। उन्हें बाजार में ऊंचे दाम मिलेंगे। साथ ही देश की आयात पर निर्भरता भी घटेगी। खाद्य तेलों के अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण भारत को फिलहाल 10 अरब डॉलर के खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। सरकार ने जिन सुधारों का आगाज किया है, उनसे कृषि व्यवसायी किसानों से सीधी खरीद करने में सक्षम होंगे। साथ ही निर्यात एवं खाद्य प्रसंस्करण की हिस्सेदारी बढ़ेगी और कृषि कारोबार को बिचौलियों तथा ढुलाई की दुश्वारी से मुक्ति मिलेगी। पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसकी मिसाल हैं। यहां आलू का बीज उत्पादित करने वाले एक हजार से अधिक किसानों ने आइटीसी की सहायक कंपनी टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड के साथ करार किया। इससे जहां किसानों की उत्पादकता में 10 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं उन्होंने लागत पर 35 प्रतिशत मार्जिन का लाभ भी अर्जित किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां कारोबारियों से करार कर किसानों की आय बढ़ने के साथ ही कृषि कारोबार का विस्तार हुआ है। दुनिया के करीब 30 देशों में 300 से अधिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स में निवेश और रुझानों पर नजर रखने वाले वैश्विक मंच ट्रैक्सकन के अनुसार 2018 के बाद से भारतीय कृषि स्टार्टअप्स ने कृषि बाजार, रसद और भंडारण में 15 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है। वहीं नैसकॉम का मानना है कि एग्री-टेक स्टार्टअप द्वारा 2019 में 25 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए गए। वास्तव में कृषि प्रबंधन में नवाचार से उत्पादकता में सुधार आएगा, फसल की कटाई के बाद के प्रबंधन में सुधार से अपव्यय कम होगा, डिजिटल बाजारों में पहुंच बढ़ेगी और बाजार से जुड़ाव होगा। सबसे उत्साहवर्धक चीज है कि बाजार सुधार कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। नए बाजार सुधारों के साथ हम मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखेंगे। यह सहयोगी क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करेगा, जैसे लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, वेयरहाउस ऑपरेटर, प्रोसेसिंग यूनिट स्टाफ आदि। हम बहुजनहितकारी कृषि कार्य भी देखेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अब खरीद और विपणन के लिए एफपीओ सीईओ या प्रबंधक बनने की ख्वाहिश रख सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार सुधार कई सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, जैसे किसानों के लिए उच्च आय, नई नौकरियां, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास आदि।

भारत कृषि विकास के एक नए पायदान पर है। एक ऐसा पायदान जिसे किसान, व्यवसायी, सरकार और उपभोक्ता मिलकर बनाएंगे। सरकार की कई अलग-अलग पहलों के जरिये हम इस राह पर आए हैं और कृषि संबंधी इन दो अधिनियमों के पारित होने के बाद अब हम किसानों की आय दोगुनी करने, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में विकसित करने और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सार्थक आजीविका प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। ■

नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ

1. मुक्त बाजार

कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य कानून-2020 राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब कानून बन चुका है। अब किसान देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

मौजूदा प्रणाली : फिलहाल किसान राज्य सरकार की कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी मंडियों में अपने उत्पाद बेचते हैं। वे अधिकृत कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर होते हैं। ये एजेंट किसानों से मिलने वाली रकम में से डेढ़ से तीन फीसद की कटौती कर लेते हैं। एजेंट यह कटौती उत्पाद की सफाई, छटाई व अनाज का ठेका आदि के नाम पर करते हैं। मंडियाँ एजेंटों से फीस वसूलती हैं। एफसीआई समेत अन्य सरकारी एजेंसियाँ 60-90 दिनों तक एमएसपी के आधार पर किसानों से फसलों की खरीद करती है।

ऐसे होगा लाभ : किसान अपने लिए बाजार का चुनाव कर सकते हैं। अपने या दूसरे राज्य में स्थित कोल्ड स्टोर, भंडार गृह या प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उत्पाद बेच सकते हैं। फसलों की सीधी बिक्री से एजेंट को कमीशन नहीं देना होगा। न तो परिवहन शुल्क लगेगा और न ही सेस या लेवी देनी होगी। इसके बाद मंडियों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी होना होगा।

2. अनुबंध कृषि

मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून-2020 के कानून बनने के बाद किसान अनुबंध के आधार पर खेती करने के लिए आजाद हो जाएँगे।

मौजूदा प्रणाली : मौजूदा अनुबंध कृषि का स्वरूप अलिखित है। फिलहाल निर्यात होने लायक आलू, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी व फूलों के उत्पादन के लिए ही अनुबंध किया जाता है। कुछ राज्यों ने मौजूदा कृषि कानून के तहत अनुबंध कृषि के लिए नियम बनाए हैं।

ऐसे होगा लाभ : किसान आपसी सहमति के आधार पर फसल की कीमत तय करते हुए उसकी बिक्री के लिए प्रसंस्करण इकाइयों, थोक विक्रेताओं व निर्यातकों आदि से समझौता कर सकते हैं। इसके जरिए किसानों को फसल बोने से पहले उसके न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि किसानों का जोखिम अब खरीदार उठाएँगे। किसान फसल की बुवाई से पहले रणनीति तय कर सकेंगे और उसके अनुरूप बीज, खाद आदि की खरीद कर सकेंगे। बाजार मूल्य अगर ज्यादा हो जाता है तो खरीदारों को उसी के अनुरूप भुगतान करना होगा चाहे समझौते में उत्पाद की कीमत कम ही क्यों न तय हुई हो। विवाद की स्थिति में तय समय सीमा में उसका निस्तारण किया जाएगा।

3. असीमित भंडारण

आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाले तेल, प्याज व आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी।

ऐसे होगा लाभ : कानून बनने के बाद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के प्रति बड़ी कंपनियाँ और विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। इसके जरिए कोल्ड स्टोर व भंडारण गृहों की व्यवस्था दुरुस्त होगी। जब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला दुरुस्त होगी तो कीमतों में भी स्थिरता आएगी। फसल अच्छी होने की स्थिति में कीमत बहुत कम नहीं होगी और खराब होने की स्थिति में मूल्य आसमान पर नहीं चढ़ेगा। भंडारण की सुविधा अच्छी होने के बाद अनाज की बर्बादी भी कम हो जाएगी।

राष्ट्रीय सहकारिता का विस्तार

रमेशचंद्र मालवीय » *मालवा प्रांत संगठन प्रमुख, सहकार भारती*

सहकारिता का इतिहास मानव के जन्म के साथ ही प्रारंभ होता है, संपूर्ण प्रकृति सहकार के माध्यम से संचालित है। यह व्यक्ति से चलकर परिवार फिर समाज और राष्ट्र तक पहुँचकर संपूर्ण विश्व को जोड़ती है। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले सभी दिशाओं, वायु, जल, भूमि आदि देवीय शक्तियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें आह्वान करते थे कि वे सभी हमारे इस कार्य की सफलतापूर्वक पूर्ण होने तक सहयोग करें। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सहकारिता के संबंध में उल्लेख है।

'समानो मंत्र समिति समानी, समान मनः सहचित्त मेषाम।
समानं मंत्रमभिमंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहो मि।।'

अर्थात् 'तुम्हारी समिति एक हो, तुम्हारी मंत्रण मन के विचार एवं चित्त भी एक हो ताकि सभी कार्य सफल हो सकें।'

इसी प्रकार अथर्ववेद में भी सहकारी समिति के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए निम्न उल्लेख है। 'एक साथ श्रम करने के फलस्वरूप जो काम हो उसे सभी सहयोगियों में वितरित करें जल व अन्न के भागों का समान वितरण हो, एक ही भाव में बंधकर सब साथ मिलकर कार्य करें। जिस प्रकार रथ चक्र की भुजाएँ नाभि के चारों और लगी होती हैं। उसी प्रकार तुम भी समिति में संगठित होकर कार्य करो।

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल से सहकारिता की भावना का मूल उद्‌गम स्थल भारत ही है। यहाँ की सहकारिता स्वभाविक गुण सांस्कृतिक एवं संस्कार की देन है। किसी के प्रति राग द्वेष, स्पर्धा या क्रिया की प्रतिक्रिया में से उत्पन्न नहीं हुई है। वस्तुतः यह हमारी संगठित शक्ति सृजन की दृष्टि एवं सर्वांगीण उन्नति की ही द्योतक है। इस भौतिक जगत में सहकारी भावना अभावग्रस्तता की संवेदना का एक स्वैच्छिक उपचार पंथ है, और सहकारी संस्था उसका पथ है, यह एक विश्वास तंत्र है।

आशादीप है जहाँ रात्रि रूपी अंधकार को दूर भगाकर भविष्य के सुप्रभात के मनकों की किरणें फूटती है। सरकार महर्षि धनंजयराव गाडगील, स्व. बैकुंठ भाई मेहता, पद्मश्री विखे पाटील जिनका जीवन सहकारिता के क्षेत्र में सदैव दीपस्तंभ की भाँति पथ प्रदर्शक एवं नवचेतना पुंज के रूप में रहा है, इन महर्षियों, पूर्वजों का ज्ञान और हमारी सांस्कृतिक धरोहरर, आज का पूर्व एवं पश्चिम में अपने अनुभवों के आधार पर हमें सहकारी आंदोलन में अटूट निष्ठा, अपार श्रद्धा, समर्पण और यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था या सुधार सहकार के बिना संभव नहीं हो सकता है।

सहकार एक जीवन जीने की पद्धति है, सहकारिता के सार्वभौमिक सिद्धांत सही सिद्ध हुए हैं। धर्म, जाति, लिंग तथा सभी सिद्धांत निरपेक्ष सहकारिता के आदर्शों ने समाज के हर वर्ग को जोड़ा है। सहकारिता विचारधारा के साथ ही एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। इसमें समान आवश्यकता वाले व्यक्ति सहयोग की भावना से समानता, सामूहिक चेतना, आम सहमति से गतिविधियाँ संचालित करते हैं तथा बदले में प्रतिफल पाने के हकदार होते हैं। सहकारी समिति व्यक्तियों की ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।

हम सब एक दूसरे के सहयोग और सहकार पर जीवित है। विश्व में उल्लेखनीय सृजन और आधुनिक सुविधाजनक जीवन शैली का विकास सहयोग और सहकार से ही संभव हुआ है। हमारे पूर्ववर्ती युग दृष्टाओं ने सहकार की मूलभावना के अनुरूप सहकारिता की अवधारणा को जन्म देकर अमलीजामा भी पहनाया है। हमारे देश की सहकारिता की वैधानिक प्राण प्रतिष्ठा हुए एक सौ दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जब सहकारिता का पहला अधिनियम बना और इसके माध्यम से समाज में सर्वांगीण विकास और समरसता पूर्ण व्यवहारिक जीवन पद्धति की नींव रखी गई, धीरे-धीरे, सहकारिता के स्वरूप में एक विशाल आंदोलन का रूप धारण कर लिया और सहकारी क्षेत्र के गौरव शिखर के रूप में हमारी स्टार संस्थाएँ, अमूल, इफको, कृभको जैसे वृहद संस्थानों का स्वरूप भी आज हमारे सामने हैं, इससे हम सब गौरवान्वित हैं।

सहकारिता की आंतरिक शक्ति और कुछ प्रदेशों में सक्रिय सदस्य सहयोग के कारण देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का हिस्सा 30 प्रतिशत पहुँच गया है। कई क्षेत्रों में तो सहकारिता का परचम सबसे ऊँचाई पर लहरा रहा है। कपास के क्षेत्र में 68 प्रतिशत, शक्कर उत्पादन 31 प्रतिशत और सूत उत्पादन में 22 प्रतिशत कब्जा सहकारिता का रहा है। एक करोड़ पंद्रह हजार परिवार सहकारिता की छत्रछाया में आज रोजगार पा रहे हैं और इसके जरिए लाखों अन्य परिवारों को स्व-रोजगार प्राप्त होता है।

सहकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक व प्रभावी है यह समाज सेवा का सशक्त माध्यम है, यह आर्थिक क्षेत्र का विश्व में सबसे बड़ा स्वयंसेवी उपक्रम है। भारत वर्ष में 6 लाख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लगभग 25 से 30 करोड़ जनता इनकी सदस्य हैं, अर्थात् देश की आबादी का एक चौथाई हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से सहकारिता से जुड़ा हुआ है। कृषि प्रधान अपने देश में ग्रामों की आबादी को लगभग किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़ी ही रहती है। कृषि में लगने वाला खाद का 70 प्रतिशत सहकारिता के माध्यम से वितरित कराया जाता है।

आज आर्थिक क्षेत्र में आए परिवर्तन में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा स्वतंत्र व्यवसायिक व्यवस्था की बढ़ती दौड़ में सहकारिता के द्वारा ही प्रभावी रूप से दृढ़ता के साथ खड़े रहकर उक्त चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि सहकारिता नैसर्गिक सिद्धांत पर स्थानीय परिस्थितियों और व्यक्तियों पर आधारित है। सहकारिता में इतनी सामर्थ्य है कि भविष्य में और भी चाहे कितनी आर्थिक पद्धतियाँ आए सब पर विजयी हो सकेगी। निष्ठावान प्रबुध संस्कारित सहकारी कार्यकर्ताओं के बल पर, यह सब कुछ निर्भर है।

हमारे देश में स्वदेशी अर्थव्यवस्था, मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति संगठन भाव, आर्थिक स्वावलंबन, व्यक्तिगत सक्रियता की प्रेरणा, प्रभावी नेतृत्वी क्षमता, प्रगतिशील विचार, रोजगारोन्मुखी सहायता, समुदाय के प्रति चिंता का सरोकार, सहकार से समाज के प्रति आर्थिक सेवा का भाव समाज व्यापी दिखाई देता है। समाज उत्थान अथवा सर्वांगीण उन्नति जैसे पवित्र भाव को लेकर सहकारिता एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्यरत है। इसमें समाज का 50 प्रतिशत हिस्सा महिला वर्ग का भी आता है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी का प्रतिशत बहुत ही कम है। ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आज समय की माँग है।

हमारे देश में आज जब हम प्रचलित सहकारी आंदोलन, संस्था, सहकारी कार्यकर्ता तथा इस क्षेत्र की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान परिलक्षित करते हैं। तब दृश्य विपरित, नैराश्यपूर्ण, मन को दुखाने वाला दिखाई देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने हाल ही में प्रदेश स्तर की एक सहकारी बैंक के पुनजीर्वन एवं पुनर्वास के लिए अध्ययन किया था। उसने अपनी रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया है कि 'पुनर्जीवन की प्रक्रिया बहुत कठिन है, इससे दुश्मन पैदा होते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है और भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, किंतु यह प्रक्रिया सहकारी संरचना और आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी है। पुनर्जीवन का कोई विकल्प नहीं है।

अतः राष्ट्रीय सहकारिता की व्यापकता के अर्थ और विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए जिन कारणों से सहकारिता के सिद्धांतों को आंच आती है उन्हें जड़ से हटाना तथा फलीभूत करने वाले प्रत्येक प्रयत्न को सफल बनाना आज की महती आवश्यकता है। सहकारिता के प्रबुद्ध संस्कारित कार्यकर्ताओं की संगठित शक्ति व सृजन दृष्टि से ही देश की सर्वांगीण उन्नति होगी एवं फिर से सहकारिता का क्षेत्र समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करने में सफल होगा।

हम सबको यह उद्‌घोष वाक्य, हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

बिन संस्कार, नहीं सहकार
बिन सहकार, नहीं उद्धार ■

गेहूँ उत्पादन की नई तकनीक

भूमि का चुनाव-खेत की तैयारी

गेहूँ की खेती के लिए काली, गुमट एवं हल्की जमीन जिसमें पानी की उपलब्धता होना आवश्यक है। अक्टूबर, नवंबर माह में दो-तीन जुताई कर खेत तैयार करें। पर्याप्त नमी के अभाव में आवश्यकतानुसार पलेवा कर खेत की तैयारी करें। यदि प्रति वर्ष संभव न हो तो हर दूसरे तीसरे वर्ष 10-15 टन प्रति हैक्टेयर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट अवश्य प्रयोग में लाएँ।

बीज उपचार

बीज जनित रोगों के बचाव के लिए दो से तीन ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को थायरस/ कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित करें। पीएसबी कल्चर 5 ग्राम/किलो बीज से उपचारित करने पर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है।

बोनी का समय

असिंचित तथा अर्द्धसिंचित गेहूँ की बोवनी 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एवं सिंचित क्षेत्र में 10 नवंबर से 25 नवंबर तक की जा सकती है। इसके अलावा देर से बोए जाने वाले गेहूँ की दिसंबर तक बोवाई की जा सकती है। गेहूँ की बोवाई में तापमान 20 डिग्री के आसपास हो तो अंकुरण अच्छा होता है।

बीज दर/बोने की विधि

100 किलो प्रति हैक्टेयर। देर से बोए जाने पर बीज दर में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। गेहूँ में 1000 दानों में वजन के आधार पर बीज की दर निर्धारित करें। सामान्यतः 1000 दानों का वजन जितने ग्राम आए उतने कि.ग्रा. बीज प्रति एकड़ उपयोग में लाएँ। बोनी किस्मों में 4 से 5 से.मी. गहराई तथा असिंचित किस्मों में 5 से 6 से.मी. गहराई पर बीज की बोवाई करें। कतार से कतार की दूरी 20 से 22 से.मी. रखें।

लागत में कमी (नई तकनीक)

*बीज एवं उर्वरक में महँगे आदान की मात्रा कम करने के लिए मेड़-नाली पद्धति अपनाने से बीज दर 30-35 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

*उर्वरक की खपत में कमी

*नींदा नियंत्रण आसान

*सिंचाई में पानी की कम मात्रा

जीरो टिलेट तकनीक :

धान की पछेती फसल की कटाई के उपरांत खेत में समय पर गेहूँ की बोवनी के लिए समय नहीं बचता और खेत, खाली छोड़ने के अलावा किसान के पास विकल्प नहीं बचता ऐसी दशा में एक विशेष प्रकार से बनाई गई बीज एवं खाद ड्रिल मशीन से गेहूँ की बुवाई की जा सकती है।

जिसमें खेत में जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती। धान की कटाई के उपरांत बिना जुताई किए मशीन द्वारा गेहूँ की सीधी बुवाई करने की विधि को जैसे टिलेज कहा जाता है। इस विधि को अपनाकर गेहूँ की बुवाई देर से होने पर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है एवं खेत को तैयारी पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। इस तकनीक को चिकनी मिट्टी के अलावा सभी प्रकार की भूमियों में किया जा सकता है। जीरो टिलेज मशीन साधारण ड्रिल की तरह ही है। इसमें टाइन चाकू की तरह है। यह टाइंस मिट्टी में नाली जैसी आकार की दरार बनाता है जिससे खाद एवं बीज उचित मात्रा एवं गहराई पर पहुँचता है।

जीरो टिलेज तकनीक के लाभ

1. इस मशीन द्वारा बुवाई करने से 85-90 प्रतिशत ईंधन,

उपयुक्त किस्मों का चयन : क्षेत्रवार बोवनी के समय एवं सिंचाई जल उपलब्धता के आधार पर

1. मालवा अंचल : रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, धार, देवास तथा गुना का दक्षिणी भाग

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3269, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1500, एच.आई. 1531, एच.डी. 4672 (कठिया)
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 322, जे.डब्ल्यू. 273, एच.आई. 1544, एच.आई. 8498 (कठिया), एम.पी.ओ. 1215
- **सिंचित (देरी से)** : जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 4010, एच.डी.2864, एच.आई. 1454

2. निमाड़ अंचल : खंडवा, खरगोन, धार एवं झाबुआ का भाग

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित**:जे.डब्ल्यू.3020,जे.डब्ल्यू. 3173, एच.आई. 1500, जे.डब्ल्यू. 3269
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 1201, जी.डब्ल्यू. 366, एच.आई. 1418
- **सिंचित (देरी से)** : इस क्षेत्र में देरी से बुवाई से बचें। समय से बुआई को प्राथमिकता क्योंकि पकने के समय पानी की कमी। किस्में : जे.डब्ल्यू. 1202, एच.आई. 1454

3. विंध्य पठार : रायसेन, विदिशा, सागर, गुना का भाग

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3173, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1531, एच.आई. 8627 (कठिया)
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 1201, एच.आई. 1544, जी.डब्ल्यू. 273, जे.डब्ल्यू. 1106 (कठिया), एच.आई. 8498 (कठिया), एम.पी.ओ. 1215 (कठिया)
- **सिंचित (देरी से)** : जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 4010, एच.डी. 2864, डी.एल. 788-2

4. नर्मदा घाटी : जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1531, जे.डब्ल्यू. 3211, एच.डी. 4672 (कठिया)
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1142, जी.डब्ल्यू. 322, जे.डब्ल्यू. 1201, एच.आई. 1544, जे.डब्ल्यू. 1106, एच.आई. 8498, जे.डब्ल्यू. 1215
- **सिंचित (देरी से)** : जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 4010, एच.डी. 2932

5. बैनगंगा घाटी : बालाघाट एवं सिवनी क्षेत्र

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 3269, जे.डब्ल्यू.3211,जे.डब्ल्यू.3288, एच.आई. 1544
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1201, जी.डब्ल्यू. 366, एच.आई. 1544, राज 3067
- **सिंचित (देरी से)** : जे.डब्ल्यू. 1202, एच.डी. 2932, डी.एल. 788-2

6. हवेली क्षेत्र : रीवा, जबलपुर और नरसिंहपुर का भाग

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 3020, जे.डब्ल्यू. 3173, जे.डब्ल्यू. 3269, जे.डब्ल्यू. 17, एच.आई. 1500
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 1106, जी.डब्ल्यू. 322, एच.आई. 1544
- **सिंचित (देरी से)** : जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एच.डी. 2864, एच.डी. 2932

7. सतपुड़ा पठार : छिंदवाड़ा एवं बैतूल

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित**: जे.डब्ल्यू.17, जे.डब्ल्यू. 3173, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1531
- **सिंचित (समय से)** : एच.आई. 1418, जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 1215, जी.डब्ल्यू. 366
- **सिंचित (देरी से)** : एच.डी. 2864, एम.पी. 4010, जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203

8. गिर्द क्षेत्र : ग्वालियर, भिंड, मुरैना एवं दतिया का भाग

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 3288, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 17, एच.आई. 1531, जे.डब्ल्यू. 3269, एच.डी. 4672
- **सिंचित (समय से)** : एच.आई. 1544, जी.डब्ल्यू. 273, जी.डब्ल्यू. 322, जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 1106, जे.डब्ल्यू. 1215, एच.आई. 8498
- **सिंचित (देरी से)** : एम.पी. 4010, जे.डब्ल्यू. 1203, एच.डी. 2932, एच.डी. 2864

9. बुंदेलखंड क्षेत्र : दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना का भाग

- **असिंचित/अर्द्धसिंचित** : जे.डब्ल्यू. 3288, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 17, एच.आई. 1500, एच.आई. 1531
- **सिंचित (समय से)** : जे.डब्ल्यू. 1201, जी.डब्ल्यू. 366, राज 3067, एम.पी.ओ. 1215, एच.आई. 8498
- **सिंचित (देरी से)** : एम.पी. 4010, एच.डी. 2864
- **विशेष** : सभी क्षेत्रों में अत्यंत देरी से बुवाई की स्थिति में **किस्में** : एच.डी. 2404, एम.पी. 1202
- **उन्नत कठिया किस्म** : एच.डी. 8713 (पूसा मंगल), एच.आई. 8381 (मालवश्री), एच.आई. 8498 (मालवा शक्ति), एच.आई. 8663 (पोषण), एम.पी.ओ. 1106 (सुधा), एम.पी.ओ. 1215, एच.डी. 4672 (मालव रत्न), एच.आई. 8627 (मालव कीर्ति)
- **सिंचित देर से बुवाई के लिए उपयुक्त किस्में** : जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3173

सिंचाई		नत्रजन	स्फुर	पोटाश
असिंचित खेती		40	20	10
अर्द्धसिंचित	एक सिंचाई दो सिंचाई	40 80	30 40	15 20
पूर्ण सिंचित	समय पर बोवाई देर से बोवाई	120 80	60 40	40 30

ऊर्जा एवं समय की बचत की जा सकती है।

2. इस विधि को अपनाने से खरपतवारों का जमाव कम होता है।

3. इस मशीन के द्वारा 1-1.5 एकड़ भूमि की बुवाई 1 घंटे में की जा सकती है। यह कम ऊर्जा की खपत तकनीक है अतः समय से बुवाई की दशा में इससे खेत तैयार करने की लागत 2000-2500 रु. प्रति हैक्टेयर की बचत होती है।

4. समय से बुवाई एवं 10-15 दिन खेत की तैयारी के समय को बचा कर बुवाई करने से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।

5. बुवाई शुरू करने से पहले मशीन का अंशशोधन कर ले जिससे खाद एवं बीज की उचित मात्रा डाली जा सके।

6. इस मशीन से सिर्फ दानेदार खाद का ही प्रयोग करें जिससे खाद एवं बीज की उचित मात्रा डाली जा सके।

7. इस मशीन में सिर्फ दानेदार खाद का ही प्रयोग करें, जिससे पाइपों में अवरोध उत्पन्न न हो।

8. मशीन के पीछे पाटा कभी न लगाएँ।

फरो इरीगेशन रेज्ड बेड (फर्ब) मेड़ पर बुवाई तकनीक

मेड़ पर बुवाई तकनीक किसानों में प्रचलित कतार में बोवनी या छिड़ककर बोवनी से सर्वथा भिन्न है। इस तकनीक में गेहूँ को ट्रैक्टर चलित रोजर कम ड्रिल से मेड़ों पर दो या तीन कतारों में बीज बोते हैं। इस तकनीक से खाद एवं बीज की बचत होती है एवं उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है।

मेड़ पर फसल बोने से लाभ

1. बीज, खाद एवं पानी की मात्रा में कमी एवं बचत, मेड़ों में संरक्षित नमी लंबे समय तक फसल को उपलब्ध रहती है एवं पौधों का विकास अच्छा होता है।

2. गेहूँ, उत्पादन लागत में कमी।

3. गेहूँ की खेती नालियों एवं मेड़ पर की जाती इससे फसल गिरने की समस्या नहीं होती। मेड़ पर फसल होने से जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है एवं जड़ें गहराई से नमी एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं।

4. इस विधि से गेहूँ उत्पादन में नालियों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यही नालियाँ अतिरिक्त पानी की निकासी की भी सहायक होती है।

5. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

6. मशीनों द्वारा निंदाई गुड़ाई भी की जा सकती है।

नींदानाशक रसायनों की मात्रा एवं प्रयोग समय			
नींदानाशक	**खरपतवार**	**दर/हे.**	**प्रयोग का समय**
पेंडीमिथेलीन	संकरी एवं चौड़ी	1.0 कि.ग्रा.	बुवाई के तुरंत बाद
सल्फोसल्फूरान	संकरी एवं चौड़ी	33.5 ग्रा.	बुवाई के 35 दिन तक
मेट्रीब्यूजिन	संकरी एवं चौड़ी	250 ग्रा.	बुवाई के 35 दिन तक
2, 4-डी	चौड़ी पत्ती	.4-.5 किग्रा	बुवाई के 35 दिन तक
आइसोप्रोट्यूरान	संकरी पत्ती	750 ग्रा.	बुवाई के 20 दिन तक
आइसोप्रोट्यूरान + 2, 4-डी	चौड़ी एवं संकरी पत्ती	750 ग्रा.+ 750 ग्रा.	बुवाई के 35 दिन तक

7. अवांछित पौधों को निकालने में आसानी रहती है।

खाद-उर्वरक

गेहूँ के लिए सामान्यतः नत्रजन स्फुर एवं पोटाश 4:2:1 के अनुपात में देना चाहिए। मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएँ। परीक्षण के आधार पर नत्रजन, फास्फेट एवं पोटाश की मात्रा का निर्धारण करें। जिंक सल्फेट का प्रयोग 3 फसल के उपरांत 25 कि.ग्रा./हैक्टे. की दर से करें।

(अ) बोवाई के समय स्फुर एवं पोटाश की पूरी तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा बोवाई के समय उपयोग करें।

(ब) नत्रजन की शेष मात्रा दो बराबर हिस्सों में बाँटकर पहली तथा दूसरी सिंचाई के साथ दें।

(स) असिंचित खेती में पूरी उर्वरक की मात्रा बोवाई के समय दें तथा असिंचित खेती में नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई कर दें।

सिंचाई

पहली सिंचाई 25 दिनों के अंतराल में अवश्य करें क्योंकि इस समय काऊन रूप बनती हैं जिससे कल्ले ज्यादा होंगे। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में, तीसरी सिंचाई 60 से 70 दिन में, चौथी सिंचाई 80 से 90 दिन में, पाँचवीं सिंचाई 90 से 100 दिन में दुग्धावस्था में देने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। नई विकसित किस्मों में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता नहीं 3-4 सिंचाई पर्याप्त (55-60 क्विंटल उपज) हैं। जहाँ तक संभव हो स्प्रिंकलर का उपयोग करें। एक सिंचाई अवस्था, पूरे कल्ले निकलने पर, दाना बनने के समय, चार सिंचाई : किरीट अवस्था, पूरे कल्ले निकलने पर, फूल आने पर, दुधिया अवस्था।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवारों द्वारा 25-35 प्रतिशत तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। यह कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। गेहूँ की फसल में होने वाले खरपतवार मुख्यतः दो भागों में बाँटे जाते हैं।

1. **चौड़ी पत्ती :** बथुआ, सेंजी, दूधी, कासनी, जंगली पालक, अकरी, जंगली मटर, कृष्णनील, सत्यानाशी, हिरनखुरी आदि।

2. **सँकरी पत्ती :** मोथा, कांस, जंगली जई, चिरैया बाजरा एवं अन्य घासें।

रासायनिक विधि से नींदा नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इससे समय की बचत होती है एवं आर्थिक रूप से भी लाभप्रद रहता है। इस विधि से नींदा नियंत्रण (तालिका में दर्शाए अनुसार) करते हैं।

पौध संरक्षण

प्रमुख कीटों में निम्नलिखित कीट ज्यादा नुकसान करते हैं :

1. **तना छेदक :** फसल के फूटान के समय इसका प्रयोग होता है। इसके नियंत्रण हेतु क्वीनालफास 25 ईसी एक लीटर दवा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टयर छिड़काव करें।

2. **मकड़ी एवं तेला :** यदि फसल पर लाल मकड़ी दिखाई दे तो डायमेथोएट 30 ईसी या फास्फोमिडान 85 डब्ल्यू.सी. का 300 मि.ली. 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

3. **झुलसा रोग :** फसल पर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से 3 बार छिड़काव करें।

4. **करनॉलबंट/कंडवा (लूस स्मट) :** प्रायः यह रोग म.प्र. में नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि लक्षण दिखाई दें तो रोगग्रस्त बालियाँ उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए।

5. **गेरुआ रोग :** यह लाल भूरा आदि रंग का होता है। सबसे अधिक हानि काले रस्ट से होती है। ज्यादा रोग फैलने पर दाने राई की तरह हो जाते हैं। पौधा लोहे की जंग के रंग का हो जाता है। नियंत्रण के लिए गंधक चूर्ण 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से भुरकाव करें या डायथेन एम-45 (0.2 प्रतिशत) का भुरकाव करें। इस रोग पर घुलनशील गंधक (0.2 प्रतिशत) घोल का प्रयोग करें।

कटाई एवं गहाई

फसल के पूरी तरह पकने पर कटे हुए गेहूँ के बंडल सावधानीपूर्वक बनाएँ। ज्यादा सूखने पर दाने झड़ने का अंदेशा रहता है तथा कटाई के तुरंत बाद थ्रेसिंग कार्य करना चाहिए। ■

प्रधानमंत्री ने नए कृषि विधेयकों की किसानों को बधाई दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए किसानों को बधाई दी है। इस सबंध में कई ट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, 'भारतीय कृषि के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर हमारे मेहनती किसानों को बधाई! इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। दशकों से भारतीय किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश रहे और बिचौलियों के हाथों परेशान होते रहे। संसद द्वारा पारित विधेयक किसानों को ऐसी विपत्तियों से मुक्त कराएंगे। ये विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे और उनके लिए अधिक समृद्धि सुनिश्चित करेंगे। हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसे नवीनतम तकनीक की सख्त जरूरत है जो मेहनती किसानों की सहायता कर सके। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही हमारे किसानों के लिए भविष्य की आधुनिक तकनीक तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा जिसके बेहतर परिणाम होंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम उनकी मदद करने और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

खरीफ बुआई 1116.88 लाख हे. में

नई दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने मिशन कार्यक्रमों और फ्लैगशिप योजनाओं का सफल कार्यान्वयन करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। भारत सरकार द्वारा बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसे इनपुटों का समय पर पूर्व-निर्धारण करने से महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान भी बड़े कवरेज को संभव बनाया गया है।खरीफ फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की प्रगति पर वर्तमान समय में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस वर्ष खरीफ फसल का क्षेत्र कवरेज 1116.88 लाख हेक्टेयर है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1066.06लाख हेक्टेयर था।

क्र. फसल	लाख हेक्टेयर में बोया गया क्षेत्र		% वृद्धि
	2020-21	2019-20	2019-20
1 चावल	407.14	385.71	5.56
2 दालें	139.36	133.94	4.05
3 मोटा अनाज	183.01	180.35	1.47
4 तिलहन	197.18	179.63	9.77
5 गन्ना	52.84	51.89	1.83
6 जूट और मेस्टा	6.98	6.86	1.78
7 कपास	130.37	127.67	2.11
कुल	**1116.88**	**1066.06**	**4.77**

रबी की नई एमएसपी को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का निर्णय लिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इसका अनुमोदन किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोक सभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि आज का दिन भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय के अनुसार, एमएसपी में 50 रूपए से लेकर 300 रू. प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) व अन्य नामित राज्य एजेंसियां एमएसपी पर पहले की तरह खरीद करेगी। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, वहीं मंडियों की व्यवस्था भी बरकरार रहेगी।

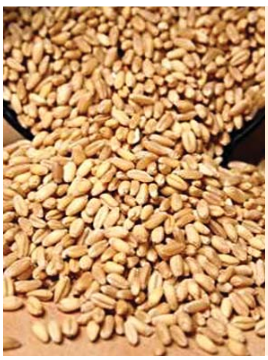

फसल	19-20	20-21
गेहूं	1925	1975
जौं	1525	1600
चना	4875	5100
मसूर	4800	5100
सरसों	4425	4650
कुसुम	5215	5327

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोगामुख (असम) में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर का उद्घाटन किया

संस्थान पूर्वोत्तर में कृषि के लिए प्रोत्साहन देगा : श्री तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोगामुख में नया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, असम परिसर देश को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि आईएआरआई असम का नाम पं दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार, इस संस्थान की स्थापना से असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2050 तक देश की जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ काफी बढ़ जाएंगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि देश का कृषि क्षेत्र इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो और हर समय पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद हो।

देश में कई उच्च उपज वाले बीज और फसल की किस्में विकसित करके हरित क्रांति लाने वाले कृषि वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका की सराहना करते हुए, श्री तोमर ने कहा कि देश अब न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन भी अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार ने विकास प्रक्रिया की खामियों को दूर करने के प्रयास किए हैं, और इसके परिणामस्वरूप झारखंड तथा असम में नए कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। सिक्किम अब पूरी तरह से जैविक राज्य है, और अन्य राज्य भी इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी की चुनौती के मद्देनजर, फसल विविधीकरण का कार्य करना और ऐसी किस्में विकसित करना महत्वपूर्ण है जिनकी पैदावार करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने किसानों की आय और निर्यात के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्थानीय रूप से विकसित फसलों के महत्व पर भी जोर दिया।

असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आईएआरआई असम की स्थापना के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि संस्थान अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने उद्यमशीलता के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की कृषि आय बढ़ाने के लिए क्षेत्र की स्थानीय रूप से विकसित बागवानी फसलों पर अनुसंधान गतिविधियों पर जोर दिया। श्री सोनोवाल ने यह भी उम्मीद जताई कि पूर्वोत्तर राज्यों को आईसीएआर-आईएआरआई, असम के समर्थन से फिर से ÷बाउल ऑफ राइस÷ के रूप में जाना जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा, जन प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी भी इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।

एनसीडीसी ने एमएसपी के लिए 19444 करोड़ मंजूर किये

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सर्वोच्च वित्तीय संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रक्रिया के अंतर्गत खरीफ सत्र में धान की खरीद के लिए 19444 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दी। यह राशि इसलिए मंजूर की गई है ताकि राज्यों और राज्यों के मार्केटिंग महासंघों (फेडरेशनों)को अपने सहकारी संगठनों के जरिए समयबद्ध ढंग से धान की खरीद करने की प्रक्रिया में सहायता मिले। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक यानी 9000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हरियाणा के लिए 5444 करोड़ रुपये और तेलंगाना के लिए 5500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। कोविड की महामारी के दौरान एनसीडीसी की ओर से पहले से उठा लिए गए इस कदम से इन तीनों रकज्यों के किसानों को बेहद जरूरी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी देश में धान के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत उपजाते हैं । उचित समय पर उठाए गए इस कदम से राज्यों की एजेंसियां तत्काल खरीद प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगी। इससे किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने में जरूरी सहायता मिलेगी।

एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक, श्री संदीप नाइक ने कहा कि एनसीडीसी माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुपालन में और ऐतिहासिक कृषि विधेयकों के प्रकाश में किसानों को उनके उत्पाद का अच्छे से अच्छा मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी प्रक्रिया को पूरा करने के वास्ते अन्य राज्यों को भी सहायता देने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन पर किसानों के लिए 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम पूरे प्रदेश में शुरू

आत्मनिर्भर मप्र का सपना सहकारिता से साकार करेंगे

पेक्स स्तर तक सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटराइजेशन होगा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ होगी। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों को चार हजार रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिलवाना है। करीब 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे-छोटे किसानों को जो अन्य योजनाओं के लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें वार्षिक छह हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब हितग्राही किसान को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता मिल सकेगी। किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से किसान हितैषी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित कर लागू किया जाएगा। सहकारिता विभाग में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य व्यापक स्तर पर होगा। साढ़े चार हजार प्राथमिक सहकारी समितियों में इस व्यवस्था के लिए राज्य शासन धनराशि उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस से आरंभ गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मिंटो हाल भोपाल में आयोजित 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों को ऋण और क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ ही सहकारी बैंकों और समितियों के खातों में 800 करोड़ रुपये की राशि जमा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 63 हजार हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी प्रदान किए।

सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत करते हुए कहा कि वर्चुअल आधार पर आयोजित इस कार्यक्रम से 15 लाख 8 हजार लोग जुड़े हैं। यह कार्यक्रम 43 हजार स्थानों पर लाइव प्रसारित हो रहा है। कुल 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर 335 करोड़ रुपये की साख सीमा स्वीकृत की गई। इसके साथ ही 35 हजार 532 किसानों को 122 करोड़ का ऋण का भी सहकारी समितियों द्वारा दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से किसानों, पशु पालकों, मत्स्य पालकों के जीवन में बदलाव आ रहा है। श्री भदौरिया ने कोरोना काल में सहकारी समितियों द्वारा रबी फसल के उपार्जन की दिशा में किए गए अभूतपूर्व कार्य के लिए सहकारिता विभाग तथा इससे जुड़ी समस्त समितियों और संस्थाओं की सराहना की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए राज्य सहकारी बैंक की ओर से एक करोड़ रूपए और सहकारिता विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से 13 लाख 53 हजार 651 रूपए की राशि का चेक भेंट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल जिले के पाँच हितग्राहियों को भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितलाभ प्रदान किए।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव ने किया। वेबकास्ट, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख प्रादेशिक चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

फल-सब्जियों के मार्केटिंग पर व्यय होंगे 7440 करोड़

मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन की बैठक सम्पन्न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना प्रारंभ की गई है। इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। जिलों में पैदा होने वाली फल-सब्जी और फसलों की ग्रेडिंग, पैकिंग तथा बेहतर मार्केटिंग के लिये अगले चार साल में 7 हजार 440 करोड़ रूपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जायेगा। हमारा उद्देश्य है कि किसान को उसके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिले। कृषि उत्पादों के वेल्यू एडिशन के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। जिलावार 17 कृषि उत्पादों और तकनीकी रूप से आवश्यक 36 गतिविधियों का चिन्हांकन कर लिया गया है। प्रत्येक स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन के लिये तकनीकी विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों और वित्तीय तथा व्यापार प्रबंधकों की सेवाएं ली जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन-एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गिर्राज दंडोतिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादों से संबंधित इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है। इसमें कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन उद्यानिकी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को पदस्थ किया जा रहा है। यह मिशन अधिकतम दो करोड़ रूपए तक की क्रेडिट गारंटी देगा, ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान रहेगा। यह मिशन राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा सिंगल विण्डो फैसेलिटी के रूप में कार्य करेगा। इसके तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, निवेश क्षेत्र व एक्सपोर्ट क्लस्टर की पहचान, जिला स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण तथा गतिविधियों व सूचनाओं को डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना आदि कार्य किए जाएंगे। मिशन द्वारा 15 बैंक से एम.ओ.यू.किया गया है।

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ के अंतर्गत आगर-मालवा व राजगढ़ में संतरा, अलीराजपुर में सफेद मूसली, अनूपपुर, बालाघाट, सीधी व उमरिया में आम, अशोकनगर व गुना में धनिया, बड़वानी, दमोह, धार, सागर, सतना, झाबुआ, कटनी, रायसेन तथा शिवपुरी में टमाटर, बैतूल में काजू, भिण्ड, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन और इंदौर में आलू, भोपाल व श्योपुर में अमरूद, बुरहानपुर में केला, छतरपुर, रीवा और शहडोल में हल्दी, जबलपुर में हरी मटर, मंदसौर, रतलाम और दतिया में लहसुन, पन्ना में आँवला, हरदा व खरगौन में मिर्च, होशंगाबाद में नींबू, शाजापुर व खण्डवा में प्याज और टीकमगढ़ तथा निवाड़ी में अदरक की ग्रेडिंग, सोर्टिंग तथा आवश्यकतानुसार राइपनिंग, कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चैन सुविधा विकसित की जाएगी।

भंडारण व मार्केटिंग के लिए 36 परियोजनाएँ

प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि मिशन के तहत कृषि उत्पादों में वेल्यू एडिशन के लिए आधुनिकतम तकनीक पर आधारित 36 परियोजनाओं को जोड़ा गया है। इनमें वेयर हाउस, प्याज भंडारण सुविधा, होपर बॉटम सायलो, ग्रेडिंग एवं सॉर्टिंग, लहसुन, उन्नत बीज, कोंदो कुटकी, सफेद मूसली, मूंगफली, टमाटर, धनिया की ग्रेडिंग व पैकेजिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, संतरा, कद्दू की ग्रेडिंग एवं स्टोरेज, आलू कोल्ड स्टोरेज, केला राइपनिंग स्टोरेज सेंटर, टमाटर एवं लहसुन सॉस उत्पादन इकाई, सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट, सोया उद्योग यूनिट, आम आधारित उद्योग, मिनी राईस मिल, कम्बाइन हार्वेस्टर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, केला टिशू कल्चर, कृषि सेवा केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि व्यवसाय विकास केन्द्र, ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, इफ्को बाजार, अजवाइन यूनिट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, एल.पी.जी. एजेंसी, पेट्रोल पम्प, बायो-डीजल, पशु आहार यूनिट तथा गुड़ की क्यूब उत्पादन इकाई शामिल हैं।

किसान आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा

शिवपुरी। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है, जिसमें प्रधानमंत्री के जन्म दिन को सप्ताह भर आयोजन कर गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। डॉ. भदौरिया शिवपुरी जिले के ग्राम टोड़ा में आत्मनिर्भर भारत अन्तर्गत आयोजित कृषक सहकारी सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी व मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों से किसान, मजदूर सहित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा गांव, गरीब, बेरोजगारों के लिये अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सहित अन्य सुविधाएं देकर उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूँ खरीदकर मध्यप्रेदश ने देश मे पहला स्थान प्राप्त किया है, यह किसानों की कड़ी मेहनत से ही सम्भव हो सका है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि जब व्यक्ति, समाज व प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तभी राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा।

कार्यक्रम में डॉ. भदौरिया ने लगभग दो दर्जन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये। कार्यक्रम में कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी अपने विचार रखें तथा शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

समितियों को आत्मनिर्भर बनाने मिलेगा 2 करोड़ तक ऋण

गुना। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया ने कहा है कि कृषि एवं सहकारिता के बल पर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इससे युवाओं और जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। इसके लिए भारत सरकार से प्रदेश को 7500 करोड़ रूपये की राशि मिली है। मंत्री डॉ. भदौरिया शुक्रवार को गुना जिले के बमौरी में आत्म निर्भर भारत-सहकारी संगोष्ठी विषय पर आयोजित सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने की। इस अवसर पर गुना विधायक श्री गोपीलाल जाटव भी मौजूद रहे।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि जिले से सहकारिता क्षेत्र के जो भी प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे उसे शीघ्र-अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत प्राथमिक सहकारी साख समितियों को आत्मनिर्भर व सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक प्रतिशत ब्याज की दर पर 2 करोड़ रूपये राशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए जरूरी है कि समितियाँ व्यवस्थित हों और समय पर उनका ऑडिट भी हो।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने बमौरी क्षेत्र में पोहा मिल एवं पॉपकॉर्न मिल लगाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के अंत में अतिथिद्वय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, केसीसी सामान्य एवं पशुपालन की कार्यशील पूंजी के चेक लाभार्थियों को प्रदाय किए गए।

22 लाख किसानों के खाते में 4686 करोड़ की राशि पहुँची

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4 हजार 686 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और सरकार का मुख्य केन्द्र बिन्दु किसान एवं खेती है। हर परिस्थिति में सरकार किसान के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में मौजूद किसानों एवं वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े लाखों किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने सरकार में आते ही किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा की पुरानी किश्त भरने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में कोई भी मंडी बन्द नहीं होगी। प्रदेश के किसान को यह सुविधा दी गई है कि वह चाहे तो अपने खेत से या अपने घर से भी अपनी उपज बेच सकता हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाया जायेगा और माँ नर्मदा का जल मालवा क्षेत्र में लाकर रहेंगे। आगामी तीन वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के लिये हरित क्रान्ति समिति का गठन भी किया जायेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वेब कास्टिंग के माध्यम से खंडवा, सागर एवं धार के किसानों से सीधे बातचीत की एवं उनके खाते में फसल बीमा राशि डालने की जानकारी के बारे में पूछताछ की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि यह देश किसानों का है और किसान इस देश की रीढ़ है। रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के साथ-साथ उज्जैन जिले में एक लाख 44 हजार 123 कृषकों को 868 करोड़ रुपये बीमा के रूप में भुगतान एक क्लिक से किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन जिले के छह किसानों को खरीफ-2019 की फसल बीमा राशि के भुगतान का प्रमाण-पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री पारस जैन, श्री बहादुरसिंह चौहान, श्री विवेक जोशी, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा, आईजी श्री राकेश गुप्ता, कलेक्टर श्री आशीष सिंह सहित गणमान्य अतिथि एवं कृषकगण मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री से भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को संसद में पारित किसान हितैषी विधेयकों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष श्री रामभरोस बसोतिया, महामंत्री श्री राजेन्द्र पालीवाल शामिल थे।

सहकारिता में गड़बड़ियाँ नहीं करेंगे बर्दाश्त : डॉ. भदौरिया

गुना। प्रदेश की सरकार गांव, गरीब, और किसानों की सरकार है। सहकारी समितियों में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। गड़बड़ियों को रोकने के लिये व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता व सुशासन के लिये विभागीय कार्यों में कम्प्यूटराइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात गुना के मानस भवन में गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों की बीमित दावा राशि उनके खातों में अंतरित करने के लिये आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कही।

कार्यक्रम में बताया गया कि अतिवृष्टि से जिले की क्षतिग्रस्त फसलों और आवासों के प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगभग 50 करोड़ रूपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस अवसर पर गुना जिले के 5 कृषकों को खरीफ वर्ष 2019 की क्षतिग्रस्त फसल की बीमित दावा राशि का भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र प्रतीक स्वरूप प्रदान किए। गुना विधायक श्री गोपीलाल जाटव ने भी संबोधित किया।

इसके पूर्व उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के 22 लाख किसानों के खातों में खरीफ वर्ष-2019 की क्षतिग्रस्त फसल की बीमित दावा 4688 करोड़ रूपये राशि का सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में अंतरित संबंधी कार्यक्रम का एलईडी लगाकर लाइव प्रसारण किया गया। गुना जिले के 32 हजार 584 कृषकों की 76.37 करोड़ रूपये की फसल बीमा दावा राशि भी उनके खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से अंतरित की गई।

गरीब और किसानों के सपने हो रहे है पूरे : श्री पटेल

ग्वालियर। आजादी के 70 सालों में पहली बार गरीब और किसानों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का सपना साकार हो रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक है।प्रदेश के एक करोड़ किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का आज से पूरे प्रदेश में वितरण शुरू हो गया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शुभारंभ अवसर पर ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ग्वालियर में कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सम्मान निधि देना शुरू किया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू कर किसानों को प्रतिवर्ष 4 हजार रुपये अतिरिक्त रूप से प्रदान करना प्रारंभ कर दिया हैं। प्रदेश के लगभग 80 लाख से एक करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों की उन्नति के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है जिसे पूरा करने के लिए हम सभी दृढ़संकल्पित है।

फसल बीमा योजना नए स्वरूप में लाई जाएगी : मुख्यमंत्री

खंडवा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनासा स्थित स्टेडियम में विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमिपूजन के कार्यक्रम में करोड़ों रूपए की सौगात देते हुए खंडवा जिले की मूंदी और किल्लोद नगर परिषद को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत सिंगाजी स्थल को प्रदेश का धार्मिक पर्यटन स्थल भी घोषित किया है। इसके अलावा उन्होंने यहां अधोसंरचना के विकास के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए भी देने की घोषणा की। विकास कार्यों के भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब मप्र में फसल बीमा योजना एक नए स्वरूप में लाई जाएगी।

पुनासा माइक्रों लिफ्ट एरिगेशन योजना का पुनः आंकलन कर छुटे हुए गांवों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दीन-दुखियों और गरीबों के लिए संबल योजना उनका हक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस वर्ष बारिश से प्रभावित हुई फसलों का ईमानदारी से सर्वे कराने के आदेश देते हुए कहा कि पर्याप्त राहत राशि की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को राशि और प्रमाण-पत्र वितरित किए।

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सर्वांगीण विकास के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में कदम बढ़ गए है। अब सरकार द्वारा निरंतर लोक कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभांवित किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आरबीसी 6/4 के अंतर्गत बारिश से प्रभावित फसलों की राहत राशि किसानों को प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को क्षेत्रीय सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में खंडवा विधायक श्री देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक श्री राम दांगोड़े, मांधाता के पूर्व विधायक श्री नारायण पटेल, खंडवा कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

श्री सुरेश पत्रकारिता विवि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ,भोपाल के नव पदस्थ कुलपति श्री केजी सुरेश ने सौजन्य भेंट की। कुलपति श्री सुरेश ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को विश्वविद्यालय के अकादमिक विकास के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि श्री सुरेश पत्रकारिता विश्वविद्यालय को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री सुरेश को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब वे सांसद थे तब श्री सुरेश से नई दिल्ली में अक्सर भेंट हो जाया करती थी। पत्रकारिता के दीर्घ अनुभव के साथ वे गंभीर और विचारवान व्यक्तित्व के धनी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री सुरेश के कुलपति के रूप में पदस्थ होने से यह विश्वविद्यालय निश्चित ही अलग प्रतिष्ठा बनाएगा। मध्य प्रदेश के मीडिया जगत, जनसंपर्क विभाग और देश-प्रदेश के मीडिया संस्थानों को इस केंद्र से शिक्षित, प्रशिक्षित अच्छे विद्यार्थी मिल सकेंगे।

सांवेर क्षेत्र के गाँव-गाँव तथा घर-घर पहुँचेगी नर्मदा

सांवेर (इंदौर)। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर जिले के सांवेर में लगभग 2400 करोड़ रूपये लागत की महत्वाकांक्षी माँ नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इस योजना से इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 178 गाँव लाभान्वित होंगे। इन गाँवों के एक लाख 58 हजार 147 एकड़ जमीन के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही इन गाँवों में पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिये भी पानी मिलेगा।

राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सांवेर क्षेत्र के लिये 2400 करोड़ रूपये की नर्मदा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने का असंभव कार्य संभव किया है। पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये दृढ़ संकल्पित होकर तेजी से कार्य कर रही है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि योजना से सांवेर क्षेत्र के विकास की तकदीर एवं तस्वीर बदलेगी। हर खेत तक सिंचाई के लिये पानी होगा, घर-घर तक पेयजल सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने नर्मदा जल के विशाल कलश पूजन के साथ कन्या पूजन भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये गये। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायकगण श्री रमेश मेंदोला, श्री आकाश विजयवर्गीय, श्री महेन्द्र हार्डिया, पूर्व विधायक डॉ राजेश सोनकर व श्री सुदर्शन गुप्ता और श्री गौरव रणदिवे विशेष रूप से मौजूद थे।

प्याज के भावांतर की राशि भी किसानों को दी जायेगी

देवास। मुख्यमंत्रीश्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले में हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोठा में 1041 करोड़ के 168 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हाटपीपल्या के 147 गांवों की 41 हजार हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कोई भी कृषि उपज मण्डी बंद नहीं होगी। किसान चाहें तो अपनी उपज घर बैठे या मण्डी के बाहर बेच सकेंगे। किसानों को यह स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्याज के भावांतर की राशि भी दी जायेगी। कोरोना के चलते प्रदेश के उद्योग धन्धे ठप्प हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार कर्ज लेकर किसानों की सहायता करेगी। कोरोना के खत्म होते ही पुन- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आरंभ कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ढाई एकड़ भूमि वाले किसानों के बच्चे यदि मेडिकल या इन्जीनियरिंग कॉलेज में पढाई करते है तो उनकी फीस शासन देगी।

राज्य सभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि लम्बे समय तक देवास में स्वर्गीय श्री तुकोजीराव पवार ने कुशल नेतृत्त्व किया। श्री सिंधिया ने कहा कि श्री मनोज चौधरी ने हमेशा हाटपीपल्या की जनता की सेवा की है। वर्तमान सरकार किसान-हितैषी सरकार है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री मनोज चौधरी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उपस्थित लोगो को संबोधित किया और पेयजल, डेम, पुल-पुलिया, बिजली, सिंचाई की सुविधा की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया। विधायक देवास श्रीमती गायत्री राजे पवार और पूर्व मंत्री श्री दीपक जोशी ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्य अथितियों का स्वागत कर स्मारिका भेंट में दी गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत विधायक खातेगांव श्री आशीष शर्मा, विधायक बागली श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, आष्टा विधायक श्री रघुनाथ सिंह, नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार भी उपस्थित थे।

सहकारिता हमारे देश की मूल आत्मा : सहकारिता मंत्री

मुरैना। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारिता हमारे देश की मूल आत्मा है। सहकारिता से ही आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि जब हमारे अन्नदाता किसान मजदूर, गरीब व नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हमारे गाँव, जिला, प्रदेश के साथ-साथ हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। मंत्री डॉ. भदौरिया मुरैना जिले में कृषि उपज मंडी मुरैना तथा विकासखण्ड मुख्यालय अम्बाह में अलग-अलग आयोजित कृषक सहकारी सम्मेलन में उपस्थित किसानों को सम्बोधित कर रहे थे।

डॉ. भदौरिया ने कहा कि किसानों की तरक्की के लिये प्रदेश सरकार अनेक योजनायें संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वर्ष में दी जा रही 6 हजार रूपये की राशि के अलावा 2 किश्तों में 2-2 हजार रूपये के मान से कुल 4 हजार रूपये प्रदेश सरकार की और दिये जायेंगे। इस तरह किसानों को वर्ष में कुल 10 हजार रूपये की राशि प्राप्त होगी।

किसान कल्याण एवं कृषि राज्य मंत्री श्री गिर्राज डंडोतिया ने कहा कि प्रदेश में सर्वहारा वर्ग की हितैषी सरकार है जिसने हर गाँव, गरीब किसानों की चिंता की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 37 लाख नये पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान की है जिससे कि उन्हें राशन उपलब्ध हो सके। किसानों को पी.एम. किसान सम्मान निधि में मिल रही 6 हजार रूपये की राशि के अलावा अब प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 2 किश्तों में 4 हजार रूपये और देगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री रघुराज सिंह कंषाना ने भी अपने विचार रखे।

म.प्र. उपचुनाव में 3 नवंबर को मतदान, 10 को नतीजे

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा ने उप चुनाव 2020 के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि उप निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर को की जाएगी। नाम निर्देशन-पत्रों की वापसी 19 अक्टूबर को होगी। मतदान 3 नवम्बर को होगा एवं मतगणना 10 नवम्बर को होगी।

आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव के लिये मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। श्रीमती वीरा राणा ने बताया कि मध्यप्रदेश में विधानसभा उप निर्वाचन तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के सभी प्रावधान संबंधित जिलों/विधानसभा क्षेत्रों और राजनैतिक दलों, उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होंगे। आदर्श आचरण संहिता 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, सागर, इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास में जहॉं नगर पालिका निगम हैं, वहाँ केवल उसी विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी। शेष 12 जिलों अनूपपुर, छतरपुर, रायसेन, मन्दसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिण्ड, दतिया, धार, आगर-मालवा एवं राजगढ़ में पूर्ण रूप से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मंडियों का सुगम संचालन आवश्यक : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंत्रालय में भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समिति के सदस्य गण को जानकारी दी कि मंडियों को स्मार्ट स्वरूप दिया जा रहा है। मंडी परिसर मल्टीपरपज़ कैंपस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश लागू होने के बाद किसानों और व्यापारियों को मंडी परिसर में निरंतर बेहतर सुविधा मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक संरचना और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि मंडी फीस की दर 50 पैसे होने से किसानों और व्यापारियों के हितों के संरक्षण, मंडियों के सुगम संचालन और विकास गतिविधियों के विस्तार की प्रक्रिया में सहायता मिलना स्वाभाविक है।

विकास में महिलाएं होगी बराबर की भागीदार : श्री पटेल

हरदा। गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत मंडी प्रांगण हरदा में स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से ऋष्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जिले के ग्रामीण अंचलों के स्वयं सहायता समूह की लगभग 200 महिलाएं शामिल हुई। मंत्री श्री पटेल ने उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक विकास ही नहीं सामाजिक विकास के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनें सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना के क्रियान्वयन के बारे में अवगत कराया गया। श्री पटेल द्वारा 128 स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ 57 लाख रुपए की बैंक लिंकेज राशि का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल द्वारास्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए आजीविका उत्पादों का अवलोकन भी किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सीधे प्रसारण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आश्वस्त किया गया कि प्रदेश में चाइना से बनी वस्तुएं नहीं बेची जाएगी। अब यह कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जावेगा।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मनीष निशोद, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिलीप कुमार यादव, एडीएम श्रीमती प्रियंका गोयल एवं श्री जे.पी. सैयाम,सांसदप्रतिनिधिश्रीअमरसिंहमीणा, जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे।कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन श्री अमृतलाल परस्ते द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

सहकारिता मंत्री ने पुण्यतिथि पर गाँधी-शास्त्री को नमन किया

भोपाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मिंटो हॉल परिसर में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने उन्हें नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि उनके विचार, आदर्श, मूल्य, सिद्धांत तथा जीवन दर्शन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। बापू ने सत्य, अहिंसा व प्रेम का संदेश दिया तथा समाज में समरसता व सौहार्द का संचार करके विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। वे संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मंत्री डॉ. भदौरिया ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

आवास पाकर मंडी कर्मचारी हुए खुश

दतिया। कृषि उपज मंडी में कार्य करने वाले कुछ ही कर्मचारियों को शासकीय आवास उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी समिति दतिया के प्रागंण में दस मंडी अधिकारी एवं कर्मचारी शासकीय आवास पाकर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि आवास मिलने से वे अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मंडी निरीक्षक श्री अनिल माथुर ने बताया कि आवास मिलने पर वे एवं उनका परिवार बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि उनके सेवा काल में पहली बार शासकीय आवास प्राप्त हुआ है। आवास की सुविधा मिलने से उनके कार्य में भी गति आएगी और बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे। उन्हें अपने परिवार के लिए शहर में बार-बार किराए पर मकान ढूँढ़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल गया है। उल्लेखनीय है कि गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने गत दिनों मंडी परिसर दतिया में एक करोड़ 78 लाख की लागत से मंडी के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए दस आवास भवनों के फ्लेट को लोकार्पित कर चाबियां सौंपी थीं।

किसानों को फसल बीमा में न्यूनतम राशि का निर्धारण किया जाएगा

भोपाल। प्रदेश में किसानों को फसल बीमा योजना का यथोचित लाभ दिलाए जाने के लिए जल्द ही न्यूनतम बीमा राशि का निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को सम्मानजनक राशि का भुगतान बीमा योजना अंतर्गत किया जाए।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश के विभिन्न अंचलों के जिलों में औसतन रूप से किसानों को फसल बीमा योजना का न्यूनतम लाभ बेहतर तरीके से दिया गया है। अनुपपुर जिले में औसतन 5268 रुपए, बैतूल में 10,804 रुपए, बुरहानपुर में 49,360 रुपए, धार में 16,362 रुपए, हरदा में 20728 रुपए, होशंगाबाद में 16,772 रुपए, इंदौर में 19,664 रुपए, झाबुआ में 1228 रुपए, पूर्वी निमाड़ खंडवा में 10,232 रुपए, पश्चिम निमाड़ खरगोन में 3397 रुपए, सीहोर में 13,999 रुपए, शहडोल में 5774 रुपए और उमरिया जिले में 5763 रुपए औसतन प्रति किसान बीमा राशि का भुगतान किया गया है।

शीघ्र ही प्रदेश में किसानों को सम्मानजनक न्यूनतम बीमा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्णय लिए जा कर बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर कृषि विश्वविद्यालय में पौधरोपण

ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रो. एस. के. राव व अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से बने उपवन में गुलमोहर, खमेर एवं कचनार के पौधे रोपे। कुलपति प्रो. राव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व दिया है जिनके नेतृत्व में भारत ने विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं एवं उनकी आमदनी को दुगुनी करने के लक्ष्य को तय समय में पूरा करके किसानों के जीवन में अवश्य खुशहाली लाएंगे। इस अवसर पर निदेशक अनुसंधान डॉ. एम. पी. जैन, निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस. एन. उपाध्याय, निदेशक शिक्षण ए. के. सिंह, कुलसचिव डी. एल. कोरी, डॉ. एच. एस. भदौरिया, डॉ. कर्णवीर सिंह, डॉ. राजेश लेखी, डॉ. वाय. डी. मिश्रा सहित अधिकारी व वैज्ञानिकगण मौजूद थे।

प्रदेश के मंडियों को स्मार्ट मंडियाँ बनाएँगे : कृषिमंत्री

उज्जैन। गांव, गरीब एवं किसानों को सक्षम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। प्रदेश की मंडियों को स्मार्ट मंडियां बनायेंगे। जिस प्रकार मिलेट्री कैम्पस में सैनिकों के लिये सब सामान की सुविधाएं उपलब्ध रहती है, उसी तरह मंडियों में किसानों के लिये भी सर्वसुविधायुक्त स्मार्ट मंडियां बनाई जायेंगी।

इस आशय के विचार किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कालिदास अकादमी परिसर स्थित संकुल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सप्ताह अन्तर्गत 'सबको साख, सबका विकास' कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड/ऋण राशि वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किये। इस अवसर पर भोपाल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के प्रत्येक जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को ऑनलाइन के माध्यम से सम्बोधित कर प्रदेश पांच जिलों के कृषकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों को साल में तीन किश्तों में छह हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि में वृद्धि की जाकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि वे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को चार हजार रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रकार अब भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 10 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि राशि उपलब्ध कराई जायेगी। विधायक श्री पारस जैन ने कहा कि पहले से अब सिंचाई का रकबा बढ़ा है। इस वर्ष प्रदेश में रिकार्ड तोड़ गेहूं खरीदी हुई है। श्री जैन ने कृषि मंत्री से मांग की कि वे मंडी टैक्स 50 पैसे कर दी जाये। इस अवसर पर श्री राजपालसिंह सिसौदिया ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में कृषि मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पशुपालन, मत्स्य पालन हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत ऋण राशि प्रतीकात्मक रूप से वितरित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री लालसिंह राणावत, पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला, श्री विवेक जोशी, श्री शक्तिसिंह चौधरी, श्री केशरसिंह पटेल, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, कृषि विभाग के उप संचालक श्री सीएल केवड़ा, सहकारिता विभाग के उपायुक्त सहित किसान, अधिकारी आदि उपस्थित थे।

मंत्री श्री कुशवाह ने मटकुली नर्सरी का निरीक्षण किया

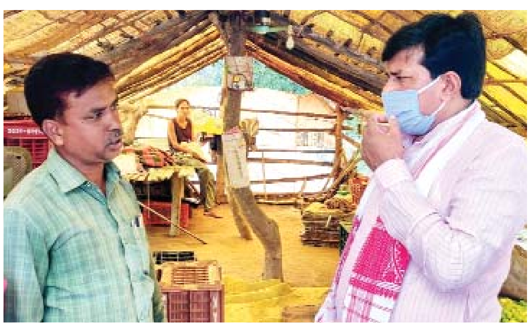

होशंगाबाद। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने होशंगाबाद जिले की उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने भोपाल में आयोजित संभागीय अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से फील्ड विजिट करने के निर्देश देते हुए कहा था कि वह स्वयं भी जिला, ब्लाक और नर्सरी स्तर पर जाकर विभागीय गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे।

श्री कुशवाह ने प्रदेश के उद्यानिकी विभाग की सबसे बड़ी मटकुली और पोलो नर्सरी का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरियों में काम करने वाले श्रमिकों , माली और स्थानीय अमले से चर्चा कर नर्सरी में चल रही पौध विकास और उनके रख रखाव की गतिविधियों की जानकारी ली। जंगल से लगे 85 एकड़ रकबे में फैली मटकुली नर्सरी में जंगली जानवरों से पोधौ को नुक़सान से बचाने के लिये राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने उप संचालक उद्यानिकी को चेन फेंसिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन के मरम्मत के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चेन फेंसिंग और भवन मरम्मत के प्रस्ताव विभाग को भेज कर कार्य करवाए। श्री कुशवाह ने नर्सरी का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उद्यान विभाग अधिकारियों के साथ होशंगाबाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी साथ थे।

सहकारिता के बगैर आत्मनिर्भरता संभव नहीं : श्री भदौरिया

भिण्ड। प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि देश की मूल आत्मा सहकारिता है। सहकारिता के बगैर आत्मनिर्भता संभव नहीं। मंत्री श्री भदौरिया कृषि उपज मंडी मेहगांव में आत्मनिर्भर भारत कृषक सहकारी सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। सम्मेलन में मेहगांव एवं गोहद के किसान मौजूद थे।

श्री अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि जब तक देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक गांव, जिला, प्रदेश व देश आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं। उन्होंने कहा कि हमे अपने अन्नदाता किसान, मजदूर, माता-बहनें, व्यक्ति, नौजवान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तभी हमारा गांव, जिला, प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके लिये केन्द्र व प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है।

सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें, जो किसानों की प्राथमिक ऋष्ठा आवश्यकताओं को पूरा करती है। सहकारी संस्थाओं को बहुसेवा केन्द्रों के परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि वे अपने व्यापार में विविधता ला सकें और एक छत के नीचे अपने सदस्यों की आवश्यकतायें पूरी कर सकें। सहकारी संस्थाओं की कायापलट करने के लिये नाबार्ड द्वारा कई पहल किये है। सहकारी संस्थायें आत्मनिर्भर संस्था बन सकें आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ का कृषि अधोसंरचना कोष सृजित किया गया है। जिसमें कृषि एवं अनुशांसिक गतिविधियों को सम्मानित कर फसल उत्पादन उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन अधोसंरचना विकसित किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें, विपणन संस्थायें एवं अन्य संस्थाओं का चयन किया गया है।

नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार सर्वहारा वर्ग की हितेशी सरकार है। जिसने हर गांव, गरीब, किसान की चिंता की है। समस्त विभागों में कई प्रकार की योजनायें संचालित की है। सांसद श्रीमती संध्या राय ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को 1 साल में दो-दो हजार केमान से 6 हजार रूपये दे रही है। ठीक उसी तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल से मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में दो-दो हजार के मान से 4 हजार रुपये सम्मान निधि देने की योजना प्रारंभ की है। जिसके अंतर्गत पहली किस्त 1 लाख 75 हजार किसानो के खातों में 2 हजार रुपये सम्मान निधि भेजी जा चुकी है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री मुकेश चौधरी, श्री नाथू सिंह गुर्जर, श्री केपी सिंह भदौरिया, श्री कोक सिंह नरवरिया, श्री अशोक भारद्वाज, श्री रमेश दुबे, श्री संजीव कांकर, श्री मलखान सिंह, श्री केशव सिंह भदौरिया, श्री अजय सिंह भदौरिया, श्री केदारनाथ वर्मा, श्री देवेद्र नरवरिया, जनप्रतिनिधि सहित गोहद एवं मेहगांव क्षेत्र के किसान उपस्थित थे।

कृषक रबी सीजन में कम सिंचाई वाली फसलों का चयन करें

गुना। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा जिले के किसान भाईयों को सलाह दी है कि जिले में कुल 867 मिमी वर्षा हुई हैं। जबकि जिले की औसत वर्षा 1053.5 मिमी हैं। रबी सीजन में सिंचाई हेतु पानी की कमी की स्थिति के दृष्टिगत कृषक भाई रबी सीजन में गेंहू फसल जो कि 4-5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, के स्थान पर अन्य फसलें जो कम अवधि वाली एवं कम समय एवं कम पानी में तैयार होकर उत्पादन दे सकती हैं जैसे- चना, सरसो, मसूर औसत कम पानी चाहने वाली फसले एवं उनकी किस्मो का चयन कर ही बुआई करें।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाए किसान

होशंगाबाद। परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के किसानो से कहा है कि वे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अपना पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाए। योजनांतर्गत 60 वर्ष की आयू पूर्ण होने पर उन्हें प्रति वर्ष 36 हजार रूपए मिलेंगे। योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 2 हेक्टर भूमि धारक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसानो को 60 वर्ष की आयु उपरांत प्रतिमाह पेंशन स्वरूप 3 हजार रूपए प्राप्त होंगे। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवार को पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत राशि मिलेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक लघु या सीमांत श्रेणी का होना चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

डॉ. अग्रवाल सहकारिता आयुक्त एवं प्रीति मैथिल कृषि संचालक बनीं

एम.के. अग्रवाल

प्रीति मैथिल

भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नवीन पदस्थापना करते हुए डॉ. एम.के. अग्रवाल को आयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ एवं प्रीति मैथिल को कृषि संचालक के पद पर पदस्थ किया है।

नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
डॉ. एम.के. अग्रवाल	सचिव आयुष	आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ
एम.बी. ओझा	कमिश्नर ग्वालियर	सचिव शासन
डॉ. मसूद अख्तर	एमडी अजा वित्त विकास निगम	सचिव गृह
जनक कुमार जैन	कमिश्नर सागर	सचिव शासन
महेशचंद्र चौधरी	कमिश्नर जबलपुर	सचिव शासन
बी. चंद्रशेखर	आयुक्त आदिवासी विकास	कमिश्नर जबलपुर
मुकेश कुमार शुक्ला	आयुक्त उच्च शिक्षा	कमिश्नर सागर
आशीष सक्सेना	आयुक्त पंजीयक सह.संस्थाएँ	कमिश्नर ग्वालियर
संजीव सिंह	संचालक कृषि	आयुक्त आदिवासी वि.
शिल्पा गुप्ता	सीईओ रोजगार गारंटी	उपसचिव पंचायत
सूफिया फारूकी वली	संचालक पीईबी	सीईओ रोजगार गारंटी
प्रीति मैथिल	उपसचिव कृषि	संचालक कृषि
गणेश शंकर मिश्रा	ट्रेनिंग से लौटे	संचालक संस्थागत वित्त
षणमुख प्रिया मिश्रा	ट्रेनिंग से लौटे	सीईओ कौशल विकास
उषा परमार	उपसचिव गृह	अपर आयुक्त भोपाल
हरिसिंह मीणा	अपर आयुक्त भोपाल	उपसचिव गृह

खरीफ का पंजीयन 15 अक्टूबर तक

भोपाल। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन हेतु 24 पंजीयन केन्द्रों पर किसान पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। किसान पंजीयन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। समस्त कृषक जिनके द्वारा अपनी कृषि भूमि में धान एवं मोटा अनाज बोया है तथा समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय करना चाहते हैं, अपना पंजीयन करवा सकते हैं। विभिन्न पंजीयन केन्द्रों पर 22 सितम्बर तक 56 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है।

छिंदवाड़ा में 48.52 लाख रु. के केसीसी और ऋण वितरित

छिंदवाड़ा। गरीब कल्याण सप्ताह के अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की विभिन्न शाखाओं और समितियों में सहकारी संगोष्ठी में लगभग 215 हितग्राहियों को 48.52 लाख रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड और ऋण भी वितरित किये गये। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रतीकस्वरूप 15 पशुपालक कृषकों 3.28 लाख रूपये और 5 मत्स्य पालक कृषकों को 50 हजार रूपये की ऋण राशि के चेक वितरित किये। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक श्री प्रकाश भंडारे, उपायुक्त सहकारिता व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री जी.एस.डेहरिया, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री के.के.सोनी, बैंक के सहायक प्रबंधक एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री ए.के.जैन, सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री रवि कुमार गजभिये, अन्य अधिकारी और पशुपालक व मत्स्यपालक कृषक उपस्थित थे।

अंकेक्षण न कराने वाली सहकारी संस्थाओं को नोटिस जारी

इंदौर। जिले में सभी सहकारी संस्थाओं को वर्ष 2019 - 20 के वित्तीय पत्रकों को आगामी 15 दिवस में जमा करने के निर्देश दिए है। साथ ही संस्था प्रबंधक पर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 कि धारा 56 (3) के तहत् नोटिस जारी किए गए है। सहायक आयुत (अंके.) सहकारिता कुमारी वर्षा श्रीवास ने बताया कि सभी सहकारी संस्थाओं को लेखा वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर या 30 जून तक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। लेकिन अभी तक जिले के अधिकतम सहकारी संस्थाओं ने यह पत्रक जमा नहीं कराए है। ऐसी संस्थाओं विरूद्ध 50 हजार रुपए की शास्ति की कार्यवाही कि जाएगी।

पुण्यतिथि पर स्व. माधवराव सिंधिया को याद किया

स्व. सिंधिया ने विकास को हमेशा प्राथमिकता दी : मोघे

इंदौर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवरावजी सिंधिया की 19 वीं पुण्यतिथि पर बंगाली चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने श्री सिंधिया के किए गए कार्यो को याद किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णमुरारी मोघे ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया एक सफल राजनेता के साथ-साथ उनका राजनीतिक जीवन पारदर्शी था। वे जनता के दुख दर्द में हमेशा उनके साथ रहते थे। उन्होनें कहा कि स्व. सिंधिया का व्यक्तिगत जीवन पारदर्शी और छविवान रहा। उनका समान हमेशा विरोधी दल भी करते थे। देश व क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी गई। रेलवे मंत्री रहते हुए उनके द्वारा नई ट्रेनें और नई रेल लाइन के कार्य करवाए गए। उन्होंने विकास को हमेशा आगे रखा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सांसद शंकर लालवानी, केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, प्रमोद टंडन, प्रकाश तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, महामंत्री गणेश गोयल, घनश्याम शेर, नानूराम कुमावत, मुकेश मंगल, अजयसिंह नरूका, अजय सेंगर, लकी अवस्थी, गजेंद्र गावड़े सहित अन्य भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माधवरावजी सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

सांवेर में 'सबको साख-सबका विकास' का आयोजन

इंदौर। सहकारिता विभाग म.प्र.शासन के तत्वाधान में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड/ऋण राशि/ सहकारी बैंकों एवं समितियों को सहायता राशि का वितरण किया गया। इंदौर जिले में मुख्य कार्यक्रम कृषि उपज मण्डी सांवेर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री राजेश सोनकर, श्री इकबाल गांधी, श्री भारत सिंह, श्री दिलीप चौधरी, श्री हुकुम सिंह सांखला, श्री जितेन्द्र आंजना, श्री सूरज सिंह दरबार आदि जनप्रतिनिधिगण विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के अलावा अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर, उपायुक्त सहकारिता श्री मदन गजभिए, मण्डल प्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ श्री महेश त्रिवेदी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें श्री प्रमोद शर्मा, जिला लीड बैंक प्रबंधक श्री राजू फतेहचंदानी, आईपीसी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.के.खरे भी उपस्थित थे।

भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले में इंदौर प्रीमियर को-आपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड के मुख्यालय, बैंक की 19 शाखाओं, बैंक से सम्बद्ध 120 सेवा सहकारी संस्थाओं तथा 160 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के साथ-साथ जिले की ग्राम पंचायतों, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों, विपणन सहकारी संस्थाओं, सहकारी शीतगृह राउ आदि स्थानों पर किया गया।

अप्रतिम शहर है इंदौर, सदैव दिखाता है समाज को दिशा

इंदौर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले तीन वर्षों में इंदौर में हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का आवास मुहैया कराया जाएगा। इंदौर एक ऐसा अप्रतिम शहर है जिसने सदैव ही समाज को एक दिशा दी है। उन्होंने इंदौर के नागरिकों और व्यापारियों द्वारा सप्ताह में दो दिन स्वैच्छिक लॉकडाउन की पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-तीन में आयोजित विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय की पहल पर यहाँ 50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, श्री रमेश मेंदोला, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री मधु वर्मा, श्री गौरव रणदिवे, डॉ. राजेश सोनकर, श्री उमेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री आकाश विजयवर्गीय को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहते हुए कहा कि विकास के प्रति जैसी ललक आकाश के मन में है वह सराहनीय है। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य आगे भी निरंतर होते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के व्यापारिक संगठनों की उस पहल को सराहा, जिसके तहत व्यावसायिक संस्थान सायंकाल छह बजे बंद करने और सप्ताह में दो दिन स्वैच्छिक लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर के नागरिकों ने सदैव ही मिसाल क़ायम की है। यह अद्भुत शहर है जिसने पिछली गर्मियों में यहाँ से गुज़रने वाले प्रवासी मज़दूरों के खाने से लेकर नंगे पैरों में जूते चप्पल पहनाने तक का इंतज़ाम किया था। इस शहर के जज्बे ने ही स्वच्छता में इसे चौथी बार सिरमौर बनाया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी की इंदौर चौका ही नहीं छक्का भी लगाएगा।

ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी मिलेगी हरसंभव मदद

हरदा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी हरसंभव मुहैया कर रही है, जिससे कि उन्हें व्यवसाय में सहुलियत मिल सके। मंत्री श्री पटेल जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना अन्तर्गत ऋण वितरण प्रमाण-पत्र कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने 279 हितग्राहियों को 27 लाख 90 हजार रूपये के ऋण प्रमाण-पत्र वितरित किये। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मनीष निशोद, जनपद अध्यक्ष श्रीमति फून्दाबाई एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

श्री पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में छोटी पूंजी के व्यावसायियों पर विपरित प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को आवश्यक मदद मुहैया कराने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हितग्राही को 10-10 हजार रूपये की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करा रही है। इससे उन्हें और उनके परिवार को आवश्यक संबल मिलेगा साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार 'सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास' के मूल मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग को सक्षम एवं समर्थ बनाने के लिये कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के हितग्राहियों से चर्चा की। ग्राम महेन्द्रगांव के हितग्राही महेन्द्र बघेल, ग्राम बालागांव के हितग्राही संतोष दारसे, ग्राम मगरधा के हितग्राही बहीद खां, ग्राम नकवाड़ा के हितग्राही भागवत एवं दुर्गा शर्मा ने कोरोना काल के दौरान उनके व्यवसाय पर पड़े विपरित प्रभाव के बारे में बताया, साथ ही उन्होंने ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से प्राप्त होने वाली राशि को अपनी आजीविका के लिए संजीवनी बताया। मंत्री श्री पटेल ने हितग्राहियों को विश्वास दिलाया कि सभी को आवश्यक सहायता दी जाएगी।

डिजिटल तकनीक से इंदौर सहकारी दुग्ध संघ की हुई वार्षिक साधारण सभा

इंदौर दुग्ध संघ का टर्नओवर 559.81 करोड़ रु. : श्री पटेल

इंदौर। कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये इंदौर सहकारी दुग्ध संघ की सैंतीसवें वार्षिक साधारण सभा डिजिटल तकनीक से आयोजित की गई। इसमें लगभग 819 संघ प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भाग लिया।

सभा की अध्यक्षता करते हुए दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री मोतीसिंह पटेल ने कहा कि दुग्ध संघ का वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर 559.81 करोड़ रूपये रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वार्षिक कार्ययोजना अनुसार टर्न ओवर 734.88 करोड़ रूपये होना संभावित हैं। दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 2019-20 में 16.41 करोड़ रूपये का लाभ एवं दुग्ध समितियों द्वारा भी 918.55 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया गया हैं, जो संघ की प्रगति का परिचायक हैं। संचालक मण्डल द्वारा तीन नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी आम सभा में सदस्यों को दी गई हैं। बताया गया कि मेधावी छात्र/छात्रा पुरूस्कार योजना अंतर्गत कार्यरत दुग्ध समितियों के सदस्य के पुत्र/ पुत्रियों जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरूस्कार एक हजार रूपये निर्धारित की गई हैं। यह राशि 50 प्रतिशत दुग्ध समिति एवं 50 प्रतिशत इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा वहन की जायेगी।

श्री तंवरसिंह चौहान, श्री रामेश्वर गुर्जर, श्री विकम मुकाती संचालक इन्दौर दुग्ध संघ एवं श्री घनश्याम पाटील पूर्व संचालक द्वारा भी सभा को संबोधित करते हुए दुग्ध क्रय भाव में वृद्धि हेतु प्रस्ताव रखा गया। श्री चौहान द्वारा अन्य राज्यों के अनुरूप म.प्र. शासन को दूध के भाव में 5 रूपये प्रति लीटर अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया। श्री उमरावसिंह मौर्य पूर्व अध्यक्ष इंदौर दुग्ध संघ द्वारा संबोधित करते दुग्ध क्रय दर एवं तरल दुग्ध विक्रय में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया। साथ ही उनके द्वारा दुग्ध संघ द्वारा संचालित साँची बीमारी सहायता योजना, कर्मचारी एवं सदस्य मृत्यु सहायता योजना की प्रशंसा की गई। श्री एस.सी. माण्डगे पूर्व अध्यक्ष एमपीसीडीएफ, भोपाल एवं एन.सी.डी.एफ.आई, दिल्ली द्वारा सुझाव दिया गया कि एमपीसीडीएफ, भोपाल द्वारा दुग्ध संघों से विकय राशि पर कमीशन लिया जाता है, उससे डिजिटल तकनीक के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो का निजी टेलीविजन चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया गया। श्री मोतीसिंह पटेल द्वारा दुग्ध संघ में कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। वर्तमान में दुग्ध समिति कर्मचारी की मृत्यु पर 2 लाख रूपये का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रूपये किये जाने एवं वर्तमान में संचालित दुग्ध समिति कमीशन 7 रूपये प्रति किलो फेट में वृद्धि कर 10 रूपये प्रति किलो फेट किये जाने की घोषणा की गई।

वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर संचालक श्री तंवरसिंह चौहान, श्री रामेश्वर गुर्जर, श्री विक्रम मुकाती, श्री कृपालसिंह सेंधव, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री रामेश्वर रघुवंशी, श्री राजेन्द्रसिंह पटेल, श्री जगदीश जाट, श्री किशोर परिहार, श्री महेन्द्र चौधरी, कलेक्टर प्रतिनिधि जिला खण्डवा डॉ. जी.एस.डॉवर संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग इन्दौर एवं राज्य सहकारी बैंक प्रतिनिधि श्री गणेश यादव, दुग्ध संघ पूर्व अध्यक्ष श्री उमरावसिंह मौर्य, पूर्व संचालक श्री एस.सी.माण्डगे, श्री घनश्याम पाटील, श्री महेश पटेल भी उपस्थित रहे।

दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.एन.द्विवेदी द्वारा दुग्ध संघ प्रतिनिधियों के समक्ष वार्षिक साधारण सभा की विषय सूची रखी गई। जिसका सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही दुग्ध संघ की समस्त गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि बटर चॉकलेट (मक्खन टिकिया) मशीन क्या की जा चुकी है। शीघ्र ही बाजार में उपभोक्ताओं को छोटे पैक में मक्खन टिकिया उपलब्ध हो सकेगी।

अपेक्स बैंक का 56वाँ वार्षिक साधारण सम्मिलन सम्पन्न

किसानों की सेवा समर्पित भाव से करें : डॉ. भदौरिया

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध व सशक्त बनाने का माध्यम बने। सहकारी कर्मी प्रदेश के किसानों की सेवा समर्पित भाव से करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश के सभी किसानों का दुर्घटना बीमा हो जिससे संकट की घड़ी में उनके परिजनों को सहारा मिल सके। अपेक्स बैंक इसके लिए एक समिति गठित कर बेहतर प्लानिंग करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें प्राथमिकता से निराकृत की जाएं, इन मामलों के निराकरण में कोई लापरवाही नहीं हो। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में 56वें वार्षिक साधारण सम्मिलन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' अंतर्गत समितियां अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में लें ताकि वे वायबल हो। मध्यप्रदेश में सहकारी समितियों की कार्य-प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिये समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर 2020 की स्थिति में पिछले वर्ष 7534 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को वितरित किया गया था जबकि चालू वर्ष में इसी अवधि में लगभग 9200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में जिला सहकारी बैंकों में एनपीए की तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिए गए कि सहकारी बैंकों में ऋण माफी के पहले व ऋण माफी के बाद की एनपीए संबंधी तुलनात्मक जानकारी तैयार की जाये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में बताया गया कि खरीफ 2019 में 74 हजार 860 कृषकों को 54 हजार 865 लाख रुपए की दावा राशि स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। रबी 2019 - 20 में 12 लाख 83 हजार 551 कृषकों का बीमा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 में पोर्टल पर प्रविष्टि की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अपेक्स बैंक द्वारा पिछले 5 वर्षों में किये गए विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। अपेक्स बैंक के साधारण वार्षिक सम्मिलन में वर्ष 2018- 19 एवं वर्ष 2019- 20 के अंकेक्षण की तुलनात्मक वित्तीय स्थिति, वर्ष 2020-21 हेतु किए गए बैंक के वित्तीय आंकलन का पुनरीक्षण, वर्ष 2021-22 हेतु कार्य व्यवसाय के वित्तीय अनुमानों के प्रतिवेदन का अनुमोदन, वर्ष 2019-20 के वास्तविक अंकेक्षित आय-व्यय का अनुमोदन, वर्ष 2020-21 के आय व्यय (बजट) का पुनरीक्षण एवं वर्ष 2021-22 के अनुमानित आय व्यय की स्वीकृति, बैंक के अंकेक्षित वित्तीय वर्ष 2019- 20 का अवलोकन किये जाने के साथ ही बैंक के वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित शुद्ध लाभ के विनियोजन/वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के लेखाओं के संपरीक्षण हेतु संनदी लेखाकार/संपरीक्षक की नियुक्ति तथा बैंक की लेखा पुस्तकों में दर्शित अपलेखन योग्य आस्तियों/हानियों के अपलेखन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में अपेक्स बैंक के 124 करोड़ के लाभार्जन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

अंत में मंत्री डॉ. भदौरिया ने गेहूं के रिकॉर्ड उपार्जन तथा देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उल्लेखनीय कार्य के लिए अपेक्स बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री प्रदीप जोशी व सहायक लेखा अधिकारी श्री विजय अग्रवाल को सम्मानित भी किया। बैठक में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता तथा अपेक्स बैंक के प्रशासक डॉ. एम.के. अग्रवाल, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री डी.एस. चौहान, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा विशेष रूप से उपस्थित थे।

मत्स्य महासंघ 12 हजार मी. टन मछली उत्पादन करेगा

भोपाल। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में मप्र मत्स्य महासंघ की 24 वी वार्षिक बैठक में सामूहिक अनुमोदन से आगामी वर्ष के लिए 12 हजार मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष संघ को 9 करोड से अधिक की शुद्ध आय प्राप्त हुई है। शासन 6 रुपए प्रति किलो के मान से 3 करोड़ 18 लाख की रॉयल्टी भी दी गई है।

मत्स्य महासंघ की 24वीं वार्षिक बैठक सम्पन्न

मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने कहा कि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए विभाग और मत्स्य महासंघ की भूमिका महत्वपूर्ण हैं मछुआ महासंघ के सदस्यों के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए संघ प्रभावी भूमिका निभा सकता है। सहकार के बिना उद्धार संभव नहीं है। इसके लिए सामूहिक रुप से प्रयास किये जाने चाहिये। श्री सिलावट ने कहा कि मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिये नई तकनीकों का प्रयोग करें, इसके लिए मछुआ संघ के सदस्यों को ज्यादा मछली उत्पादन करने वाले प्रदेशो में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जाये।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मछुआ संघ के सदस्यों के बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाये। उन्होंने कहा कि कृषि की तुलना में मछली उत्पादन व्यवसाय से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। महासंघ की सभा मे बताया गया कि 1 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मध्यंम और बड़े तालाब में आधुनिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है।

भोपाल दुग्ध संघ की 38वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न

मार्केटिंग बढ़ाने के लिए 250 मिल्क पार्लर तैयार होंगे

भोपाल। संभागायुक्त और दुग्ध संघ प्रशासक श्री कवीन्द्र कियावत ने भोपाल दुग्ध संघ के 38वें वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुग्ध मार्केटिंग बढ़ाने के लिए नयी डिजाईन में 250 पार्लर तैयार कर सुविधाजनक स्थानों पर शीघ्र प्रांरभ किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों की मांग के अनुसार दूध खरीदी के दाम बढ़ाने के लिए जल्दी समीक्षा की जाएगी। वार्षिक अधिवेशन में श्री कियावत ने कहा कि कोरोना महामारी एक चुनौती और संकट का समय है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पशुओं के पालन और संसाधन में भी कमी आने के बाद भी वर्तमान में प्रतिदिन 02 लाख 20 हजार लीटर दूध की खपत हो रही है। जिसे बढ़ाकर प्रतिदिन 02 लाख 60 हजार लीटर किये जाने की पहल की जा रही है। सम्मेलन में सीईओ डॉ. के.के. सक्सेना सहित जिलों के समितियों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अनेक समितियों के पदाधिकारियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।

श्री कियावत ने कहा कि भोपाल दुग्ध सहकारी संघ को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मार्केटिंग को दुरूस्त करना होगा। इसके लिए जिलों के एम.बी.ए. शिक्षित युवाओं को मार्केटिंग में कमीशन के आधार पर कार्य कराया जायेगा। जिससे दुग्ध संघ की बिक्री बढ़ेगी। उ

श्री कियावत ने कहा कि कलेक्टरों को विशिष्ट तौर पर दुग्ध विक्रेताओं के लिए पार्लर आवंटन के लिए निर्देश दिये गये हैं। मिल्क प्रोडक्ट की माकेर्टिंग के लिए शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैण्ड और ऐसे स्थान पर जहां मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग अधिक से अधिक हो सकें, वहां पार्लर स्थापित किये जायें। ऐसे प्रकरण समिति द्वारा दुग्ध संघ के सीईओ के संज्ञान में लाये जायें। उन्होंने कहा? कि एम.पी. नगर भोपाल में 1000 वर्गफिट के प्लॉट पर साँची ब्रांड के पार्लर तैयार कर सभी उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। सम्मेलन में प्रस्तुत सभी 12 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। कार्यक्रम में दुग्ध संघ समितियों के संचालक, दूध विक्रेता, कृषक अधिकारी उपस्थित थे।

इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि. की 104वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न

आईपीसी बैंक लि. इस वर्ष 4 करोड़ के शुद्ध लाभ में

इंदौर। इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि. (आईपीसी) की 104वीं वार्षिक साधारण सभा जाल सभागृह में संपन्न हुई। बैठक में बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री उमानारायण सिंह पटेल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री रंजनसिंह चौहान, पूर्व संचालक एवं नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री देवराज सिंह परिहार, पूर्व संचालक एवं जिला पंचायत इंदौर उपाध्यक्ष श्री गोपालसिंह चौधरी, पूर्व संचालकगण सर्वश्री बालाराम सिसोदिया, बहादुरसिंह डाबी, हरिसिंह नागर, बृजभूषण शर्मा तथा अपेक्स बैंक इंदौर के संभागीय शाखा प्रबंधक श्री गणेश यादव, सहायक आयुक्त सहकारिता सुश्री वर्षा श्रीवास व अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित हुए। अतिथियों के स्वागत उपरांत बैंक प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता श्री बबलू सातनकर ने बैंक की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विशेषकर कृषि विकास में बैंक काफी सहयोग कर रहा है। बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री एस.के. खरे द्वारा बैंक के वर्ष 2019-20 का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि बैंक ने इस वर्ष कुल 4 करोड़ 2 लाख रु. का शुद्ध लाभ उपार्जित किया है।

पुरस्कार ग्रहण करते राऊ शाखा के प्रबंधक श्री ओमप्रकाश श्रोत्रिय

बैंक की विभिन्न शाखाओं एवं बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं तथा बैंक मुख्यालय के कर्मचारियों को अमानत संग्रहण, ऋण वसूली व उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। अमानत संग्रहण में राऊ शाखा के श्री ओमप्रकाश श्रोत्रिय को प्रथम एवं गाँधीनगर शाखा के श्री प्रवीण जैन को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार ऋण वितरण में राऊ शाखा को प्रथम एवं गौतमपुरा शाखा के श्री परमानंद यादव को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। ऋण वसूली में सिंहासा समिति के श्री सुरेन्द्र सिसोदिया को प्रथम, आगरा संस्था के श्री खुमानसिंह यादव को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। शत-प्रतिशत ऋण वसूली में राऊ संस्था के श्री प्रदीप नागर को प्रथम तथा अमानत संग्रहण हेतु रंगवासा संस्था के श्री रमेश पाण्डे को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। सहायक लेखापाल मुख्यालय श्री दिलीप सोनी को वर्ष में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिना अवकाश लिए क्लियरिंग का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यालय के लिपिक श्री प्रवीण शर्मा को गेहूँ उपार्जन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। संचालन संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर के निज सचिव श्री आर.के. देवकर द्वारा किया गया।

गाँधीनगर शाखा प्रबंधक श्री प्रवीण जैन को अतिथियों ने पुरस्कृत किया

गौतमपुरा शाखा के शाखा प्रबंधक श्री परमानंद यादव पुरस्कार ग्रहण करते हुए

सिंहासा समिति के प्रबंधक श्री सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया पुरस्कार ग्रहण करते हुए

सहकारी संस्था आगरा के प्रबंधक श्री खुमानसिंह यादव पुरस्कार प्राप्त करते हुए

सेवा सहकारी संस्था राऊ के प्रबंधक श्री प्रदीप नागर पुरस्कार प्राप्त करते हुए

रंगवासा संस्था के प्रबंधक श्री रमेश पाण्डे पुरस्कार ग्रहण करते हुए

सहायक लेखापाल मुख्यालय श्री दिलीप सोनी को पुरस्कृत करते अतिथिगण

मुख्यालय के लिपिक श्री प्रवीण शर्मा को गेहूँ उपार्जन के लिए पुरस्कृत किया

उज्जैन बैंक ने 47.08 लाख का लाभ अर्जित किया

उज्जैन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. उज्जैन की 102वीं वार्षिक आमसभा बैंक के प्रधान कार्यालय भरतपुरी बैंक प्रशासक श्री बी.एल. मकवाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रथम सत्र में वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम, वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित लेन-देन पत्रक, लाभ-हानि पत्रक तथा वर्ष 2021-22 का अनुमानित बजट का वाचन बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विशेष श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि बैंक की कुल अंशपूँजी 88 करोड़ 38 लाख, अमानतें 502 करोड़ 76 लाख है तथा ऋण व्यवसाय 1198 करोड़ 85 लाख का हुआ है जो अपने आप में उल्लेखनीय है।

श्री बी.एल. मकवाना ने कहा कि बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन की किसान हितकारी योजनाओं जैसे समर्थन मूल्य पर खरीदी, आत्मनिर्भर भारत, केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाकर समाज कल्याण का कार्य किया है। सभा में पूर्व बैंक अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल तथा बैंक प्रतिनिधि श्रीराम सांखला ने भी सुझाव दिये जिस पर श्री मकवाना ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संभागीय शाखा प्रबंधक डॉ. रवि ठक्कर, उपायुक्त सहकारिता श्री ओ.पी. गुप्ता सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रशासक एवं बैंक प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे। बैंक के जनसंपर्क अधिकारी श्री विमलेश डोसी एवं श्री सोनगरा ने यह जानकारी दी।

रतलाम सहकारी बैंक की साधारण सभा सम्पन्न

रतलाम। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. की 71वीं साधारण सभा बैंक प्रशासक श्री पी.एन. गोडरिया की अध्यक्षता में बैंक के प्रधान कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें बैंक महाप्रबंधक श्री आलोक जैन द्वारा बैंक का वार्षिक लेखा-जोखा तथा वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। श्री जैन ने बताया कि इस वर्ष बैंक द्वारा 218.28 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। बैंक की वर्तमान अंशपूंजी 4371.19 लाख एवं अमानतें 47451.91 लाख तथा बैंक की कार्यशील पूंजी 78477.53 लाख है। इस वर्ष बैंक की वसूली 76.81 प्रतिशत रही है। चालू वित्तीय वर्ष में बैंक वसूली का लक्ष्य 80 प्रतिशत रखा गया है। इस वर्ष भी सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। बैंक प्रदेश के चुनिन्दा सहकारी बैंकों में होकर निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। आगामी वर्ष में बैंक द्वारा शाखाओं में एटीएम लगाए जाना प्रस्तावित है। बैकं द्वारा संबंद्ध पैक्स संस्थाओं में कृषकों हेतु खाद का पर्याप्त भण्डारण किया है। सभा को बैंक प्रतिनिधि श्री नन्दकिशोर शर्मा, श्री कीर्तिशरणसिंह, श्री सूर्यनारायण उपाध्याय, श्रीमती उषा भार्गव, श्री के.सी. मोदी ने भी संबोधित किया।

केसीसी से किसानों को मिलेगी बड़ी मदद : डॉ. चौधरी

साँची (रायसेन)। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिले के सांची में किसानों को क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। जिले में सहकारी समितियों द्वारा 1818 किसानों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनकी स्वीकृत लिमिट 314.42 लाख रूपए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश के 63 हजार से अधिक किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। इससे उन्हें खेती एवं खेती संबंधी व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों का विकास करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये क्रेडिट कार्ड और शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये सहकारी बैंकों को आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हितग्राहियों को केसीसी वितरण के साथ ही सहकारी बैंकों/समितियों को ४00 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई है।

जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक श्री एन.यू. सिद्दीकी ने बताया कि रायसेन, गैरतगंज, साँची, देवनगर के किसानों और हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव, जनपद पंचायत साँची के अध्यक्ष एस. मुनियन, प्रदीप दीक्षित, राकेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश किरार, रतनलाल जायसवाल, वकील विमल कुमार जैन, कमल किशोर पटेल, साँची जनपद सीईओ भगवानसिंह, कुँवर सिंह दांगी, नवलसिंह मेहरा आदि उपस्थित थे।

फसल बीमा राशि किसानों के लिये ऑक्सीजन : उषा ठाकुर

खरगोन। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने खरगोन में आयोजित जिला-स्तरीय फसल बीमा के सिंगल क्लिक से भुगतान कार्यक्रम में किसानों को बीमा क्लेम राशि के प्रमाण-पत्र वितरित किये। सुश्री ठाकुर ने कहा कि खरीफ-2019 के अति-वृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये यह राशि ऑक्सीजन की भाँति काम करेगी।

सुश्री ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम में खरगोन जिले के एक लाख 43 हजार 327 किसानों के खातों में 118 करोड़ 22 लाख रुपये ट्रांसफर किये गये हैं। सांकेतिक रूप से भीलगांव के राजेन्द्र कालूराम के खाते में 3 लाख 35 हजार 740 रुपये, उटावद के मंजीत सिंह एक लाख 58 हजार 37 रुपये, अक्षय सुखलाल 36 हजार 500 रुपये, दुलीचंद 10 हजार 400 रुपये तथा जुबेदा मुनीर खान के खाते में 8 हजार 624 रुपये ट्रांसफर किये गये।

मंत्री सुश्री ठाकुर ने भीकनगांव के ग्राम कोठड़ा पहुँचकर आदिवासी जन-नायक टंट्या भील के परिजनों से भेंट की। उन्होंने परिजनों से कहा कि आप लोग महान टंट्या मामा के वंशज हैं, उनके जीवन-दर्शन को समझें। अपने बच्चों को शिक्षित करें और नशामुक्ति का पाठ पढ़ायें। सुश्री ठाकुर ने टंट्या मामा के मंदिर में उनकी पूजा-अर्चना भी की।

किसान मंजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने 17 हेक्टेयर में फसल का बीमा कराया था। कुल 16 हजार 560 रुपये बीमा राशि का भुगतान किया था। ऐसी आपदा में आज मुझे एक लाख 58 हजार रुपये का क्लेम मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ी राहत है। किसान राजेन्द्र पाटीदार ने 39 हजार रुपये की बीमा राशि भरकर 14 हेक्टेयर में केला, अदरक और मिर्च की फसल का बीमा कराया था। आज उन्हें क्लेम के 3 लाख 35 हजार रुपये मिले।

पूर्व कृषि राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व विधायक श्री बाबूलाल महाजन और कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी. सहित जन-प्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन की वार्षिक साधारण सभा संपन्न

खरगोन बैंक मप्र-छग में प्रथम पंक्ति में पहुँचा : श्री जैन

खरगोन। जिला सहकारी बैंक खरगोन ने वर्ष 2019-20 में उल्लेखनीय प्रगति की है। मप्र एवं छत्तीसगढ में प्रथम पंक्ति में बैंक की उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। इसी तारतम्य में बैंक के ऋण व्यवसाय में आशातीत वृद्धि होकर बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। सभी के सराहनीय सहयोग एवं मार्गदर्शन के कारण यह बैंक आज आत्मनिर्भर होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन की वर्ष 2019-20 की वार्षिक साधारण सभा की बैठक मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में संपन्न हुई। प्रशासकीय उद्बोधन में बैंक के प्रशासक एवं उप आयुक्त सहकारिता जिला खरगोन मुकेश जैन ने सभा में अवगत कराया कि वर्ष 2021-22 का 298 करोड 25 लाख रु. का बजट पारित किया गया। 15 करोड 27 लाख के मुनाफे का लक्ष्य रखते हुए 2812 करोड़ रु. का ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक की आर्थिक सक्षमता के संबंध में और अधिक स्पष्ट करते हुए आपने कहा कि बैंक की अंशपूँजी में गत वर्ष की तुलना में 0.34 करोड की वृद्धि हुई है। अमानतों में रू. 108.37 करोड एवं कार्यशील पूँजी में रू. 320.85 करोड की वृद्धि दर्ज की है।

बैठक में बैंक के प्रबंध संचालक ए.के. जैन ने बताया कि बैंक की खरगोन एवं बडवानी जिले में सभी शाखाएं कोर बैकिंग अंतर्गत संचालित हो रही है। ग्राहकों एवं अमानतदारों को डायरेट सबसिडी एनईएफटी आरटीजीएस एसएमएस अलर्ट इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु एटीएम मोबाईल वेन बैंक द्वारा नाबार्ड के सहयोग से प्राप्त कर संचालित की जा रही है जो लगातार भ्रमण करती है।

बैंक द्वारा अपनी सदस्य संस्थाओं को उनकी अंशपूँजी पर लाभांश 1 प्रतिशत के मान से रु. 2 करोड 49 लाख का प्रावधान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त हो जाने पर संस्थाओं को राशि प्रदाय की जावेगी। बैंक को भारतीय रिर्जव बैंक से मोबाईल सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। बैंक शीघ्र अपने ग्राहकों एवं अमानतदारों को मोबाईल बैंकिंग सेवाएं देगी।

बैठक में बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश रत्नपारखी, पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम पटेल सहित बैंक प्रतिनिधि, राजेन्द्र भावसार, परसराम चौहान, रमेश पटेल, दिलीप जोशी, सतेन्द्रसिंह चौहान, शांतिलाल पाटीदार, चतरसिंह सोलंकी, चन्द्रशेखर यादव, मोहन जायसवाल, भारत यादव, संजय पटेल मौजूद थे। बैठक में संस्थाओं से आए प्रतिनिधि राजेन्द्र यादव, सत्येन्द्रसिंह चौहान, राजेन्द्र परसाई आदि ने किसानों एवं पेक्स संस्थाओं के हित में सुझाव दिए।

झाबुआ बैंक की 100वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न

जगदीश कन्नौज

डी.आर. सरोठिया

झाबुआ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ की 100वीं वार्षिक साधारण सभा नवीन जिला पंचायत भवन में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं बैंक प्रशासक श्री जगदीश कन्नौज ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक ने 40588.10 लाख रु. की अमानतें संग्रहीत की हैं। बैंक ने अल्पावधि ऋण 17325.20 लाख रु. जिले के किसानों को वितरित किया है। बैंक की कार्यशील पूँजी गत वर्ष 94194.48 लाख थी जो घटकर 711171.66 लाख तक पहुँच गई। बैंक द्वारा इस वर्ष 34.08 लाख रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.आर. सरोठिया ने कहा कि बैंक अपनी 20 शाखाओं और 72 लैम्प्स समितियों तथा 372 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जिले के किसान भाइयों को सेवा दे रही है। बैंक से संबद्ध सहकारी समितियों द्वारा 149333 किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा हेतु शाखा झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट, पेटलावद, थांदला एवं उमराली में लॉकर्स सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर संभागीय शाखा प्रबंधक श्री गणेश यादव, प्रभारी उपायुक्त सहकारिता श्री डी.सी. भिड़े सहित बैंक के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

जिला सहकारी बैंक सीहोर की वार्षिक आमसभा संपन्न

सीहोर बैंक 533.91 लाख के लाभ में

सीहोर। जिला सहकारी बैंक सीहोर ने आलोच्य वर्ष में 533.91 लाख रु. का लाभ अर्जित किया है तथा बैंक का संचित लाभ 855.49 लाख रु. है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीहोर की 38वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए बैंक की अध्यक्ष श्रीमती उषा सक्सेना ने कहा कि वर्तमान में बैंक की अंशपूँजी 11081.12 लाख रु. है तथा बैंक की निधियाँ 11583.22 लाख रु. है। बैंक की कार्यशील पूँजी 143494.92 लाख रु. हैं एवं अमानतें 43898.02 लाख रु. है। इस वर्ष भी बैंक का सीआरएआर 14.05 प्रश है। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष बैंक द्वारा समितियों को वर्ष 2011 से 2015 तक 1395.19 लाख रु. का लाभांश वितरण किया गया है। बैंक का इस वर्ष का एनपीए 20.72 प्रश है जो विगत वर्ष की तुलना में 6.07 प्रश कम है एवं बैंक की वसूली दिनांक 31.8.2020 पर 76.05 प्रश है जो गत वर्ष से 23.85 प्रश अधिक है। कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

उषा सक्सेना

होशंगाबाद बैंक की साधारण सभा संपन्न

होशंगाबाद। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद की 110वीं वार्षिक साधारण आमसभा श्री बृजेश शरण शुक्ल, बैंक प्रशासक महोदय एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता नर्मदापुरम संभाग की अध्यक्षता में बैंक के सभागार में संपन्न हुई। आमसभा में श्री बी.एस. परते, उपायुक्त सहकारिता, श्री अखिलेश चौहान सहायक आयुक्त सहकारिता हरदा एवं बैंक सदस्य सहकारी समितियों के बैंक प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक एवं समिति प्रबंधक उपस्थित हुए। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के. दुबे द्वारा वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन का जारी एजेंडा से विषयवार वाचन किया गया। बैंक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन के सभी विषयों का सर्वसम्मति से आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया। आमसभा में पधारे सभी प्रतिनिधियों का आभार श्री शुक्ल ने व्यक्त किया। आमसभा में कोविड-19 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के विशेष रूप से पालन किया गया।

बी.एस. शुक्ला

आर.के. दुबे

जिला सहकारी बैंक खंडवा की 109वीं साधारण सभा संपन्न

खंडवा। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. खंडवा की 109वीं वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता बैंक के प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर संभाग श्री जगदीश कन्नौज द्वारा की गई। श्री कन्नोज द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि 31 मार्च 2020 पर बैंक की अमानतें 755.43 करोड़ रु. रही। बैंक द्वारा म.प्र. शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि कार्य हेतु 861.83 करोड़ रु. का ऋण वितरण किया गया। बैंक की कार्यशील पूँजी 1595.03 करोड़ रु. हो गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.के. हरसोला द्वारा बैंक के प्रगति प्रतिवेदन का वाचन किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई तथा वर्ष 2021-22 के लिए 128.22 करोड़ का आय-व्यय बजट एवं 1162.15 करोड़ का ऋण वितरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसे आमसभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर खंडवा जिले के उपायुक्त सहकारिता श्री के. पाटनकर, नाबार्ड अधिकारी श्री रवि मोरे, जिला अग्रणी प्रबंधक श्री बी.के. सिन्हा, दुग्ध संघ के प्रबंधक श्री कराहे उपस्थित रहे। इनके साथ ही जनप्रतिनिधियों में श्री अरुणसिंह मुन्ना, पूर्व मार्केटिंग अध्यक्ष श्री माणिकराव आव्हाड़, इफको प्रतिनिधि, श्री सुरेश मिश्रा अध्यक्ष मरईमाता थोक उपभोक्ता भंडार उपस्थित रहे।

लिंबी संस्था की वार्षिक सभा संपन्न

पाटी। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. लिंबी की वार्षिक आमसभा पंचायत भवन बमनाली में संपन्न हुई। इसमें संस्था के समस्त अंशधारी सदस्य शामिल हुए। संस्था प्रशासक श्री मुवेल की अध्यक्षता में हुई आमसभा में किसानों को जुवार, मक्का, बाजरा पसलों के पंजीयन, शासकीय योजनाओं, संस्था से शून्य प्रतिशत पर ऋण, खाद-बीज के बारे में जानकारी दी गई। जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है उन्हें कर्ज को समय पर अदा करने के लाभ भी बताए गए। सहकारी संस्था के 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष में अंकित लेख विवरण ऑडिट, बैलेंस शीट, लाभ-हानि पत्रक प्रतिवेदन का अवलोकन कराया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक श्री गोविंद पाटीदार, संस्था प्रमुख फईम खान, संतोष राठौड़, लखन यादव सहित किसान मौजूद रहे।

राजगढ़ में 3.50 करोड़ के केसीसी बाँटे गए

राजगढ़। पी.एम. किसान निधि पशुपालक एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को के.सी.सी. वितरण एवं कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के उदेश्य से प्रदेश एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजगढ़ महल में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जिसका शुभारंभ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने मां सरस्वती का पूजन एवं द्वीप प्रज्जवलित कर किया। इस दौरान उपस्थित हितग्राहियों को के.सी.सी. कार्ड एवं मछुआ समितियों को ऋण वितरित किए गए।

कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक श्री नीरज कुमार सिंह ने किसान एवं सहकारी समितियों के सदस्यों से कहा कि आप सब किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर कृषि उत्पादन दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ाए उन्होने किसानों को इस पैसे से उन्नत तकनीक और खाद बीज प्राप्त कर आमदनी बढ़ाने की सलाह दी। कार्यक्रम के तहत जिले में 14 शाखाओं के माध्यम से 140 संस्थाओं द्वारा पी.एम. किसान निधि वाले कृषक, सामान्य कृषक, पशुपालक तथा मत्स्य पालन करने वाले 450 हितग्राहियों को 03 करोड़ 50 लाख रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए कार्यक्रम के दौरान राजमहल में कलेक्टर द्वारा 09 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिनकी राशि 05 लाख 04 हजार रूपये है। इसी प्रकार पशुपालन 10 कृषकों को 01 लाख 70 हजार रूपये के के.सी.सी. जारी किए गए। कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम में मत्स्य सहकारी संस्था के 106 हितग्राहियों को 07 लाख 21 हजार रूपये का के.सी.सी. जारी किया गया। कार्यक्रम में 13 लाख 96 हजार रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम में वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री अमर सिंह यादव, श्री दीपेश सिंह चौहान, श्री मनोज सिंह हाडा, श्री शैलेन्द्र गुप्ता, श्री प्रवीण मिश्रा, श्री शफीक गामा, महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक श्री चौहान, अन्य अधिकारीगण व कृषकगण मौजूद रहे।

देवास जिले में किसानों को केसीसी वितरित

देवास। प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम मल्हार स्मृति मंदिर देवास में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का उद्बोधन वर्चुअल माध्यम किसानों ने देखा और सुना। इस दौरान कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला, श्री नन्द किशोर पाटीदार, श्री महेन्द्र सिंह मकवाना, श्री रमेशचन्द्र जायसवाल तथा श्री भारत सिंह, श्री यशवंत सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा अधिकारियों में श्री अविनाश तिवारी, उपायुक्त सहकारिता श्री मनोज गुप्ता, बैंक के महाप्रबंधक डॉ. के.एन. त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण तथा किसान उपस्थित थे।

सुश्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। कोरोना संकट के काल में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार खेती के साथ-साथ स्वसहायता समूह को पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलने से किसानों को साहुकारों को अधिक ब्याज देने से छुटकारा मिलेगा।

देवास जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत 35 हजार 290 किसानों को 21 करोड़ सम्मान निधि तथा अल्पावधि ऋण साख सीमा 141 करोड़ रूपये प्रदान किये गये। देवास जिले में गेहूं उपार्जन में 57 हजार 37 किसानों से 754 करोड़ का 4 लाख 11 हजार मट्रीक टन गेहूं तथा 16 हजार किसानों से 217 करोड़ का 44 हजार मेट्रिक टन चना खरीदी गया, जिसका शत प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

जिले में गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत जिले की समस्त 124 प्राथमिक साख संस्थाओं, जिला सहकारी बैंक की 20 शाखाओं, उचित मूल्य की 326 दुकानों पर प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड वितरीत किये गये।

मंदसौर में हितग्राहियों को प्रदान किये केसीसी

मंदसौर। प्रदेश के साथ जिले में भी जिला स्तरीय सबको साख सबका विकास कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालकों की समृद्धि के लिए अभिनव पहल की जा रही है। इसके साथ ही पशुपालकों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जा रहे है। इस कार्यक्रम अवसर पर नंदकिशोर शर्मा, बिहारीलाल, लक्ष्मीनारायण, बाबूलाल आदि को ऋण पत्र भी कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका मुकेश गिरी गोस्वामी, गरोठ विधायक श्री देवी लाल धाकड़, नगर पालिका मन्दसौर के अध्यक्ष श्री राम कोटवानी, कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, सीईओ जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्ता, श्री बंशीलाल गुर्जर, श्री मदनलाल राठौर, श्री शिवराज सिंह राणा, श्री भारत सिंह चौहान, श्री पी एल यादव, श्री नानालाल अटोलिया, सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सचिव, जिला अधिकारी, कर्मचारी, किसान एवं पत्रकार मौजूद थे।

इस अवसर पर विधायक श्री देवी लाल धाकड़ द्वारा कहा गया कि सरकार की इस तरह की अभिनव पहल से देश शक्तिशाली एवं समृद्ध शाली बन रहा है। सरकार सबको साख सबका विकास हो, इस पर कार्य कर रही है। हम सभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खुद खड़ा हो, इसके लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। मन्दसौर की सहकारिता बैंक का नाम जिले के साथ-साथ प्रदेश में भी गौरव से लिया जाता है। यह बैंक लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। आज के दिन पूरे प्रदेश में 63 हजार किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। किसानों को अपने उत्पादन का उचित दाम मिले इसके लिए भी सरकार ने पहल की है। बिना किसी बाधा के व्यापार हो इसके लिए एपीएमसी का मॉडल एक्ट भी लाया गया।

किसानों को बीमा राशि दिलवाने के पूरे प्रयास करेंगे

शाजापुर। प्रदेश के किसानों पर फसल खराब होने से बड़ा संकट आया है। प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है। नुकसानी का आंकलन कराया जाकर सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। किसानों को आरबीसी 6(4) के सहायता दी जाएगी। साथ ही गत वर्ष की बीमा राशि भी पात्र किसानों को दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। यह बात प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) तथा सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने जिले के अकोदिया मण्डी में गरीब कल्याण सप्ताह के अन्तर्गत 'सबकों साख-सबका विकास' को लेकर आयोजित हुए कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के लिए क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण समारोंह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहीं।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन, श्री अम्बाराम कराड़ा, श्री दौलत सिंह मण्डलोई, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री नवीन शिन्दे, श्री किशोर सिंह पाटीदार, श्री नरेन्द्र यादव, श्री शिवप्रताप मण्डलोई, श्री जीपी परमार, श्री खामसिंह यादव, श्री प्रभु राजपुत, श्री हेमन्त परमार, श्री रामचरण परमार, श्री जीवन सिंह आर्य,श्री रामचन्द्र वर्मा, उपायुक्त सहकारिता श्रीमती सुनीता गोठवाल, सीसीबी सीईओ श्री केके रायकवार, उपसंचालक कृषि श्री आरपीएस नायक, पशुचिकित्सा डॉ एके बरेठिया भी मौजूद थे।

जिले में खरीफ फसलों के लिए 323 करोड़ 35 लाख रूपए का क्रेडिट ऋण वितरण किया गया।खरीफ 2019 में फसल ऋण के रूप में जिले में 249 करोड़ 88 लाख रूपए का वितरण हुआ। इस प्रकार गत वर्ष से अब तक 73 करोड़ 47 लाख रूपए की वितरण वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र 548 किसानों के लिए 2 करोड़ रूपए की साख सीमा जारी की गई है। इसी तरह जिले के 328 किसानों को 70 लाख रूपए का फसल ऋण, दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित पशुपालकों तथा अन्य पशुपालकों एवं मत्स्य सहकारी समितियो को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। संचालन प्रबंधक सीसीबी श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने किया।

धार में 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम संपन्न

धार। पीएम किसान सम्मान निधि, पशुपालक एवं मत्स्य पालक हितग्राहियों को केसीसी के वितरण एवं कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहाकारी बैंको/सहकारी समितियों को शासकीय सहायता प्रदाय कार्यक्रम 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला सहाकारी केद्रीय बैंक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया गया। जिसे उपस्थित जनसमुदाय ने देखा और सुना।

मुख्य अतिथि मालती मोहन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुखिया है जो हमेशा किसानों की चिन्ता कर उनके परेशानी को समझते है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जमीन से जुडे व्यक्ति है जो हमेश जनता के लिए एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते है। उन्होने फसल बीमा, पात्रता पर्ची, शून्य प्रतिशत दर पर ब्याज उपलब्ध कराकर जनता की समस्याओं का निराकरण किया है। वे हमेशा किसानों के सुख दुख में उनके साथ रहकर उनका निराकरण करते है।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि एक सप्ताह से शासन द्वारा जरूरतमंद लोगो को लाभांवित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवास, पट्टों, फसल बीमा, स्व सहायता समूह को ऋण के कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभांवित किया है। कार्यक्रम में बताया गया कि जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभांवित 1703 कृषकों को केसीसी में 336.19 लाख की साख सीमा स्वीकृति की गई है। स्वीकृत साख सीमा में से 1703 कृषको को 208.10 लाख का फसल ऋण वितरित किया गया है। दुग्ध सहकारी समितियों से सम्बद्ध 189 पशुपालकों को कार्यशील पूंजी हेतु 89.19 लाख का ऋण वितरित किया गया। मत्स्य सहकारी समितियों के 274 सदस्यों को मछली पालन हेतु कार्यशील पूंजी हेतु 8 लाख का ऋण वितरित किया गया। दुग्ध सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य 7 पशुपालको को 42 लाख का ऋण वितरित किया गया है। इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता श्रीमती भारती शेखावत सहित बैंक के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित ते।

111 कृषकों को 45 लाख केसीसी के माध्यम से ऋण वितरण

दमोह। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सप्ताह के आयोजन के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दमोह में सबको साख सबका विकास कार्यक्रम के तहत प्रतीक स्वरूप 10 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत जिले में पशु पालक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की साख सीमा जारी की गई, जिसमें कुल 111 कृषकों को 45.40 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण वितरण किया गया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सम्मान निधि 185 कृषकों को 173.56 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साख सीमा देकर ऋण वितरण किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री तरूण राठी ने कहा गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों को ऋण स्वीकृति वितरण का कार्य किया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री एस.के. कनौजिया ने कहा गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत 'सबको साख सबका विकास' इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसी तरह के कार्यक्रम जिले की सभी शाखाओं, समितियों एवं ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। साथ ही मुख्यालय पर जिस तरह ऋण वितरण किया गया, उसी तरह जिले की सभी शाखाओ में भी वितरण किया गया है, जिला सहकारी बैंक खरीफ फसल में लगभग 134 करोड़ ऋण वितरण कर चुका है।

बड़वानी में किसानों को क्रेडिट कार्डों का वितरण

बड़वानी। प्रदेश के पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने कलेक्टरेट में आयोजित गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कृषको, पशु पालको एवं मत्स्य पालको को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, जिला सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक श्री अनूप जैन, प्रबधक श्री अजयपालसिंह तोमर, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संजय वर्मा, शाखा प्रबंधक श्री खेमचन्द्र सोलंकी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र भावसार के साथ लाभान्वित भी उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थितों को सम्बोधित करते हुये श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब कृषक बन्धु सहजता से शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्राप्त कर उन्नत खेती कर अपना एवं क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। उन्होने बताया कि कृषको को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 सौ करोड़ रूपये की राशि सहकारी बैंको, समितियों को उपलब्ध करवाई है। कार्यक्रम के दौरान जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक संचालक श्री अनूप जैन ने बताया कि खरीफ 2020 के दौरान जिले के 49529 कृषको को 307 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार जिले के 11652 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में उज्जैन के प्रणत जैन ने बाजी मारी

प्रणत जैन

उज्जैन। लफ्ज : द इंडियन स्पीकर्स फोरम द्वारा आयोजित स्पीक इंडिया नामक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में उज्जैन जिले के निवासी प्रणत जैन ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का विषय 'राजनीति की शव परीक्षा' था। प्रतियोगिता में देश-विदेश से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रणत जैन ने हाल ही में एम.टेक. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे से पूर्ण किया। है।

सभी वर्गों को आत्म-निर्भर बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य : सुश्री सिंह

विदिशा। आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को आत्म-निर्भर बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। किसानों को सशक्त बनाने के लिये उन्हें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह विदिशा में 'सबको साख-सबका विकास' के जिला-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे। विदिशा जिले में 7 हजार 31 किसानों को 63 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि साख के रूप में मंजूर की गई है। इसके साथ ही किसानों को करीब 36 करोड़ रुपये फसल ऋण के रूप में वितरित किये गये। कार्यक्रम में दुग्ध सहकारी समितियों के 1033 पशुपालकों को करीब 2 करोड़ रुपये के किसान क्रेडिट-कार्ड वितरित किये गये। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता श्री के.के. द्विवेदी, वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री विनयप्रकाश सिंह भी मौजूद थे।

शिवपुरी में 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम आयोजित

शिवपुरी। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत मंगलवार को ''सबको साख सबका विकास'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके तहत जिले के 164 किसानों को 95 लाख 76 हजार रूपये के किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ एवं प्रभारी कलेक्टर श्री एच.पी.वर्मा द्वारा कृषक हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी पर्यटन संघ भोपाल के अध्यक्ष श्री अरविंद तोमर, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की महाप्रबंधक श्रीमती लता कृष्णन, सहकारिता के उपायुक्त श्री सुरेश सांवले, ऑडिट ऑफिसर श्री सी.एल.मौर्य, जिला मत्स्य अधिकारी श्री रेकवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सहकारिता विभाग के जिला पंजीयक ने बताया कि जिले में खरीफ सीजन में भी किसानों को ऋण वितरित किए गए है। प्रदेश में सहकारिता को मजबूत बनाया जा रहा है।

भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक में 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम

किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम खिलावन पटेल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के हितों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके लिये राज्य सरकार ने किसान हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये है। श्री पटेल भोपाल सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक की न्यू मार्केट स्थित बैंक शाखा में 'सबको साख सबका विकास' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री पटेल ने कहा कि अब किसान को एक लाख रूपये का कृषि ऋण लेने पर मात्र 90 हजार रूपये ही लौटाने होते है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को खेती के अलावा उससे जुड़ी गतिविधियों जैसे उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की और प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपायुक्त सहकारिता श्री विनोद कुमार सिंह ने बताया कि भोपाल जिले में सहकारिता के क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के माध्यम से नवीन 1039 किसानों को 8 करोड़ 70 लाख रूपये की साख सीमा स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 38 हजार 452 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चके है। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि 'सबको साख सबका विकास' कार्यक्रम का राज्य स्तरीय प्रसारण जिले की 7 कृषि शाखा, 34 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, 75 उचित मूल्य की दुकानों पर भी किया गया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री आर.पी. हजारी, शाखा प्रबंधक, कर्मचारीगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

जावरा में व्यापारियों ने अपनी माँगों का ज्ञापन दिया

जावरा। केन्द्र सरकार द्वारा लागू अध्यादेश से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में उत्पन्न समस्याओं के निदान को लेकर व्यापारियों ने ज्ञापन दिया। कृषि उपज मंडी व्यापारी संगठन ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार वंदना हरित को ज्ञापन देते हुए कहा कि 5 जून को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश से प्रदेश की मंडियों का कारोबार प्रभावित होने लगा है। मंडी के बाहर फीस एवं निराश्रित शुल्क, मंडी लायसेंस समाप्ति आदि की समाप्ति, मंडी प्रांगण में लागू रखे जाने से व्यापार पड़तल संतुलन बैठाना संभव नहीं रह गया है। दिन-प्रतिदिन मंडी के व्यापार में गिरावट होने से मंडियों के उजड़ने की स्थिति बनेगी। व्यापारियों ने मंडी व्यापार सुचारू रूप से संचालित किये जाने को लेकर मंडी फीस दर 50 पैसे करने, निराश्रित शुल्क समाप्त करने, मंडी लायसेंस फीस न्यूनतम रख आजीवन करने, कृषक व मंडी फीस भुगतान सरल व्यवस्था लागू करने के साथ अनुज्ञा पत्र व्यवस्था समाप्त करने, मंडी दुकान/गोदाम पंजीयन शुल्क कलेक्टर रेट से कर दिया है जो अनुचित है। व्यापारियों ने कहा है कि माँगें नहीं मानी गई तो व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस अवसर पर सर्वश्री अशोक कोठारी, पवन पाटनी, धीरज सारडा, कांतिलाल दलाल, संदीप हरण, शैलू गोखरू, अश्निव शर्मा, नितेश भंडारी, दिलीप रावत, अनोखीलाल बोरदिया, नरेन्द्र कोलन, अभिषेक गोखरू, वीरेन्द्र संचेती, अनिल चत्तर, रुद्रप्रताप गोखरू, शशांक गर्ग, अक्षय गर्ग, विनोद दख, नीरज जैन, मत पोरवाल, मुकेश पोरवाल आदि उपस्थित थे। डॉ. काटजू मंडी व्यापारी संघ ने भी 6 सूत्री माँगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मंडी के भारसाधक अधिकारी राहुल नामदेव धोटे को ज्ञापन सौंपा है।

दि उज्जैन बैंक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की वार्षिक साधारण सभा

उज्जैन। दि उज्जैन बैंक क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित की 38वीं वार्षिक साधारण सभा रुचिश्री गार्डन उज्जैन में कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एस.एल.दाहिमा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई। इस अवसर पर 28 सदस्यों को परिवार कल्याण निधि से 10 हजार के चैक वितरित किये गये। संस्था ने वर्ष 2019-2020 मे 2.29 लाख का लाभ अर्जित किया है। इस कार्यक्रम में मनोज शर्मा, प्रशांत सोहेल, कुलदीप सिंह, सीटू के राम त्यागी, यू.एस.छाबड़ा, कोमलचंद जैन, रविन्द्र जेठवा, महेन्द्र जाटवा, वीरेन्द्र परमार, अशोक ज्ञानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रबंधक विमलेश दोषी ने किया।

आईपीसी कर्मचारी संस्था की सभा

इंदौर। इन्दौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी साख संस्था मर्यादित की 46वीं वार्षिक साधारण सभा सिन्धु भवन क्रांती कृपलानी नगर इन्दौर मे आयोजित की गई। संस्था ने वर्ष 2019-2020 में 816927.75 का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जिसमें अपने सदस्यों को 3% से लाभांश वितरित करने जा रही है। सभी सदस्यो ने संस्था मे सुधार हेतु सुझाव, प्रश्न किये जिसका संस्था अध्यक्ष अनिल बावनिया ने संतोषजनक जबाब दिये। सभा के बाद संस्था के सदस्यों के बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये गये। बैंक के यूथ क्लब के अध्यक्ष मनीष शर्मा और सचिव वीरेन्द्र पथरिया ने भी इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित किया और मेडल प्रदान किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन के कोषाध्यक्ष रमाकांत यादव एवं उपकोषाध्यक्ष योगेन्द्र महावर और संस्था के वर्तमान और सेवानिवृत्त सदस्य उपस्थित रहे।

सहकारिता विभाग में तबादले

भोपाल। राज्य शासन द्वारा उपायुक्त, सहायक आयुक्त, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रशासकीय आधार पर आगामी आदेश तक पदस्थ करने के आदेश दिये हैं।

बबलू सातनकर

मदन गजभिये

परमानंद गोडरिया

सुनील सिंह

मनोज गुप्ता

महेन्द्र दीक्षित

नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
श्रीमती सुनीता गोठवाल	उपायुक्त शाजापुर	उपायुक्त सतना
श्री मनोज गुप्ता	उपायुक्त देवास	उपायुक्त शाजापुर
श्री महेन्द्र दीक्षित	मुख्याय भोपाल	उपायुक्त देवास
श्री आर.एस. गौर	उपायुक्त सिवनी	उपायुक्त भिण्ड
श्री मदन गजभिये	उपायुक्त इंदौर	उपायुक्त खरगोन
श्री बबलू सातनकर	उपायुक्त गुना	उपायुक्त इंदौर
श्री एस.के. सिंह	उपायुक्त मंदसौर	उपायुक्त रतलाम
श्री परमानंद गोडरिया	उपायुक्त रतलाम	उपायुक्त धार
श्रीमती भारती शेखावत	उपायुक्त धार	उपायुक्त बुरहानपुर
श्री मुकेश जैन	उपायुक्त खरगोन	उपायुक्त गुना
सुश्री वर्षा श्रीवास	सहा. आयुक्त देवास	सहा.आयुक्त अं.इंदौर
श्री सुरेश सांवले	सहा.आयुक्त ग्वालियर	सहा.आयुक्त इंदौर
श्री अखिलेश चौहान	सहायक आयुक्त हरदा	उपायुक्त भोपाल
सुश्री दीपाली खंडेलवाल	सहा.आयुक्त इंदौर	उपायुक्त टीकमगढ़

निसरपुर समिति की आमसभा संपन्न

निसरपुर। आ.जा. सेवा सहकारी समिति निसरपुर की साधारण सभा में संस्था प्रशासक सर्वपालसिंह चौहान, शाखा प्रबंधक प्रवीण बर्वे एवं पूर्व वरिष्ठ संचालक भूरालाल लछेटा, परसराम पाटीदार मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रबंधक दशरथ पाटीदार द्वारा संस्था का वर्ष 2019-20 का वार्षिक आय-व्यय, लाभ-हानि पत्रक का वाचन किया गया। संस्था के कृषकों द्वारा ग्राम निसरपुर डूब क्षेत्र में आने से संस्था कार्यालय को पुनर्वास स्थल पर शासन द्वारा निर्मित भवन को रिपेयरिंग कर नवीन स्थान पर शिफ्ट करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

आगर-मालवा में 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम

प्रदेश सरकार किसान हितैषी है : डॉ. मोहन यादव

आगर-मालवा। प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड व शून्य प्रतिशत ब्याज योजनांतर्गत फसल ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों एवं समितियों को 800 करोड़ की शासकीय सहायता उपलब्ध कराई है। जिसका सीधा लाभ कृषकों एवं पशुपालकों को मिलेगा। कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। अब पशुपालकों को भी क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितेषी हैं।

कार्यक्रम में कलेक्टर अवधेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर, पूर्व विधायक लालजीराम मालवीय, बंटी ऊंटवाल, कैलाश कुम्भकार, कैलाश कक्का, करण सिंह यादव, उदयसिंह यादव, अजय जैन, मंयक राजपूत, भेरूं सिंह चौहान महेश शर्मा, संजय जैन, पारस जैन, सतीश सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा प्रभारी उपायुक्त सहकारिता वैशाली जैन, उप संचालक पशुपालन डॉ. एसव्ही कोसरवाल, उपसंचालक कृषि श्री आर.पी. कनरिया, आत्मा परियोजना के आरके तिवारी, दुग्ध शीत केन्द्र उज्जैन के प्रबंधक, बैंक के प्रबंधक के.के. नागर, प्रभारी शाखा प्रबंधक शेषनारायण शर्मा सहित सहकारिता बैंक के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मध्यप्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता रामचन्द्र शर्मा द्वारा किया गया तथा उपस्थितजनों का आभार प्रदर्शन नोडल अधिकारी श्री सुरेश शर्मा द्वारा किया गया।

कृषि विज्ञान केन्द्र उज्जैन में पोषण माह मनाया गया

उज्जैन। भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, रा.वि.रा.सिं. कृ.वि.वि. उज्जैन द्वारा तीन दिवसीय वेबीनार गूगलमीट के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । जिसमें पहले दिन विकासखण्ड उज्जैन, घट्टिया, दूसरे दिन तराना एवं महीदपुर तथा तीसरे दिन बडनगर एवं खॉचरोद की कुल 347 ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ऑनलाईन प्रशिक्षण से लाभांवित हुई। संस्था प्रमुख डॉ. आर.पी.शर्मा के मार्गदर्शन में तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी श्री गौतम अधिकारी के समन्वय से इस तीन दिवसीय सफल वेबीनार में मुख्यतः पॉच महत्वपूर्ण बिन्दुओं- शिशु के प्रारंभिक 1000 दिवस का महत्व, रक्ताल्पता तथा डायरिया से बचाव एवं पोषक तत्व का महत्व, वैयक्तिक साफ-सफाई का महत्व इन विषयों पर पॉवर पॉईट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गयी। संस्था की गृह वैज्ञानिक डॉ. रेखा तिवारी ने एनिमिया (रक्ताल्पता) के लक्षण जैसे की चक्कर आना, नाखून एवं जीभ का सफेद होना साथ ही महिलाओं की उम्र के विभिन्न पड़ाव जैसे नवजात शिशु अवस्था, किशोर अवस्था गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोष्टिक आहार एवं योगञ्चव्यायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ्य रहने के उपाय बताये।

संस्था की वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. मौनी सिंह (गृह विज्ञान) द्वारा बच्चों के प्रथम 1000 दिन व स्वास्थ्य देखभाल विषय पर ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं को विस्तृत प्रशिक्षण दिया। ऑनलाईन प्रशिक्षण में तकनीकी से संबंधित समस्त सहयोग श्रीमती गजाला खान वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी का तकनीकी द्वारा दिया गया एवं कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के वैज्ञानिक डॉ. डी.एस.तोमर, डॉ. एस.के. कौशिक, श्री हंसराज जाटव, श्री राजेन्द्र गवली तथा श्री अजय गुप्ता एवं श्रीमती सपना सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

बालाघाट में किसानों को ऋण वितरण कार्यक्रम

बालाघाट। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की इस समस्या को समझा और किसानों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को 18 प्रतिशत से कम करते करते शून्य प्रतिशत पर ला दिया है। अब किसानों को बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है और किसानों की आय को दोगुना करना है। यह बातें मध्यप्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष (स्वतंत्र प्रभार) एवं जल संसाधन विभाग श्री रामकिशोर 'नानो' कावरे, ने गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान श्रीमती रेखा बिसेन, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए, श्री राजकुमार रायजादा, श्री चित्रसेन पारधी, श्री अनिल धुवारे, श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. के. शुक्ला एवं प्रशासक श्री आलोक दुबे, उप संचालक कृषि श्री सी आर गौर, उप संचालक मत्स्योद्योग श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे, अन्य अधिकारी एवं ऋण प्राप्त करने वाले किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में दिये गये संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। जिला पंचायत प्रधान श्रीमती रेखा बिसेन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. के. शुक्ला ने कार्यक्रम में बताया कि उनके बैंक के अंतर्गत 126 सोसायटी के माध्यम से खरीफ सीजन 2020 में जिले के 73 हजार 650 किसानों को 219 करोड़ रुपये का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिया गया है। अब मत्स्य पालन एवं पशु पालन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ऋण की वसूली के मामले में 73 प्रतिशत वसूली के साथ जबलपुर संभाग में प्रथम स्थान पर है।

सागर में 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम

सागर। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत 'सबको साख सबका विकास' के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक सागर के सभागार में सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। जिला सहकारी बैंक सागर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए है। उन्होंने प्राथमिक साख सहकारी समिति केरवना के दो किसान श्री अमर सिंह और श्री रामसिंह को क्रेडिट कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक श्री सुरेश मोटवानी, जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक श्री एके असाटी और सहकारी समितियों से जुड़े कृषक व कर्मचारी उपस्थित थे।

आ.जा. सेवा सहकारी समिति आशापुर की आमसभा संपन्न

महेश्वर। आ.जा. सेवा सहकारी संस्था मर्या. आशापुर में सहकारिता विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम सबको साख सबका विकास के तहत संस्था की वार्षिक आमसभा का आयोजन भी किया गया। संस्था प्रबंधक श्री तिलोक यादव ने बताया कि संस्था के वार्षिक लेखा-जोखा व वार्षिक बजट इस मौके पर पारित किया गया। साथ ही 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम की सबको जानकारी दी गई। सभी कृषकों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में बताते हुए सभी कृषकों को लाभ दिलाने हेतु संस्था में आकर पंजीयन कराने के लिए भी कहा गया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने मध्यप्रदेश तीर्थस्थान एवं मेला प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री माखन सिंह चौहान को हार्दिक शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में मध्यप्रदेश के सभी पवित्र तीर्थस्थलों का विकास होगा और धार्मिक मेलों के आयोजन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

म.प्र. सहकारिता कर्मचारी महासंघ ने भामसं को समस्याओं से अवगत कराया

भोपाल। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव कृष्ण प्रताप सिंह और विधायक देवीलाल से म.प्र. सहकारिता कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सजेन्द्रसिंह खींची की अगुवाई में मुलाकात की। इस मौके पर सहकारिता कर्मचारियों की माँगों और समस्याओं से अवगत कराया गया। भामसं महासचिव ने सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह के संज्ञान में लाकर समस्याओं का निराकरण करवाने का भरोसा दिलाया।

तराना मंडी में कर्मचारियों-व्यापारियों द्वारा हड़ताल

तराना। मंडी बोर्ड कर्मचारियों का संचालनालय कृषि विपणन में संविलियन किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अमान्य कर दिये जाने के विरोध में तराना कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारियों और व्यापारियों ने हड़ताल कर दी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद प्रस्ताव खारिज कर देने के विरोध में प्रदेश की 259 मंडियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी इकाई तराना के मीडिया प्रभारी महेश व्यास ने बताया कि माँगें पूरी नहीं होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी ने ग्राम मोर्चाखेड़ी में ब्यावरा विधायक स्व. श्री गोवर्धन दांगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की व शोकाकुल परिवार को सांत्वना व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक श्री हुकुम सिंह कराड़ा, श्री प्रियव्रत सिंह, श्री जयवर्धन सिंह, श्री बापूसिंह तंवर, श्री रामलाल मालवीय, श्री महेश परमार सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विपणन संस्था गुना की आमसभा संपन्न

गुना। विपणन सहकारी संस्था मर्या. गुना की वार्षिक आमसभा संस्था कार्यालय पर आयोजित की गई। संस्था प्रबंधक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यों का ब्योरा पेश किया गया एवं आगामी वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना का वाचन किया गया। संचालकों ने आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत संस्था की प्रोसेसिंग यूनिट खोलने बाबद प्रारूप पेश किया जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रदान की। आगामी वर्ष के अंकेक्षण हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया। सभी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों का प्रबंधक ने आभार व्यक्त किया।

हाटपीपल्या समिति की साधारण सभा

हाटपीपल्या। उन्नत कृषि सहकारी संस्था समिति हाटपीपल्या की वार्षिक साधारण सभा देवास बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष रमेशचंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संस्था सचिव भरत जोशी ने बजट का वाचन किया। प्रबंधक मणिशंकर नागर, प्रशासक समीर हरदास, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवास, पूर्व अध्यक्ष विजेन्द्र पटेल, भरत सेंधव, संजय पाटीदार सहित अनेक कृषक इस मौके पर उपस्थित थे।

छतरपुर बैंक ने 39.63 लाख रु. का लाभ अर्जित किया

छतरपुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर की 59वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एल. रायकवार ने बताया कि बैंक ने इस वर्ष कोरोना काल के बावजूद पिछले वर्षों के मुकाबले शानदार उपलधियां अर्जित की हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बैंक ने 39.63 लाख रुपए लाभ अर्जित किया है जिससे बैंक का संचित लाभ 930.23 लाख हो गया है। श्री रैकवार ने बताया कि पहली बार छतरपुर जिले में 47100 किसानों से 3 लाख 97 हजार 9776.42 मीट्रिक टन गेंहू खरीदा गया जो कि गत वर्ष से 87 हजार 92 मीट्रिक टन अधिक है। नगद ऋण बाँटने के मामले में भी गत खरीफ वर्ष 2019 में 64.65 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 100 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। वसूली भी पिछले वर्ष जहां 26 प्रतिशत थी वह इस वर्ष बढ़कर 60 प्रतिशत तक हो चुकी है। के.एल. रायकवार ने इस सफलता का श्रेय बैंक के प्रबंधन और अधिकारी कर्मचारियों को दिया है। बैठक की अध्यक्षता करूणेन्द्र प्रताप सिंह ने की और उन्होंने भी बैंक के सभी साथियों को बधाई दी।

बैठक में बैंक के उपाध्यक्ष जयकृष्ण चौबे सहित संचालक मण्डल के सभी सदस्य, समितियों के जनप्रतिनिधि, उपायुक्त अशोक कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन के.बी. ताम्रकार शाखा प्रबंधक द्वारा किया गया। रामविशाल पटैरिया ने बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला एवं शाखा प्रबंधक सुश्री प्रभा वैद्य ने सभी का आभार जताया।

व्यावसायिक एवं औद्योगिक बैंक मुरैना की साधारण सभा

मुरैना। व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक 45 वर्षों से निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की राशि में 935.70 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं बैंक का एनपीए 27.63 फीसदी रह गया है। बैंक की यह उपलब्धि सभी खाताधारकों, कर्मचारियों, अधिकारियों तथा संचालक मंडल के सकारात्मक प्रयासों से मिल सकी है। बैंक की 45वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन मुरैना में किया गया। जिसमें सभी संचालक तथा खाताधारक सदस्य शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता केशवलाल अग्रवाल ने की। सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अर्जुनसिंह परिहार द्वारा दिया गया। बैंक अध्यक्ष केशवलाल ने बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन उपस्थित जन को अवगत कराते हुए बताया कि बैंक की रक्षित एवं अन्य निधियों में 232.68 लाख से अधिक की वृद्धि हो गई है।

मेघनगर शाखा में पशुपालकों को केसीसी वितरित

मेघनगर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा मेघनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर नए केसीसी ऋण का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तोलाराम मुनिया सहकारिता विस्तार अधिकारी, श्री गौड़ पशु चिकित्सा शाखा प्रबंधक मन्नू सिंह खतेड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित किया और विस्तारपूर्वक योजनाओं की जानकारी दी। 10 कृषकों को केसीसी पशुपालन क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पशुपालकों ने शासन की इस योजना के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन शाखा पर्यवेक्षक संजय नागर ने किया।

नीमच में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन

नीमच। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत जिले की सभी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं, जिला सहकारी बैंक की शाखाओं, उचित मूल्य की दुकानों पर प्रधानमंत्री किसान योजनांतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों, मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराए गए। कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर श्री जितेन्द्रसिंह राजे की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला सहकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.पी. नागदा ने विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। सहायक आयुक्त सहकारिता श्री पुष्पेन्द्र कुशवाह ने आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में विस्तार से बताया। कलेक्टर श्री राजे ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सहकारिता बैंक को पर्याप्त फंड प्रदान किया गया है। उन्होंने किसानों से सहकारी बैंकों से संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत योजना की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर जावद विधायक प्रतिनिधि श्री महेन्द्र भटनागर, नीमच विधायक प्रतिनिधि श्री नीलेश पाटीदार, मनासा विधायक प्रतिनिधि श्री अजय तिवारी भी उपस्थित थे।

काँटाफोड़ शाखा में केसीसी वितरण

काँटाफोड़। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक देवास की शाखा काँटाफोड़ और संस्था काँटाफोड़ द्वारा संयुक्त रूप से किसान सम्मान निधि नवीन केसीसी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन केसीसी वितरण का आयोजन किया गया। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष महेश दुबे, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल इस अवसर पर उपस्थित थे। जिला सहकारी बैंक देवास के प्रबंधक सुखलाल मौर्य, संस्था सचिव यशवंतसिंह पंवार, सत्यनारायण तिवारी, राजेश मीणा, ज्ञानेन्द्र जोशी, रमजान शेख, मोतीलाल गेहलोत सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

झकनावदा शाखा में प्रमाण-पत्र वितरित

पेटलावद। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था झकनावदा में प्रधानमंत्री किसान कल्याणनिधि योजना के हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मुख्य अतिथि श्री प्रदीपसिंह तारखेड़ी ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले यही हमारा लक्ष्य है। 800 करोड़ रु. की राशि किसानों को पशु लोन एवं दुग्ध डेयरी लोन के लिए दी गई है। झकनावदा और बोलासा संस्था के 134 हितग्राहियों को पशु एवं दुग्ध डेयरी ऋण उपलब्ध कराया गया। संस्था पर्यवेक्षक दिनेश खतेड़िया, सुरेन्द्रसिंह पंवार, रविकुमार राठौड़ सहित संस्था के कर्मचारी और किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक हरिराम पडियार ने किया और भरतसिंह राठौर ने आभार व्यक्त किया।

सारंगपुर शाखा में केसीसी वितरण

सारंगपुर। 'सबको साख-सबका विकास' योजना एवं गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजगढ़ की शाखा सारंगपुर में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, विशेष अतिथि वरिष्ठ एडवोकेट पर्वतसिंह मंडलोई एवं अध्यक्षता भाजपा जिला उपाध्यक्ष निर्मल जैन ने की। भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव प्रसारण देखा गया। संस्था तलेनी और सारंगपुर के 12 नवीन किसानों को अतिथियों ने किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन पं. कैलाश शर्मा ने किया एवं आभार आर.के. पांडे ने माना। इस अवसर पर संस्था प्रबंधक सज्जनसिंह पुष्पद, देवीलाल पुष्पद, सुपरवाइजर के.पी. शर्मा, सूरत सिंह सोलंकी सहित समिति कर्मचारी उपस्थित थे।

कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दें : रविन्द्र चौबे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने नवा रायपुर स्थित शिवनाथ भवन में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मंडी बोर्ड एवं बीज विकास निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर सभी विभागों के काम-काज की गहन समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में खेती-किसानी और इससे संबंधित गतिविधियों के विस्तार को लेकर अपेक्षाएं बढ़ी हैं। लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में और अधिक बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कृषि एवं संबंधित विभागो के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाने की दिशा में और अधिक संजीदगी से काम करने की बात कही। खरीफ सीजन में खाद-बीज की बेहतर व्यवस्था के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि रबी में भी इसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में संसदीय सचिव सुश्री शंकुतला साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री हिमशिखर गुप्ता, संचालक कृषि श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, जलग्रहण मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जगदीश सोनकर, संचालक उद्यानिकी श्री माथेश्वरन व्ही. सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के कृषिमंत्री ने ली विभागीय बैठक

बैठक में राज्य में खरीफ फसलों की वर्तमान स्थिति, धान के उत्पादन, धान खरीदी की व्यवस्था, समितियों में चबूतरा एवं शेड निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी एवं जैविक खाद के उत्पादन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु की विविधता एवं फसलोत्पादन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने सुराजी योजना के तहत बाड़ी विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने तथा राज्य में जलवायु के अनुसार उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी रबी सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में कृषि संचालक श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि रबी की विभिन्न फसलों के लिए मांग के आधार पर प्रमाणित बीज का भण्डारण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक लाख 14 हजार 385 क्विंटल गेंहू बीज तथा 16 हजार 200 क्विंटल मक्का बीज की मांग को देखते हुए समितियों में इनका भण्डारण कराया जा रहा है। अक्टूबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत बीज भण्डारण का लक्ष्य है। बैठक में जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के काम-काज की भी समीक्षा की गई।

धान खरीदी पूर्व बारदानों की व्यवस्था

रायपुर। उत्तरप्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए आवश्यक बारदानों की व्यवस्था करने की कार्यवाही शुरू हो गई है । इसके लिए विभिन्न जिलों में मिलरों की बैठक ली जा रही है। गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राईस मिलर्स की बैठक ली गई। जिसमें वर्तमान खरीफ फसल में धान खरीदी के लिए आवश्यक बारदाना की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली गई। सभी राईस मिलरों से उनके द्वारा लिए गए बारदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र देने कहा गया है । साथ ही अच्छे और खराब हुए बारदानों की संख्या की जानकारी भी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक भी जुड़े थे।

कृषि विवि रायगढ़ केन्द्र सम्मानित

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के मसाला अनुसंधान केन्द्र को वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केन्द्र के रूप में सम्मानित किया गया है। रायगढ़ केन्द्र को यह सम्मान हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसाला फसलों की नई किस्मों के विकास, फसल सुधार, अनुसंधान एवं विस्तार हेतु दिया गया है। यह केन्द्र प्रदेश के आदिवासी किसानों के उत्थान हेतु उनके खेतों में मसाला फसलों की विभिन्न किस्मों के प्रदर्शन भी आयोजित कर रह है। केन्द्र को यह सम्मान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 'मसाला' की 31वीं वार्षिक कार्यशाला के अवसर पर प्रदान किया गया।

उत्तरप्रदेश में 1 अक्टूबर से धान खरीदी प्रारंभ

योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम/ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धान खरीद 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगी। धान क्रय की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने, किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए क्रय संस्थाओं को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

उप्र राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) द्वारा धान क्रय हेतु 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कैश क्रेडिट लिमिट/अल्पकालिक ऋण उन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया जाएगा, जिनकी ब्याज दर न्यूनतम हो। उक्त कार्यशील पूँजी के रूप में कैश क्रेडिट लिमिट/अल्पकालिक ऋण लिये जाने हेतु एसएफसी को अधिकृत किया जाएगा। एसएफसी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा को उनकी आवश्यकतानुसार अल्पकालिक ऋण/अग्रिम दिया जाएगा। सम्बन्धित ऋण लिए जाने तथा ऋण की वापसी की शर्तें आदि निर्धारित करते हुए उप्र राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एसएफसी) द्वारा ऋण की वापसी सुनिश्चित करायी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं यथा-उप्र को-आपरेटिव फेडरेशन लि (पीसीएफ) एवं उप्र को-आपरेटिव यूनियन लि (पीसीयू) के द्वारा धान क्रय हेतु कार्यशील पूंजी की व्यवस्था अपने वित्तीय स्रोतों से की जाएगी। उस पर आने वाले भारित ब्याज की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त ब्याज प्रतिपूर्ति को समायोजित करते हुए राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से एसएफसी द्वारा लिये जाने वाले ऋण की राज्य सरकार द्वारा शासकीय गारण्टी स्वीकृत की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को ऋण की अदायगी होने तक ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त ब्याज की धनराशि को उपरोक्त ऋण पर देय ब्याज में से समायोजित करते हुए ब्याज की शेष धनराशि निगम को उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति है। चूंकि विचाराधीन ऋण का प्रयोग उप्र राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिये नहीं किया जाना है, अतः शासकीय गारण्टी पर गारण्टी शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा।

जिला सहकारी बैंक झाँसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू

झाँसी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाँसी के अधिकारियों व प्रतिनिधियों को अब सहकारिता मंत्री या उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के लिए लखनऊ तक की दौड़ नहीं लगानी होगी। शासन ने बैंक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान कर दी। बैंक के अध्यक्ष श्री जयदेव पुरोहित ने कहा कि पहले किसी भी काम के लिए लखनऊ तक जाना पड़ता था जिससे समय और पैसा दोनों व्यय होता था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों को सुविधा मिलेगी। सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की 50 बैंकों के अध्यक्षों और अधिकारियों से वार्ता की। बैंक अध्यक्ष श्री पुरोहित ने ई-स्टेम्प की बिक्री सहकारी बैंक के माध्यम से कराए जाने की बात कही जिस पर मंत्रीजी ने विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में उपायुक्त सहकारिता श्री के.पी. शुक्ला, बैंक महाप्रबंधक श्री नंदकिशोर सहित अनेक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

पं. रामनारायण शास्त्री का देवलोकगमन

बांसी (झाँसी)। पंडित रामनारायण शास्त्री का विगत दिनों देवलोकगमन हो गया। श्री शास्त्री इंटर कालेज बांसी से सेवानिवृत्त अध्यापक थे। कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में वे परम पूज्यनीय रहे हैं। बांसी के मनतालाब स्थित श्री हनुमान जी महाराज के वह परम भक्त थे। हनुमान जी महाराज की उन्हें सिद्धि मानी जाती थी जिससे वह भूत-प्रेत की बाधाओं को दूर करने एवं आमजन के कष्टों का निवारण करने के लिए दूर- दूर तक प्रसिद्ध थे। बांसी सहित जनपद में बड़ी तादाद में उनके शिष्य हैं। उनका अंतिम संस्कार बाँसी मुक्तिधाम पर किया गया। हरियाली के रास्ते परिवार शास्त्रीजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

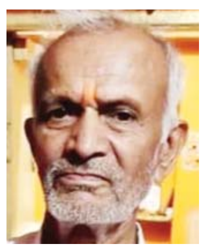

पं. रामनारायण शास्त्री

● आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक'
अध्यक्ष : म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद
376, म.गाँ. मार्ग (बड़े गणपति के पास), इंदौर
फोन : 0731-2414181, मो. 9755014181

मेष

आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी। संतान पक्ष के कार्यों में सहयोग देना होगा। विद्यार्थी वर्ग अनुकूल स्थिति पाएंगे। नौकरीपेशा भी अनुकूल स्थिति पाएंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। रुके कार्य स्वप्रयत्नों से पूरे होंगे।

वृषभ

मानसिक प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। उत्साहजनक समाचार मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक हेगी। नौकरीपेशा भी अनुकूल स्थिति पाएंगे।

मिथुन

भाग्यबल द्वारा आपके कार्य बनेंगे। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति अनुकूल रहेगी। नौकरीपेशा अनुकूल स्थिति पाएंगे। संतान के कार्यों में खर्च होगा। परिवार में शुभ कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी।

कर्क

अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलने से कार्य कुशलतापूर्वक बनेंगे। धन-कुटुम्ब के मामलों में सहयोग के साथ उत्तम स्थिति रहेगी। आर्थिक मामलों में स्वप्रयत्नों द्वारा लाभान्वित होंगे। सोचे कार्यों में थोड़ी बाधा रहेगी।

सिंह

प्रभाव में वृद्धि होगी, वहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। व्यापार-व्यवसाय में संतोषजनक स्थिति रहेगी। जमीनी कार्य से लाभार्जन कर सकते हैं।

कन्या

ईष्ट मित्रों व भाइयों का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कार्य में अनुकूल स्थिति रहेगी। नौकरीपेशा के लिए समय मिला-जुला रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग लेकर चलें। स्वास्थ्य अधिकतम ठीक रहेगा।

तुला

दांपत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। संतान पक्ष में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग में अनुकूल स्थिति रहेगी। आर्थिक प्रयासों में अनुकूल सफलता पाएंगे। नौकरीपेशा के लिए समझदारी से चलना होगा।

वृश्चिक

इच्छित कार्य में सफल होंगे, मानसिक सुख-शांति रहेगी। पारिवारिक सहयोग के साथ खर्च होगा। मातृपक्ष से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सुखद स्थिति पाएंगे। अधिकारी वर्ग भी सुखद स्थिति पाएंगे।

धनु

पारिवारिक सहयोग के साथ खर्च होगा। भाग्य में अनुकूल स्थिति होने से प्रगतिपूर्ण वातावरण रहेगा। पिता का किसी कार्य में सहयोग लाभकारी रहेगा। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

बाहरी व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक वार्तालाप करें व यात्रा में भी सावधानी रखना होगी। स्थानीय मामलों में सफलता के साथ प्रसन्नता रहेगी। स्त्री पक्ष के मामलों में सावधानी रखना होगी।

कुम्भ

भाग्य में अनुकूलता होने से कार्य में प्रगति आएगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नौकरीपेशा अपने कार्य में प्रगति के साथ लाभान्वित होंगे। पिता का किसी कार्य में सहयोग लाभकारी रहेगा। शत्रुपक्ष पर प्रभाव बना रहेगा।

मीन

भाग्य में अनुकूल स्थिति होने से प्रगतिपूर्ण वातावरण रहेगा। पारिवारिक सुख-शांति रहेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग अनुकूल स्थिति पाएंगे। नौकरीपेशा के लिए सहयोगवादी समय रहेगा।

आ गया 'मिर्जापुर-2' जबरदस्त ट्रेलर

वेब सीरिज मिर्जापुर-2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पिछले दिनों इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें मुन्ना, गुड्डू और कालीन भैय्या छाए रहे। ट्रेलर से साफ है कि कालीन भैया अपना पूरा राजकाज मुन्ना को सौंपने जा रहे हैं। ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया, अली फजल यानी गुड्डू पंडित और दिव्येंदु शर्मा यानी मुन्ना भैया की जरदस्त एक्टिंग नजर आ रही है। साथ ही गोलू भी है। बता दें, मिर्जापुर-2 की स्ट्रीमिंग 23 अक्टूबर से अमेजन प्राइम पर शुरू होगी। इस सीजन में 3 नए चेहरों को वेबसीरीज में इंट्री मिली है। ये हैं विजय वर्मा, प्रियांशु पुल्ली और ईशा तलवार। मिर्जापुर-2 का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। फैन्स तरह-तरह के मीम्स बनाकर अपनी रिएक्शन्स दे रहे हैं। ट्रेलर से साफ है कि मुन्ना अब मिर्जापुर का किंग बनना चाहता है और सभी नियमों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। कालीन भैय्या करते हैं कि मिर्जापुर की इस राजगद्दी पर कोई भी बैठे, नियम से चलना होगा। वहीं मुन्ना अपना नया नियम बनाता है कि इस कुर्सी पर जो भी

बैठेगा, अपने हिसाब से नियम बदल सकता है। दूसरी तरफ गुड्डू और गोली हैं। दोनों बदले की आग में जल रहे हैं। गुड्डू गोलू को तैयार करता है। बदले की आग में गुड्डू ऐसा हो गया है कि वह दुश्मन को मौत के घाट उतारने में जरा भी नहीं सोचता है। ट्रेलर देखने के बाद फैन्स में रोमांच और बढ़ गया है। उनके मन में सवाल बरकरार है कि क्या मुन्ना की मौत हो जाएगी? क्या गुड्डू अपना बदला पूरा कर पाएगा?

एसपीबी को सलमान की आवाज समझा जाता था

दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 वर्षीय बालासुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जब सलमान ख़ान नए-नए फिल्मों में आए थे तो कई सालों तक एसपी बालासुब्रण्यम को सलमान खान की आवाज समझा जाता था। 'मैंने प्यार किया' के गाने हों या 'साजन' या फिर 'हम आपके हैं कौन', इन सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही आवाज दी थी। ये बात भी अगर पुरानी लग रही हो तो कुछ साल पहले आई 'चेन्नई एक्सप्रेस' का टाइटल गाना एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही गाया था। 80 के दशक से लेकर नई सदी की शुरुआत तक एसपी बालासुब्रमण्यम हिंदी फिल्मों में गाते रहे। तेलुगु में आई सागर संगमम, स्वाति मुथ्यम और रुद्रवीणा जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी गायकी को और निखारा और शास्त्रीय शैली में प्रयोग भी किया। 60 के दशक से गाते आ रहे एसपी बालासुब्रमण्यम 74 साल की उम्र तक सक्रिय बने रहे। एसपी बालासुब्रमण्यम के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने एक दिन में 21 कन्नड़ गाने गाकर रिकॉर्ड बनाया था। और ये भी दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा गाना गाने का गिनीज रिकॉर्ड (करीब 40000) भी उनके नाम हैं। लेकिन खुद एसपी बालासुब्रमण्यम ने 2016 में कहा था कि अब तो वो खुद भी गिनती भूल चुके हैं।

कीमती फसलों के रक्षक, तेज असरकारक एवं विश्वसनीय

तरल, घुलनशील एवं भुरकाव हेतु उपयोगी
55 कीटनाशकों की विशाल श्रृंखला

बायो क्रान्ति में शानदार धमाका

बायो करे कमाल
किसान बने खुशहाल

तरल – बायो पौषक, अमिनोटॉप, ह्युमिटॉप, स्कारपियो, रिसर्च-30,
तरल एवं ग्रेन्यूल – बायो टेक झाईम, बायो पंचरत्न, बायो बूम-एन

शिपॉन केमिकल्स प्रा. लि.
रजिस्टर्ड ऑफिस : गोयल मार्केट, 38, वेयर हाउस रोड, इन्दौर-452 007
फोन : 0731-2475465, मो. : 98270-25084, 98930-25084
ब्रांच ऑफिस : 12-ए, रजनीगंधा सोसायटी, मुम्बई
अन्य ब्रांचेस : बेल्लारी, रायपुर

बायो पेस्ट केमिकल्स
कॉर्पोरेट ऑफिस : अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई
रजिस्टर्ड ऑफिस : गोयल मार्केट, 38, वेयर हाउस रोड, इन्दौर-452 007
फोन : 0731-2475465, मो. : 98270-25084, 98930-25084

sonie ads

डीलरशीप हेतु सम्पर्क करें

बायोस्टेड इंडिया लि. के उत्कृष्ट उत्पाद

BIOSTADT
बायोज़ाइम®

जीव विज्ञान पर आधारित
पौधों के लिए सम्पूर्ण विकास वर्धक,
अधिकतम पैदावार एवं बेहतर
क्वालिटी के लिए

वितरक :
पटवारी एग्रो एजेन्सीज

17, विशाल टॉवर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, नवलखा, इंदौर (म.प्र.)
फोन : (ऑ.) 2403694, 2400412,
(बिजलपुर) 2321668, 2321918, (नि.) 2321723

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक बृजेश त्रिपाठी द्वारा वी.एम. ग्राफिक्स, के-29, एलआयजी कॉलोनी, इंदौर से मुद्रित एवं 306-ए ब्लॉक, शहनाई-II, रेसीडेन्सी कनाड़िया रोड, इन्दौर से प्रकाशित (फोन : 0731-2595563, 9752558186, 8989179472, संपादक : बृजेश त्रिपाठी, प्रकाशन दिनांक : 17